SHRI NATHU RAM MIRDHA (Nagaur): We don't agree. What is the hurry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): Sir, this is a very simple Bill. For three days we have been sitting here. There is no hurry, but I shall have some other work in some other House. That is my difficulty.

SHRI NATHU RAM MIRDHA: We can take this up tomorrow or day after tomorrow. What is the hurry?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Agreed. Mr. Daga is supposed to have concluded his speech. The Minister will reply the next day.

SHRI MOOL CHAND DAGA: No, I have not concluded my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will reply the next day. Discussion on this is over.

SHRI MOOL CHAND DAGA: No, I will be speaking on the Bill. I have not concluded my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: How long will you take?

SHRI MOOL CHAND DAGA: I will take seven or eight minutes tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right five minutes have been granted. Tomorrow you can continue.

16.03 hrs

DISCUSSION ON FLOOD AND DROUGHT SITUATION IN VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now discussion under Rule 193. Shri Harikesh Bahadur will raise a discussion on the statements made by the Minister of Irrigation and Minister of Agriculture and Rural Development in the House on 4th October, 1982 regarding flood and drought situation in various parts of the country and the steps taken by Government in that behalf.

श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति दोनों एक साथ अब की बार कई राज्यों में आ गई है। यद्यपि सदन में हम लोग प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका की चर्चा करते हैं और हमेशा सरकार को कुछ सुझाव देते हैं और सरकार से कुछ आश्वासन भी पाते हैं, लकिन देखा यह जाता है कि बाढ़ की रोक थाम के लिये और सूखे को समाप्त करने के लिये कोई ऐसा ठोस कदम सरकार के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है जिससे बाढ़ और सूखे की वर्तमान परिस्थिति पर काबू पाया जा सके। नतीजा यह होता है कि हर साल बाढ़ से भयंकर तबाही होती है और तमाम राज्यों में सूखे से भी बहुत बड़ी तबाही होती है।

मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारे देश के जिन राज्यों में सूखे की स्थिति है, वह हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। साथ ही बाढ़ के बारे में वक्तव्य देते हुए दूसरे मन्त्री जी ने कहा था कि बाढ़ की स्थिति उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम में

[श्री हरिकेश बहादुर]

बहुत ही गम्भीर है और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा असर हुआ है। यह जो लिस्ट दी गई है, उससे ऐसा लगता है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां बाड की स्थिति और सूखे की स्थिति है । यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है । बाढ़ से जन-धन की भारी क्षति हुई है । जगह-जगह अनेक मकान गिरे हैं । लोग मरे हैं, जानवर मरे हैं, फसल बर्बाद हुई हैं । बाढ़ के जाने के साथ साथ बीमारियों के फैलने की भी बहुत आशंका पैदा हो गई है । अनेक जगहों पर बीमारियां फैल रही हैं। खास तौर से एन्सीफ्लाइटिस की बीमारी से लोग मर रहे हैं । इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार की बीमारियों से लोगों की जाने जा रही हैं । प्रतिवर्ष प्रलयकारी बाढ़ की विभीषिका हमारे देश के सामने आती है, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं ।

मान्यवर, मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूंगा । वहां पर आज भयकर बाढ की स्थिति है, लेकिन साथ ही सूखे की स्थिति भी वहां पर है । अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात को रोक कर अगने क्षेत्र के बारे में कहूं, गोरखपुर के बारे में कहू तो वहां नदियों के किनारे भयंकर बाढ़ से तबाही मची हुई हैं । जहां नदियां नहीं हैं वहां सूखे की स्थिति है । इस देश को देख कर एहसास होता है हमारे देश के तमाम भागों में इसी प्रकार की स्थिति होगी । हमारे क्षेत्र में एक राप्ती नदी है, जिसके बारे में मैंने मन्त्री जी से चर्चा की थी । यह नदी नेपाल से निकलती है और अगर उस पर बान्ध बनाकर पानी को रोक कर कोई योजना बनाई जाए तो उससे सचाई के साधन किसानों को उपलब्ध होंगे, साथ ही बाढ़ पर नियत्रण हो सकेगा और विद्युत के उत्पादन में भी सहायता मिल सकती है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी । पता नहीं क्या अड़चन है, नेपाल सरकार भारत सरकार के सहाथ सहयोग नही कर रही है या कर रही है । भारत सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है इस के बारे में हम लोगों को साफ जानकारी होनी चाहिए । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि जब वे जवाब देंगे तो इस बारे में भी हम लोगों को बतायेंगे ।

मान्यवर उड़ीसा की स्थिति यह है कि वहां ऐसी बाढ़ आई थी जो पिछले सौ सालों में नहीं आई थी । उत्तर प्रदेश में भी ऐसी बाढ़ नहीं थी । लगभग 616 करोड़ रुपये की मांग वहां के मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार से की है । इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उड़ीसा में किस प्रकार की बाढ आई होगी । जहां तक एक तरफ उड़ीस में बाहु आई है और वहीं दूसरी तरफ सूखे से तबाही हो रही है । यह बड़े शर्म की बात है कि आज हमारे देश में भुखमरी से लोग मर रहे हैं । इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बिहार के बारे में देना चाहता हूं । बिहार में आजकल उल्टे-सीधे काम हो रहें हैं, लेकिन बाढ और सूखे के नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जा रहे हैं । वहां भुखमरी प्रारम्भ हो चुकी है। इसका उदाहरण मैं आपको एक अखबार के जरिए से देना चाहूगा । यह कलकत्ता का अखबार टेलीग्राफ है, जिसने कि अपने फ्रण्ट पेज पर एक चित्र छापा है, सिको माननीय मन्त्री जी और उनके विभाग के अधिकारियों को देखना चाहिए इसमें एक

औरत के पति की मृत्यु हो गई है और वह बहुत ही दुखी हालत में है । मैं इसको कोट करता हूं :—

"Janki Devi of Chatwara Kapur village in Bihar's Vaishali district, whose husband, Aklu Choudhary, died of starvation on September 197. She is seen here with youngsters in her family, all of whom are starving."

There is an item under the head "starvation deaths in Bihar" in the front page, and also another under "Drought leads to death in Bihar", at page four.

इसको कृषि मंत्री जी और उनके विभाग के अधिकारियों को देखना चाहिए । यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है कि आज हमारे देश में लोग भुखमरी से मर रहे हैं । यह स्थिति खास तौर से बिहार के अन्दर हो रही है । वहां पर अनावश्यक काम हो रहे हैं, जैसे प्रैस विधेयक, जनता के मौलिक अधिकारों को समाप्त करना, संसद सदस्यों की पिटाई करना और पत्रकारों की पिटाई करना ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should confine yourself to the drought conditions only. You are travelling somewhere else.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Government is doing that work which should not be done and the work which should be done has never been undertaken by the Bihar Government.

मेरा यह कहना है कि सरकार ऐसे काम कर रही है जिसे कि उसे नहीं करना चाहिए ।

मेरा कहना है कि आज बिहार राज्य में भुखमरी की स्थिति है । लेकिन सरकार वहां पर उपद्रवकारी कार्यों, अन्यायपूर्ण कार्यों और अनुचित कार्यों में लगी हुई है । एक तरफ तो बाढ़ की विभीषिका है और दूसरी तरफ सूखे और बाढ़ से लोग तबाह हो रहे हैं । सूखे की स्थिति का चित्र दिखा कर मैंने आपको स्थिति स्पष्ट की है ।

वैशाली में जहां स्थिति खराब है, वहां संथाल परगना में भी स्थिति बहुत खराब है । संथाल परगना में जो स्थिति हो गयी है उसका जिक्र में कुछ शब्दों में करना चाहूंगा । (**व्यवधान**) मेरे यहां कोई भूख से नहीं मर रहा है । भुखमरी से लोग बिहार में मर रहे हैं और जो लोग भुखमरी से नहीं मर रहे हैं उन्हें बिहार में गोली से मारा जा रहा है ।

संथाल परगना जिले के पलाजोरी ब्लाक में वहां के आदिवासियों ने एक प्रदर्शन किया था । उनकी मांग यह थी कि वहां पर भुखमरी की स्थिति पैदा हो रही है और लोग भूख से पीड़ित हैं । 1967 के बाद से ऐसा दुर्भिक्ष और अकाल आज तक नहीं पड़ा था । ऐसे भयंकर सूखे के कारण वहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ है । वे लोग चाहते थे कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत वहां कार्य चलाये जाएं जो कि आम तौर पर कहीं भी नहीं चलाये जा रहे हैं । (**व्यवधान**)

मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को पैसा देती है लेकिन राज्य सरकारों द्वारा उस पैसे से जो काम चलाये जाने चाहिए, वे ठीक से नहीं चलाये जा रहे हैं । जब केन्द्रीय सरकार उन कामों के लिए पैसा दे रही है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि वे काम पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ।

मैं अपने राज्य की बात बताता हूं । वहां थोड़ा-बहुत काम हो रहा है लेकिन कहीं बिल्कुल ही नहीं हो रहा है । इस सम्बन्ध में हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मिट्टी

[श्री हरिकश बहादुर]

की पटाई के लिए पैसा नहीं है। अगर मिट्टी पड़ी है तो उस पर हम ईटा डाल सकते हैं। पीछे जनता पार्टी के शासन में 'फूड फार वर्क' प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़के बनाने हेतु मिट्टी की पटाई भी की जाती थी और लोगों को इससे रोजगार भी मिलता था। उस काम को बिल्कुल बन्द कर दिया गया है।

वहां के लोगों की यह भी मांग थी कि वृद्धावस्था पेंशन लोगों को दी जाए। इसके बारे में दो अक्तूबर को कहा गया था कि बूढ़े लोगों को वृद्धावस्था की पेंशन दी जाएगी। वे यह भी चाहते थे कि उनके इलाके को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। वहां पर यह स्थिति बनी हुई है कि 20–25 फीसदी लोगों को एक ही समय भोजन मिल पाता है। यह सारी बातें अखबार में निकली हैं जिनको कि मैं पढ़ कर सुनाऊंगा। आप देखिए, किस प्रकार की स्थिति वहां पर है। सरकार को कोई चिंता नहीं है। इन आदिवासियों ने जब इस बात के लिए आंदोलन किया, वे चाह थे कि उनकी न्यायोचित मांगों को माना जाए तो उन पर गोली बरसाई गई। उसमें 6 आदिवासी मार दिए गए जबकि वे लोग थाने से 600 गज की दूरी पर थे, शांति पूर्ण सभा कर रहे थे, लेकिन कहा गया कि उन्होंने थाने का घेराव किया। और जो लोग मारे गए, उनमें से 5 आदमी ऐसे थे जो बाजार में सामान खरीद रहे थे। श्री गिरधारी मंडल नाम के व्यक्ति का मारा गया जो नमक खरीद रहा था। मैं आज के "स्टैट्समैन" की कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहता हूं —

'The landless agricultural labourers are now looking for other means of livelihood. Mr. Girdhari Mandal, who was killed in Thursday's police firing, was a landless labourer. When the rain failed, he turned into a mason. He was buying salt in the Palojori Bazaar when he was killed. His wife, Parvati, has now lost all hopes. She has yet to receive relief by the Government. Her husband was the only earning member in the family. Parvati Devi, who has a three-year-old son to look after, may migrate to some other place in search of job. She had eaten nothing for the past three days when this correspondent and photographer met her in her mud house in Pindara village.'

यह स्थिति वहां की है और सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं है। आज तक उन लोगों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। बिहार की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार के अधिकारियों ने अभी तक किसी भी प्रकार की सहायता उन लोगों को नहीं दी है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो सरकार जनता की न्यायोचित मांगों को स्वीकार नहीं कर सकती, जब लोग खाना मांगते हैं तो उन पर लाठी और गोली बरसाई जाती है, वह सरकार सूखे की स्थिति का सामना कैसे करेगी, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। वहां के अधिकारी अपना पेट भरने में लगे हुए हैं उनका नैतिक पतन हो चुका है। जब सरकार स्वयं इस प्रकार के काम करती है तो अधिकारियों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली दूर-दूर तक गांवों में काम नहीं कर रही है; सस्ते गल्ले की दुकानों पर न गेहूं है, न चावल है। इस प्रकार की सारी रिपोर्टें अखबारों में आ चुकी है। उसी के आधार पर मैं यह सब बता रहा हूं। इन बातों की पूरी समीक्षा होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। यह बड़ी खतरनाक स्थिति है। इन परिस्थितियों में वहां की सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इस

सरकार को तुरन्त बरखास्त किया जाना चाहिए और जो लोग दोषी हैं, उनको तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए ।

राजस्थान के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पिछले 5 वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है । इस वर्ष वहां पूरे राजस्थान में दुर्भिक्ष है । लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, 33000 गांवों में, लगभग पूरे राजस्थान में दुर्भिक्ष की स्थिति हो रही है और अधिकारियों का कहना है कि अगर अब वर्षा हो भी जाए, तब भी कम से कम 18000 गांवों की स्थिति में तो कोई सुधार होने वाला नहीं है । इस स्थिति के बावजूद वहां पर राहत का कोई काम ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। लूट खसोट चल रही है । सरकार का प्रबंध खोखला है । जिस तेजी से राहत कार्य शुरू किए जाने चाहिएं, उस तेजी से नहीं किए जा रहे हैं । किसानों को ट्यूबवैल चलाने के लिए बिजली नहीं मिल रही है, ताकि वे सिंचाई कर सकें । सूखे से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को कम से कम साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, लेकिन केन्द्र सरकार ने जो अनुदान दिया है वह "ऊंट के मुंह में जीरा" के समान है । बहुत थोड़ी सहायता दी गई है । इसलिए इन बातों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है ।

पश्चिमी बंगाल की स्थिति को आप लें । वहां केन्द्रीय टीम जानी चाहिये । वहां सूखे की स्थिति है । इसकी समीक्षा करने के लिए काफी पहले गई थी लेकिन इधर स्थिति काफी बिगड़ चुकी है और तब से नहीं गई है । लगातार दो वर्ष से पश्चिमी बंगाल में सूखा पड़ रहा है । मेरी राय यह है कि प्रधान मंत्री जी को स्वयं वहां जा कर स्थिति की समीक्षा करनी चाहिये । कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए वह गई हैं । इस वास्ते यहां भी उनको स्वयं जा कर स्थिति की समीक्षा करनी चाहिये । मंत्री महोदय से भी मेरी प्रार्थना है कि वह पश्चिम बंगाल जाएं, कृषि मंत्री जी भी और सिंचाई मंत्री जी भी, दोनों जाएं और प्रधान मंत्री को भी साथ ले जाएं या प्रधान मंत्री जी के साथ वे भी जाएं और वहां की स्थिति की समीक्षा करें । वहां पर पर्याप्त सहायता नहीं दी गई है । वहां अगर जल्दी सहायता नहीं दी गई तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी । वैसी ही पैदा हो जाएगी जैसी बिहार में पैदा हो रही है । पश्चिम बंगाल सरकार इस बात के लिए धन्यवाद की पात्र है कि उसने वहां अभी तक भुखमरी की स्थिति पैदा होने नहीं दी है । लेकिन अगर केन्द्रीय सरकार ने.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you inviting the Prime Minister and the Agriculture Minister on behalf of the Government of West Bengal?

SHRI HARIKESH BAHADUR: On behalf of the people of India, I am inviting them.

वहां पर्याप्त सहायता नहीं दी गई तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । पश्चिमी बंगाल सरकार की मांग है कि उसे दूसरे राज्यों से चावल और गेहूं मंगाने की इजाज़त दी जाय । इस मांग को भी पूरा किया जाना चाहिये । ऐसी इजाज़त कुछ राज्यों को दी गई है । पश्चिमी बंगाल को भी दी जानी चाहिये ।

आप पश्चिमी बंगाल में प्रति मास 3.75 लाख टन खाद्यान्न भेजते हैं । इससे काफी अधिक खाद्यान्न वहां इस वर्ष भेजा जाना चाहिये । अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी ।

प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया था पश्चिमी बंगाल के लोगों को पर्याप्त सहायता दी जाएगी यह कोरा आश्वासन रह गया है । इसको पूरा नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि इसको पूरा किया जाए ।

[श्री हरिकेश बहादर]

ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की जो योजना है इसको व्यापक रूप से पश्चिम बंगाल में भी चलाया जाना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को तेजी के साथ हर ऐसे राज्य में जहां बाढ़ या सूखे की स्थिति है, लागू किया जाए। इससे लोगों को जो आज बेरोजगार हैं, रोजगार मिलेगा। कृषि मजदूर जिन को कोई काम नहीं मिलता है उनको काम मिलेगा और रोजी रोटी कमाने का साधन मिलेगा।

मैं यह भी चाहता हूं कि राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि वे इस कार्यक्रम को तेजी के साथ लागू करें।

बाढ़ की स्थिति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि बाढ़ का पानी अगर ठीक ढंग से नियंत्रित कर लिया जाए तो एक तो बाढ़ों पर नियंत्रण पाने में हमें सहायता मिलेगी, उससे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त होगी जिससे खाद्यान्न का और भी ज्यादा उत्पादन होगा। इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के कार्य में भी हमें काफी सहायता मिलेगी जिससे हमारे देश का औद्योगिकरण होगा और बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलेगी। इसलिए सूखे से बचाव के लिए बाढ़ के पानी पर नियंत्रण स्थापित करके उसे सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के कार्य में लगाया जाए। इससे बाढ़ से बचाव होगा तथा सिंचाई की सुविधा मिलेगी जिससे कृषि उत्पादन भी हमारा बहुत बढ़ेगा। विदेशों से जो अन्न आयात कर रहे हैं यह कार्यक्रम हमारा समाप्त हो जायगा। साथ ही बिजली से औद्योगीकरण होगा जिससे बेरोजगारी दूर होगी। इसके सम्बन्ध में गारलेंड कैनाल योजना या उससे अच्छी यदि कोई योजना हो तो उसे कार्यान्वित करना चाहिये। और केन्द्रीय समिति को प्रत्येक राज्य में भेजा जाना चाहिये जो बाढ़ और सूखे से हुई क्षति का जायजा ले और कृषि तथा सिंचाई मंत्री को जाना चाहिये दौरे पर साथ ही प्रधान मंत्री को भी जाना चाहिये।

बाढ़ से जिनके मकान गिरे हैं राज्य सरकारों को अगर पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाय तो ऐसे तमाम लोगों को राज्य सरकारें पैसा दे सकेंगी। मेरी मांग है कि जिनके मकान गिरे हैं उन्हें मकान बनाने के लिये तुरन्त आर्थिक सहायता दी जाय, बिना ब्याज के ऋण दिया जाय ताकि वह अपने मकान बना सकें। बाढ़ से नष्ट हुई फसल का मुआवजा किसानों को देने पर विचार करना चाहिये इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिये इसके बारे में कई बार चर्चा हुई है, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। मुआवजा देने की योजना पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। साथ ही बीमारियों को रोकथाम के लिये सरकार को उपाय करने चाहिये। आज की स्थिति में यह आवश्यक है कि जो बीमारियां फैल रही हैं उन पर रोक थाम के लिये केन्द्र सरकार डाक्टरों के दल भेजे। किसानों के लिये सस्ते मूल्य पर खाद और बीज उपलब्ध कराये जाने चाहिये। बाढ़ तथा सूखा पीड़ित क्षेत्रों में छात्रों की फ़ीस माफ़ की जानी चाहिये, किसानों का लगान माफ़ होना चाहिये, लोगों को दिया गया कर्ज माफ़ होना चाहिये, कम से कम कर्ज को ब्याज से मुक्त कर देना चाहिये। सभी प्रकार की वसूली बन्द होनी चाहिये राहत कार्य तेज किये जाने चाहिये, और राहत वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये। आजकल जो राहत दी जा रही है राहत बाटने वाले ही अपनी राहत कर रहे हैं। इस स्थित पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिये। सूखा पीड़ित राज्यों को पर्यात बिजली

दी जानी चाहिये ताकि किसान सिंचाई का काम कर सकें। एक जिले में एक तरफ़ बाढ़ आयी है तो दूसरी तरफ़ सूखा है। नहरों में पानी नहीं है। इसलिये नहरों में पानी की उचित व्यवस्था करनी चाहिये। तमाम प्रकार की अनियमितताओं को समाप्त करने के लिये सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिये।

नदियों की तलहटी में जो सिल्ट जमा हो गई है उसको निकालने के बारे में कोई प्रोग्राम पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। साथ ही नदियों के किनारे जो तट बंध बनाये जाते हैं ताकि बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके, आज इन तटबंधों की योजना पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रतिवर्ष तट बंध टूटते हैं, करोड़ों रु० के हर साल बांध बनते हैं नदियों के किनारे और हर साल वह छूटते हैं। लोगों को अब इंजीनियरों की नीयत पर शक होने लगा है, ऐसा लगता है कि वह चाहते हैं कि यह तट बंध हर साल टूटें और हर साल बनें, जैसे हमारे गोरखपुर जिले में हो रहा है। तो इन तट बंधों को बनाने की उपयोगिता धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। कारण यह है कि पहले जब बांध नहीं थे। तो नदियों का पानी दूर दूर तक फैल जाता था। लेकिन अब तट बंध बना कर पानी को थोड़ी दूरी के अन्दर नियंत्रित किया जाता है। उसमें बाढ़ के पानी का वेग इतना होता है कि वह जगह जगह बंध को तोड़ देता है और नदियों में वही मिट्टी बह कर फिर आ जाती है। पता नहीं इंजीनियर सही राय देते हैं कि नहीं। लेकिन अगर सही राय देते है तो कहना चाहिये कि तट बंध बनाने की योजना सही नहीं साबित हुई है, क्योंकि नदी में सिल्ट जमा होती है। इसलिये बंध बनाने में सरकार को नुकसान हो रहा है। इसलिये सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और कोई ठोस कदम इस दिशा में उठाना चाहिये। न तो मैं यह कह रहा हूं कि तुरन्त इसे बन्द कर देना चाहिये और न यह कह रहा हूं कि इसको जारी रखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इसके गुण-दोष के आधार पर इसकी समीक्षा कर के निर्णय किया जाना चाहिये कि तट बन्द बनाने की योजना अच्छी है या नहीं है।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बाढ़ और सूखे की विभीषिका से त्रस्त लोगों को बचाने के लिये कारगर कदम उठायें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members many Members have expressed their desire to speak on this. From the Ruling Party the number is about 26. Therefore, if all of them have got to be accommodated, you have to be self-disciplined and you should not take more than 10 minutes so that you can give chance to all colleagues of yours. Therefore, I give ten minutes each only for the Ruling Party Members. I will decide further after your speech is over, after ten minutes. Even if 10 minutes each are granted to Ruling Party Members and the Opposition Party Members, it comes to the fact that at 11 o'Clock only the Minister can reply.

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): You should not put a limit to ten minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There should be a workable formula. All the Members of the Ruling Party may not speak, some may withdraw. But from the Opposition everybody will be given a chance. Even by giving ten minutes to each, it comes to the point that at 11 o'Clock only the Minister can reply.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will allow you all. Even if it is midnight I am prepared to sit provided all the Members who are present now give me an assurance that the House will not become thin.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (RAO BIRENDRA SINGH): Sir, does 11 o'Clock mean tongiht or tomorrow morning at 11 o'Clock?

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must also see the criticism in the press about Rajya Sabha yesterday. Therefore, when a discussion like this takes place, I want to make it very clear to the hon. Members that when the Minister replies, the attendance—I do not want to say more than this. Therefore, if all of you are present here—you can go and take coffee and all that, but when the Minister replies, the number of Members now available must be present. I will not restrict your time. But would you give an assurance to that effect?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: For the Ruling Party Members only ten minutes each will be given. The Minister will speak at 11 o'Clock on the condition that all the Members who are present now will keep sitting.

RAO BIRENDRA SINGH: We will cut short the speech if the Members are not present.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They have to give an assurance. But, for the Ruling Party Members only ten minutes time will be given to each because their number is more. Now, Mr. Uma Kant Mishra may speak.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have given the formula. We can work out on that formula. We will see if there can be any relaxation on that.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Without your cooperation we cannot run the House. Therefore, I am putting this before you.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are the only lady Member and Mrs. Geeta Mukherjee is also there. Therefore, we want that both of you will remain till the Minister replies.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will call one from this side and one from that side. Now, Mr. Uma Kant Mishra will speak.

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले मार्च में इस देश में बड़े पैमाने पर कई भूभागों पर ओले पड़े और अरबों रुपये की किसानों की फसलें नष्ट हो गई । इसके बाद जून-जुलाई में किसानों ने खेती के लिए मन बनाया तो भयंकर सूखा पड़ गया, मानसून एक महीने लेट हो गया । बहुत से इलाकों में भदई और क्वार की फसल बोई ही नहीं जा सकी । सूखे की वजह से किसानों की 25 प्रतिशत ही फसल बच पाई और 75 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई ।

जब वर्षा शुरू हुई तो खेती शुरू हुई, लेकिन इसके साथ ही भयंकर बाढ़ आ गई। जिन इलाकों में कभी बाढ़ नहीं आती थी, वहां भी बाढ़ आई और कई तरह से फसल नष्ट हो गई । इस तरह से इस देश के किसानों पर प्रकृति ने कभी ओले से, कभी सूखे से और कभी बाढ़ से बहुत बड़ा अत्याचार किया है और इससे किसानों की बहुत बड़ी क्षति हुई है ।

हमारे श्री हरिकेश बहादुर ने यह चर्चा शुरू की है, उन्होंने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला है । उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र है । इस बार इस प्रदेश को तीनों आपदाओं को झेलना पड़ा है । ओला से प्रभावित हुआ है, सूखे से प्रभावित हुआ है और बाढ़ों से बहुत ही अधिक उत्तर प्रदेश प्रभावित हुआ है । उत्तर प्रदेश तो बर्बाद हो गया । इसमें कोई सन्देह नहीं है । इन आपदाओं से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार और

प्रदेश की सरकार ने तत्काल राहत के कदम उठाये हैं और प्रधान मंत्री जी ने दौरा किया है । कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री और प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया है । इनके द्वारा अधिक से अधिक जानों को बचाने के लिए प्रयास किया गया है । लोग भूख से मरने न पायें, उनको खाना उपलब्ध कराया गया है । इतनी बाढ़ की भयंकर विभीषिका थी, इससे जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन धन की हानि जरूर हुई है । सबसे बड़ी समस्या जो बाढ़ से निपटने के बाद पैदा हुई है, वह यह है कि रेलों की लाइनें नष्ट हो गई, स्कूल के भवन नष्ट हो गए, फसलें नष्ट हो गई, रास्ते नष्ट हो गये । अब तो वहां पर पुनर्निर्माण की आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है । इसलिए मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को पुनर्निर्माण के लिए, राहत कार्यों के लिए और बड़े पैमाने पर बाढ़ की रोकथाम के लिए अधिक से अधिक सहायता दी जानी चाहिये, ताकि इन आपदाओं से निपटा जा सके। यह सही है कि वहां पर एक केन्द्रीय टीम गई थी, जिसने वहां पर बहुत से जिलों का दौरा किया था । हमारे जिले का भी उसने दौरा किया था, उस टीम को सारी बातें बता दी गई थी कि किस प्रकार नुकसान हुआ है । जो इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, उनमें हमारा जिला मिर्जापुर, जिला बहुत ही प्रभावित हुआ है । वहां की शतप्रतिशत फसल नष्ट हो गई है । मिर्जापुर जिले में बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं, हरिजन रहते हैं, छोटे किसान रहते हैं और गरीब रहते हैं । उनके खाने के लिए वहां अन्न नहीं है । इसलिए सबसे बड़ा सुझाव यह है कि वहां पर बड़े पैमाने पर मिर्जापुर जिले में खास तौर से, पहाड़ी इलाकों में बाढ़ ग्रस्त और सुखाग्रस्त इलाकों में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत या अन्य प्रकार से उनको गल्ला दिया जाये । उनको वहां मजदूरी भी बहुत कम दी जा रही है । पांच-छः रुपए दी जा रही है, मेरे विचार में उनको दस रुपये मजदूरी दी जानी चाहिये और आधा गल्ला दिया जाना चाहिये । राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के कार्यक्रमों को चलाने के लिए सूबे की सरकारें इसलिए कम प्रयास करती हैं, क्योंकि उनको आधा रुपया केन्द्रीय सरकार देती है और आधा रुपया उनको लगाना पड़ता है । सूबे की सरकारें आर्थिक तंगी में हैं, जैसा कि मैंने पहले आपसे निवेदन किया है कि सूखे और बाढ़ तथा ओला से प्रभावित क्षेत्रों को और जहां भुखमरी के पैदा होने की आशंका है, वहां अब केन्द्रीय सरकार शतप्रतिशत सहायता दे, यदि भूख से लोगों को बचाना है, तो केन्द्रीय सरकार को तत्काल इस कदम को उठाना चाहिये, इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिये ।

इसके पश्चात् बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सस्ते दर पर, किफायती दर पर बीज और खाद की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिये । बहां पर नहरें टूट गई हैं, नलकूप टूट गये हैं, उनकी मरम्मत के लिए पैसे की कमी है । इसलिए मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के राहत के कामों के लिए तत्काल पैसा दिया जाये । तकाबी का कुछ पैसा दिया है, जिससे किसान मजदूर कुछ काम कर सकें । कुछ ऐसे लोग जो यह काम नहीं करते हैं, वे क्या खायेंगे, उन का काम कैसे चलेगा । इसलिए बड़े पैमाने पर तकाबी के ऋण की आवश्यकता है । मवेशियों के चारे की आवश्यकता है । इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को अधिक से अधिक धन देने के लिए सरकार को सहायता देनी चाहिए । मिर्जापुर शहर को ओला, सूखा और बाढ़ से बचाने के लिए केन्द्रीय

[श्री उमाकान्त मिश्र]

सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को अधिक से अधिक धन देना चाहिए, ताकि वहां का जन जीवन ठीक हो सके।

हमारे जिले में 1916 में बाढ़ आई थी, उसके बाद फिर 32 साल बाद 1948 में बाढ़ आई और फिर, 1968 में बाढ़ आई थी। 1968 के बाद 1978 में दस वर्ष बाद बाढ़ आई थी। 1978 के बाद 1980 में और अब 1982 में बाढ़ आ गई है। इस तरह से यह दो-दो साल में बाढ़ आने लगी है। इन बाढ़ों से हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र जल-मग्न हो जाता है। हमारे सिरों से ऊंचे पानी चला जाता है। इसलिए श्रीमन्, आपको सोचना होगा कि उन इलाकों को केवल राहत पहुंचा देने से ही काम नहीं चलने वाला है। उनके लिए आपको परमानेंट, स्थायी समाधान निकालना पड़ेगा।

हमारे यहां जो टीम गई थी उसको हमने सुझाव दिया था कि चार ब्लाकों कौन, छानवे, सीखड़, मझवा में कुछ ऐसी सड़कें बना दी जायें जो कि आठ-आठ फुट ऊंची हो जिससे कि बाढ़ के समय लोगों को राहत पहुंचायी जा सके और सड़कों पर आकर लोग जान भी बचा सके वहां जो ऐसे इलाके हैं जो कि बाढ़ में जलमग्न हो जाते हैं उनके लिए ऊंची जगहों पर मकान बना दिये जायें जिससे कि बाढ़ के समय में लोग वहां जा कर रह सकें। इस प्रकार से कोई अस्थाई समाधान भी आपको करना पड़ेगा।

जहां मैं बाढ़ से रक्षा करने की बात कहता हूं वहां मैं सूखे के बारे में भी कहना चाहता हूं कि इसका भी आपको स्थायी समाधान करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि जब हमारे सिंचाई मंत्री जी बनारस के दौरे पर गये थे तो उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ी योजना डा० के० एल० राव ने बनायी है जिसके द्वारा गंगा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों को जोड़ दिया जाए तो बाढ़ से भी समाधान हो सकता है और सूखाग्रस्त इलाकों को उस योजना से पानी भी मिल सकता है। यह योजना बहुत बड़ी योजना है। अरबों रुपये की योजना है। हो सकता है कि हमारी सरकार के लिए इसको पूरा करना संभव न हो मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार के सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इसको पूरा करें और अगर जरूरत पड़े तो जो हमारी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंसियां हैं उनसे भी मानवीय आधार पर सहायता ले कर इसे पूरा करें।

इस योजना को पूरा होने से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जो विशाल जनधन की हानि होती है उससे बचा जा सकेगा। यह हानि हर साल होती है। इसलिए इसके समाधान किये जायें और स्थायी कदम उठाये जायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मिर्जापुर, बांदा, वाराणसी और इलाहाबाद जिलों को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठायें और बड़े पैमाने पर उठायें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Krishan Dutta Sultanpuri. He will not take more than 10 minutes.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Time will be given equally. Nobody's time will be taken away.

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : (शिमला) : सर, मुझे कम से कम 15 मिनट दें।

मान्यवर उपाध्यक्ष जी, सारे देश में सूखा होने के कारण तवाही मची है। सारे भारत में कई जगहों पर नदी-नालों से जमीनें बर्बाद हुई हैं और लोगों की जाने भी गयी हैं। लेकिन मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां शिमला और हिमाचल प्रदेश में अधिक से अधिक वारिश होती थी। आज हालत यह है कि हिमाचल प्रदेश में मवेशियों के लिये चारा भी प्राप्त नही है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें, हिमाचल प्रदेश के अन्दर, हमारी सरकार को सरकारी नौकरों को भी तनख्वाह देनी पड़ती है। उसके लिये भी सरकार का पूरा नहीं हो पाता है। मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा हिमाचल प्रदेश पंजाब और हरियाणा पर निर्भर करता था लेकिन पंजाब और हरियाणा में तो ऐसा हो गया है कि वहां नहर ही नही बन सकती। हरियाणा में नहर न बनने से वहां का जो सिंचाई का साधन था रुक गया है। इसमें हमारे करोड़ों रुपये लग गये हैं।

हमारे पहाड़ी इलाके में डेम बन गये हैं। हमारे विलासपुर में हमारी बहुत सारी जरखेज जमीन डेम के अन्दर चली गयी है। उसके साथ व्यास लिंक के लिये भी आप ने बहुत अच्छी जमीन हमारी ले ली है। पहाड़ों के लोगों ने अपनी जरखेज जमीन को देश के लिये अर्पित कर दिया है। बाकी जो हमारे पास जमीन बची है उसमें हम सब्जी व दूसरी चीजें पैदा करते हैं। उसमें बीमारी लग गयी है। वहां कहत पड़ने के आसार हो गये हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हिमाचल प्रदेश का काम चलाने के लिये मंत्री जी मदद करें। वहां तीन डेम है। जब तक टीम जायेगी, तब तक लोगों का हाल बुरा हो जायेगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम 50 करोड़ रुपये का जो नुकसान हो गया है, उतना तो सरकार नहो दे पायेगी, लेकिन कम से कम 20 करोड़ रुपया तो जरूर वहां पहुंचा दे।

जहां बाढ़ और सूखा है, वहां राजनीतिक फ्लड भी आ रहा है। इसका लोग फायदा उठाना चाहते हैं। जनता को भड़काया जा रहा है। रेलों में बिना टिकिट यात्रा करके जुलूस निकाले जाते हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगाये जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश को बिल्कुल ठीक तरह से चला रही हैं। उनका बीस सूत्रीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

जनता पार्टी की सरकार में आप देखिये कि गन्ने की क्या कीमत किसानों को मिली थी। किसानों के उत्पादन को कीमतें बिल्कुल गिरा दी गई थी।

जहां तक फ्लड का ताल्लुक है, हिमाचल प्रदेश में मेक्सिमम फ्लड आता है और वहां से पानी आता है तो पंजाब की फसलों को बरबाद करता है और हरियाणा में भी नुक्सान होता है। करोड़ों रुपये की फसल नष्ट होती है। इसलिये

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

प्लांटेशन करके इस नुक्सान को रोका जा सकता है। इसके लिये सहायता दी जानी चाहिये। किन्नौर में एक भी पेड़ नहीं हैं, लाहौल स्पीति में एक भी पेड़ नहीं हैं। जनता पार्टी की सरकार ने सारे पेड़ कटवा दिये। यह काम किया जनता पार्टी ने। यहां पर जो चीज 12 बजे देखने को मिलती है, वह हमारे प्रदेश की विधान सभा में सारा दिन चलता है। विधान सभा में धरना देते हैं, नारे लगाते हैं। इसलिये कि वहां पर बी० जे० पी० है। ये लोग किस तरह से सूखे से और भुखमरी से निपटेंगे। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को अधिक से अधिक सहायता दें, ताकि वहां पर स्थिति का मुकाबला किया जा सके।

हरिकेश जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उससे लगता है कि वे राजनीतिक सूखाग्रस्त हैं। गढ़वाल में एक सीट क्या जीत ली समझते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान पर ही इनका कब्जा हो जायेगा। इस तरह इनका सोचना गलत है।

अभी मैं आंध्र प्रदेश गया था, तमिलनाडु गया था, एस्टीमेट्स कमेटी के साथ। माननीय दण्डवते जी भी हमारे साथ थे। वहां भी सूखा है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी सूखा है, केरल में भी सूखा है। कई प्रदेशों में सूखे की निस्थिति बनी हुयी है। इस स्थिति से निपटने के लिये सस्ते गल्ले की दुकानों को खोलने की तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

बंगाल की बात की गई कि वहां की सरकार बड़े काबिल आदमियों की सरकार है। वहां की सरकार की काबिलियत तो यहां बठे लोगों के व्यवहार से ही पता चल जाती है। वहां जो अनाज भेजा जाता है वह सब कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं में बांट दिया जाता है और आम जनता को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इन बातों को भी देखना होगा। (व्यवधान)) प्रोफेसरों का काम भाषण देना होता है। लेकिन बंगाल की सरकार अगर ठीक ढंग से काम कर सकी है तो भारत सरकार की वजह से ही कर सकती है। भारत सरकार आप को मदद करती है। हमारी पार्टी बिना भेदभाव के राज्य सरकारों की मदद करती है। सरकार उदारता से पैसा देती है। जब भी कोई मांग आती है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो मदद की जाती है उसका युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी आप को देना चाहिये। गलत तरीके से पैसे का या मदद का इस्तेमाल नहीं होना चाहिये। गरीब लोगों को फायदा पहुंचे इसको आप को देखना चाहिए कांग्रेसियों का भी ख्याल रखें जो वहां भूखों मर रहे हैं। अपनी पार्टी वालों का ही ख्याल न रखें, उनमें ही मदद को बांट न दें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे देश का सवाल है। मैं मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिये ताकि हम बच सकें। हिमाचल के लोगों को राहत पहुंचाई जानी चाहिए, ट्राइबल लोगों की मदद की जानी चाहिये। राजस्थान के लिये भी हमने पानी दिया है, पंजाब के लिये भी दिया है। बिजली पानी के साधन हमने हिमाचल में पैदा किये हैं। हमारे मंत्री लोग यहां घूमते रहते हैं और मांग करते रहते हैं कि हमें अनाज पहुंचाओ। लेकिन इसकी तरफ तवज्जह नहीं दी जाती है। इस तरफ आप तवज्जह दें। राव साहब हमारे यहां पंजाब में मुख्य

मंत्री रह चुके हैं। वह पहाड़ी इलाकों की हालत को जानते हैं। वहां किस मुश्किल से खेती होती है इसको जानते हैं खेती में जो बीमारियां लग जाती हैं उनका भी इलाज होना चाहिये। सेबों की हमारे किसानों को पूरी कीमत दिलाने की व्यवस्था होनी चाहिये। जमींदारों के फल आजादपुर में आते हैं और आजादपुर के जो आढ़ती हैं उनके पास झोले बने हुये होते हैं और जितना उसमें फल आ सकता है भर लेते हैं। इस तरह से करोड़ों रुपया हिमाचल और पंजाब के लोगों का लूटा जाता है। इस लूट से उनको आप बचाएं।

जहां-जहां सूखा पड़ा हुआ है वहां टीम्ज भेज कर जल्दी से जल्दी आप रिपोर्टस मंगाएं ताकि उन लोगों को फायदा हो सके, उनको राहत पहुंचाई जा सके।

मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): Sir, Now we are discussing about both floods and drought. The conditions in the country have reached such a stage that the Government can be said to have failed to control this calamity of flood and counter the effects of drought and both these are causing serious damage to the lives and properties of the people.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): It is a world-wide phenomenon.

SHRI SAMAR MUKHERJJEE: I will talk first about the floods. Then I will take up drought.

The Government is aware that this is a regular phenomenon. This flood and also drought has become a regular phenomenon, and without long-term measures and programmes to counter both the flood as well as the effects of drought, the situation will further deteriorate day by day.

But from the performance and the programmes of the Government, it is quite clear that the Government is not at all serious about meeting in a big way the threat posed by these natural calamities.

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj): Except in Calcutta; Except where Bengal is.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can reply if you don't agree with him.

SHRI RAM PYARE PANIKA: I don't agree with him.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: I am discussing a very serious issue. It is a serious national problem which is affecting millions and millions of people's lives and properties and mostly those who are affected are the poorest section of the people.

The statement given on 4th October by the Union Minister for Irrigation says:

> "Based on the information received so far from the State Governments, the total area affected by floods, is about 76 lakh hectares and out of a population of 335 lakhs, 932 human lives have been lost. The value of total damage due to floods and cyclone has been placed at Rs. 1150 crores approximately. The flood damage during last year was Rs. 1132.31 crores."

This year the damage is almost the same. So what measures have the Government taken since last year to improve the conditions this year? So serious thought must be given because there is a natural process. In our country the river system has not been controlled and the total amount of land covered under irrigation is less than 25 per cent. So we mostly depend on the vagaries of nature. That is that even after 35 years of our independence, we still depend on the vagaries of nature though when we give the reply in this House, we say we are doing so much, so much and so much. You must see the things in totality. About the Government measures, the long-term flood

[Shri Samer Mukherjee]

control measures, this is what I am quoting from the Government statement in reply to my question in June 1980:

> "Against a total investment of Rs. 976 crores on flood control work during the previous plan periods, the provision in the Sixth Plan is Rs. 1035 crores."

In the previous Plan the allotment was Rs. 976 crores and in the Sixth Plan it is Rs. 1035 crores. ...

RAO BIRENDRA SINGH: No, no. That was for all the previous Plans. That is for 30 years—all the Plans put together.

SHRI SAMAR MUKHERRJEE: I am giving the quotation from your statement. This is not mine.

RAO BIRENDRA SINGH: You have misunderstood the statement. All plans put together, it was Rs. 976 crores. You have not understood it properly.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Then,

> "The target of 3 million hectares of land to be brought under irrigation every year during the remaining years of the current Plan...

This si the target. What is the total position?

> "Out of the estimated cropped area of 170 million hectares...

This is also a statement by the Government.

> " . . . the area irrigated through major, medium and minor irrigation projects was 52 million hectares upto the end of March 1978."

So we can understand that out of 170 million hectares upto 1978, 52 million hectares have been brought under irrigation. Then,

> "It is estimated that by the end of June 1980 the potential created through all irrigation programmes would be 57 million hectares against 22.6 million hectares in 1951."

So how many long years will we take to reach 170 million hectares? This is the rate of your growth to bring the land under irrigation. How many years will you take? But what has been happening in between is the silting of rivers.

16.59 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the Chair*].

The rivers are rapidly getting silted. So their capacity to accumulate water is being exhausted so rapidly that unless there is regular dredging and unless the rivers are brought under control, this long-term programme will have no effect on control of floods and control of rivers.

This is the figure. Every year, starting from Mid-July within a period of three or four months, about 1400 million feet water rushes to the sea through our river channels. This is the course of the rivers and water is rushing to the sea. In that process, it deposits the silt and sediments on the river bed: It is, therefore, necessary to construct reservoirs in the catchment areas.

17. hrs.

Mr. Rao kindly listen to me.

RAO BIRENDRA SINGH: I am listening.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Unless this water is preserved through reservoirs in the catchment areas, you cannot control these floods. For that, the capacity of the dam has to be increased. The existing capacity is one-tenth of the requirements. That means your capacity to hold water in the dam should be increased by 10 times. Unless you do that, you cannot control the water. Unless you control the floods, you cannot supply water to the drought affected areas. We are becoming the victims of

these two types of calamities simultaneously—drought and floods. And this will be a permanent feature. Unless this Government gives a serious thought to this you cannot control this. The only solution is that if you can control the water, you can supply that water to the drought affected areas for irrigation, for drinking. Perennial supplies will be required for this purpose. Hydro-electric generation and everything can be done. This requires a new total national planning and that requires due understanding and new thinking. Unless this Government does this, you cannot fight the floods and drought.

What are the damages caused on account of this? I have no direct experience of the floods-affected areas where severe damages have taken place. But, I had the opportunity to go to Orissa after cyclone. I visited Cuttack and Bhadrak districts. I went to Sambalpur also. What does the statement of the Minister say and what are the damages caused in Orissa?

MR. CHAIRMAN: You were allowed 10 minuets. And it is over.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: This is for the ruling party Speakers. I am discussing a serious subject. I think you should not disturb me. See page 7 of Irrigation Ministers statement. The damage caused in Orissa on account of this devastating cyclone was in an area 25 lakh hectares, affecting a population of 73.23 lakhs and 8.1 lakh houses in the seven districts of Cuttack, Puri, Balasore, Sambalpur, Mayurbhanj, Dhenkanal and Keonjhar covering 110 blocks suffered significant damage. This is the Minister's statement. I am not going into it. What is the real damage?

In Orissa there had been cyclone, flood and drought all visited simultaneously. So, there it was this combination of three types of attacks—you can call them 'attack of nature' but how can the people withstand all these attacks unless the Central Government comes forward in a big way with all types of relief?

I visited some areas after cyclone. I have seen what relief measures are given. They are too inadequate. There also, the distribution is being done through officials who are directly involved in corruption. There was a place where firing took place. This place is in Bhadrak district in Orissa. The firing took place in the afternoon; I was there in the morning. All the people surrounded me and told me about their difficulties and corruptions in matters of relief distribution. I will tell you one story. There are the Revene Inspectors who were entrusted to prepare the list of affected persons for Relief. It is said by these people who gathered that these officers will not prepare the list unless 20 per cent commission is given. Otherwise their names are not listed. This was stated before the officer when the officer came to me when he learnt that I have come there along with some other friends. The officer came to me. He was distributing relief. When I was there, people surrounded me and said about this. I asked them You make your statement before the officer. 'He had to admit. He told them 'You give in writing; I will enquire'. This is what is happening. 20 per cent commission is charged by the Revenue Inspector. For getting a relief of Rs. 100 they have to pay Rs. 20 as commission. When I was coming back one middle-aged lady came and touch- my hand; I thought is was some petition or memorandum. I get large number of memorandum. I get large number of petitions or memoranda when I visit various places. When I opened that paper I found, it was a 100-rupee note. I told her 'What is this?' She wanted Rs. 500 as relief. So, this 20 per cent Commission. I told her, 'I am not the person' and returned money. So, immediately she realised her mistake and she went back. So, this thing has become a regular practice there. In the ration shop whichever ration is given is not fit for human consumption. I got some samples. I got it from Orissa. I could not present them here. So, my friend Mr. Satyasadhan Chakraborty presented that here. Even animals cannot eat such food. Blackmarketing is going on in full swing. Corruption is rampant there. The ruling party people are also the real bosses to these officers who are preparing the list and distributing relief. This is my personal experience. I did not

[Shri Samar Mukherjee]

get the occasion earlier to speak on this and so now I am dealing with it in detail. The nature of devastation is very huge in Orissa. Entire Sambalpur town has gone under water. I was in Sambalpur at that time. I know the condition. Hirakud dam has been completely damaged as has been admitted by the Minister's statement itself. Mahanadhi bed has been completely silted. Regarding this there was the Chief Minister's statement. This has come in today's *Statesman*. Mr. J. B. Pat- Chief Minister, Orissa has stated this.

> "The devastation caused by the recent floods in the Mahanadi system in Orissa was more devastating than the ravages by the Ganga. Some of the flood-hit towns in Orissa looked like towns ruined by bombardment. Heavy damage had been caused to the irrigation canal system and the surface roads."

He has demanded Rs. 616 crores. How much has been given? You will no doubt make a statement here..

RAO BIRENDRA SINGH: Rs. 618 crores.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: You are adding 2 crores more. I am from the press report. So, you see, the damage due to flood is very serious. But I am not going into the flood subject any more.

Now, I come to drought situation. The report in the newspapers also says about the seriousness of the drought situation. It has affected the people very seriously. I will read out a news item on the front page of the 'Statesman' of 14th October 1982.

> "Starving Santhals take up arms for justice"
>
> "In fact, many villages have not received either rice or wheat through the Fair Price Shop for the past two years. And worst, those demanding food have been fired on by Police on Thursday last. Five people were killed when the Police fired on a group of people who were agitating for declaration of the district as a drought-affected area at Pulijori".

So instead of giving relief, you are sending the Police to fire at the innocent people.

SHRI NIREN GHOSH (Dum-Dum): They asked for food, but you gave them bullets.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: This is the situation at present. The situation will go out of control if the situation continues. According to the press report in today's paper, you have admitted that severe drought is hitting Rajasthan. I do not deny it. But the defermination in combating the severity does not come out of this statement. Now, the point is: how much you have done for these areas? Your expression of good words will not produce any result unless sufficient material and financial help is given to the people in those areas.

I will now deal with West Bengal. I remind the hon. Minister that in the last Session there was a debate on this subject and I also drew the attention of the Minister to the seriousness of the situation in West Bengal at that time. I also mentioned that drought started even in the previous year in West Bengal where crops were being affected very seriously. Therefore, they were forced to depend mainly on the Centre. That is why they demanded that the Central allocation of foodgrains to West Bengal should be raised and in the last debate I pointed out that the supply should be increased to 3,30,000 tonnes per month. I also read a speech made by the Minister in the Rajya Sabha yesterday. He says, he is much more liberal to West Bengal. In what ways he is much more liberal to West Bengal? Is it in words or in practice? The West Bengal Government has sent an SOS message to the Centre. I would like to make it clear that unless you send the required quantity of foodgrains, rationing will collapse there. He has stated in the Rajya Sabha "we are ginving a supply of 2,25,000 tonnes". We do not want to hear the sweet words from

the Minister. We want the materials to be sent to West Bengal so that they may be saved from the present serious condition. Now, the situation is very very serious. This must be undestood by one and all. I want to emphasise on that aspect only because the seriousness is such that the distribution of rice through the Fair Price Shops had to be cut down in Calcutta. Now it has been reduced from 4 Kg. to 3 Kgs. because of lack of supply of foodgrains by the Centre.

The price of the foodgrains is raising outside and therefore the people are rushing to the ration shops. Now they buy the foodgrains from the ration shops. Earlier many used to buy from open market because the quality of rice supplied in the ration shops was not good. But now all are rushing to the ration shops. The situation has become very serious and West Bengal Government has appealed to the people of Calcutta at least to sacrifice one kg. per head for the rural people. The appeal has been made that we must save these people in the villages by collective contribution. We do not depend entirely on the Centre, but at least rationing must be maintained, and for that the minimum quantity required must be provided to West Bengal. Our Chief Minister rushed to Delhi yesterday; he was here today morning also. He telephoned to me and told me that I must impress upon the Government the urgency of the situation. On 12th October, the Chief Minister sent a telegram and I am reading that:

> "We are facing a grave situation because even inadequate allocation of rice did not reach the State."

Allocation is inadequate, and even that did not reach the State.Further:

> "In September, about 1.27 lakh metric tonnes Central pool rice reached the State against the allocation of 1.50 lakhs metric tonnes resulting in the shortage of more than 22000 metric tonnes."

RAO BIRENDRA SINGH: What was the offtake? What was the quantity issued?.... (*Interruptions*). How much has been issued actually? Reaching foodgrains is our responsibility. You are misleading the House.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: I have read your statement. We do not want to go into this controversy.

SHRI CHITTA BASU (Barasat): How can they issue if the foodgrain is not available?

RAO BIRENDRA SINGH: Allotted quantities are available.

Why do not you talk of what you are getting?

SHRI SAMAR MUKHERJEE: We are getting much less than what you are allotting. I am reading the statement:

> "Nearly 2.25 lakh metric tonnes of foodgrains are released every month for the public distribution system in West Bengal."

And their demand is 3.75 lakh meters tonnes. During the last debate I also requested you to raise the quota, to 3.30 lakh metric tonnes. This controversy, how much is offtake, and how much is issued, should not be brought here. The situation is very very serious. You should increase the allotment and it should be rushed to West Bengal as quickly as possible.

The question of rakes is also there. I talked to the Railway Minister, earlier also I talked to them, and I was told that their wagons are lying idle, there is no shortage of wagons. It is the FCI or the Food Ministry, who not requisition the wagons. Their point is that they should not be blamed for this. About half an hour back, I talked to Shri Mallikarjun also. I told him that I would raise it on the floor of the House also. On the plea of shortage of wagons, the supply should in no way be affected. This is an important point. The Chief Minister has talked to you also. I do not want to discuss these things in detail, but the situation in West Bengal is very very serious.

PROF. MADHU DANDAVATE: Did you talk to the latest Railway Minister?

SHRI SAMAR MUKHARJEE: I could not talk to him, but he has also made a statement that wagons are lying idle. He said that in the Consultative Committee meeting also.

SHRI NIREN GHOSH: Before leaving, the Chief Minister has also written a letter to the Minister indicating in short what should be done. We should not go into the jugglery of figures.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Now, their demand for rice is 2 lakh metric tonnes, wheat for public distribution system 1.20 lakh metric tonnes, and wheat for roller flour mills 55 lakh metric tonnes; total 3.75 lakh metric tonnes. The Chief Minister has told that at least four rakes must move daily. In his telegram he has told that the arrival of rice is further deteriorating in October, and if the further adequate monthly allocation of rice which is 1.5 lakh metric tonnes is to be delivered, then four rice takes should reach West Bengal daily. Against that only 16 rise rakes reached West Bengal up to the seventh of October. Now, the total stock there has depleted and the rice stock is most probably 90,000 tonnes, which is only for two weeks of rationing. So food should be rushed there without delay.

MR. CHAIRMAN: Mr. Mukherjee, please conclude now.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: I am concluding. Then the difficulty is that this food for work programme has also been stopped. In villages there are no works, no income. And since the supply in the ration shops has been reduced, the most affected persons are the landless labourers, the poor peasants, small income group people. And they have to purchase from the open market where the prices are rising to more than Rs. 4/- a kilogram. But they have no purchasing power. They are mostly rise eaters and this has created a serious crisis there.

Sir, in West Bengal there was no rain since September and the crops have to be saved. From the dams also water quantity has been so much reduced that the water is not sufficient for the maintenance of the crops. The Government is trying to get some water from the DVC. If water from here is available, then seven lakh acres of area under foodgrains can be saved. Otherwise the next year the crop prospect is very dim. The yield will not be more than 50 per cent. It will be rather less than that.

Sir, the food stock is not there in the hands of the State Government. We are exclusively dependent on the Central supply. The situation is critical because these overdrafts have already been stopped. So the State Government cannot go to the Bank for overdraft to meet the emergency situation. Over and above that the Central Government has banned import from other surplus States, by the State Government So, the people in West Bengal are facing the threat of starvation because of this suffocation and the spectre of famine is haunting in West Bengal and the famine of the old days is coming into their memories.

Sir, because of the distribution through Panchayats corruption is much less in West Bengal though the crisis is very serious already. Some news has appeared in the press that one wagon has been looted. This type of tendency also is growing, through we are asking the people to be patient and not to be swayed by those who are taking to such methods, and Sir, your Party people are also trying to take advantage of this situation.

Sir, the people are on the verge of starvation. Nobody knows what will be the fate of the people there if Central quota is not increased in the coming days. You know, Sir, Pooja is a very big festival in West Bengal. Therefore, before Pooja this increased supply has to be rushed into West Bengal. That is why the due must also be rushed immediately. There should be proper storage for the lean period and sufficient stocks must be stored. Then the Government

must be allowed to purchase foodgrains from other surplus States so that the State Government can manage on its own to a certain extent. And this supply through sufficient wagons and rakes should be guaranteed.

MR. CHAIRMAN: Please leave something to the imagination of the Minister.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: I am requesting the Minister to realize the seriousness of the situation. A Central team should be sent immediately. The Chief Minister has sent another proposal, regarding a Regional Standing Committee. He might have requested you to immediately send a Central team to study the situation. Earlier, they wanted Rs.75 crores. But only Rs. 24 odd crores have been given. This is too inadequate for the State Government to cope with the situation. The Chief Minister has told you; he will go back and send a subsequent report, pointing out how much of cash is to be given immediately, to counter the situation.

I again emphasize the urgency and seriousness of the situation. It should be realized by the Government, and they should respond to the demand of the State Government.

SHRI BHEEKHABHAI: rose

(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I know your name is being called. But before that I will just request the hon. Members from the Opposition also to impose some discipline regarding time Ultimately, it is not only for the ruling Party. They have fixed ten minutes for each Member. (*Interruptions*) My request is to the whole of the House. I cannot make a request to a part of the House, and not to the other part. If we want the business to be finished within a reasonable time, we have to exercise some self-control.

Now Shri Bheekhabhai.

श्री भीखाभाई (बांसवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं आप का शुक्रगुजार हूं कि मेरी दयनीय अवस्था को समझते हुये मुझे 5, 7 मिनट का समय दिया, और मैं अपने अन्य मित्रों का समय ले रहा हूं इसलिये भी अपने आपको गिल्टी समझता हूं।

मेरी एक ऐसी कांस्टीट्यूएंसी है जो आदिवासी क्षेत्र है और उनकी समस्या अन्य जातियों की समस्याओं से भिन्न है। राजस्थान की समस्या तो बहुत ही गंभीर है, परन्तु मुझे दुख हुआ हमारे कृषि मंत्री जी ने 4 तारीख को जो जवाब दिया उसमें राजस्थान का नाम नहीं लिया और उल्लेख नहीं किया कि वहां अकाल है। दूसरे दिन हमारे मुख्य मंत्री ने उसके बारे में स्टेटमेंट दिया और कहा कि 350 करोड़ रु0 राजस्थान सरकार को दिये जाने चाहिये। राजस्थान में जहां पानी की समस्या है, जहां पर फूड की समस्या है, रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके की समस्या है वहां आपको अधिक धनराशि देनी चाहिये, ऐसा मैं भी प्लीड करता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि आपदायें और विपदायें प्राकृतिक हैं और हमेशा आती रहती हैं, लेकिन उनको हम सब मिलकर हल कर सकते हैं और अगर दिलो जान से जुट जायें और आम लोगों का सहयोग प्राप्त कर सकें तो इस काम को कर सकते हैं। जब से हमारी राष्ट्रीय सरकार बनी है, तब से हम लगातार यह बात समझ रहे हैं कि हमारी सरकार को व्यवस्था करने की ओर अकाल से जूझने की चिंता है। हमेशा राज्य सरकारों को वह धनराशि देती है। मैं पुरानी बातें कहना चाहता हूं। संवत् 1956 में एक बड़ा अकाल पड़ा, उसके बाद संवत् 1957, 1972 और 1993 में अकाल पड़ा। उसके बाद भी छोटे-छोटे

[श्री भोखाभाई]

अकाल पड़ते रहे हैं। बंगाल में, उड़ीसा में भी अकाल पड़े परन्तु उस समय की तत्कालीन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया।

अभी उधर से मुखरजी साहब बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ रही है और किसी भी प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं का मुकाबला करने के लिये सक्षम रही है। मनुष्य की कमजोरी है, कई स्तरों पर यह बात हो जाती है, इसलिये कभी कमजोरी आ जाती है और काम के इम्पलीमेंटेशन में कमी भी हो सकती है। इसको ठीक करने के लिये यह जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार की एक टीम सब जगह जानी चाहिये। अभी कहीं जाती है, कहीं नहीं जाती है। इंटीरियर में कोई नहीं जाता है, एक्सटीरियर में होकर लौट आते हैं।

मैं कृषि मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इसके हल के लिये एक वालेन्टियरी सैल बनाना चाहिये जो कि स्टेट टू स्टेट जाये और रैगुलेट कर के काम को देखना चाहिये कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। गड़बड़ी बहुत होती हैं, कहीं वितरण में और कहीं काम में।

आदिवासी क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जबलपुर का इलाका हो, झाबुआ, मांडला, अलीराजपुर, सरगुजा, संथाल परगना, पलामू या छोटा नागपुर का इलाका हो। हमारे राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के इलाके हैं। सर्वत्र एक बात है, हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, लेकिन पहाड़ी सहायता जो दूसरे लोगों को मिलती है, हिमाचल वाले पहाड़ी इलाके के नाम से पैसा लेते हैं, लेकिन हमको वह पैसा नहीं मिलता है। हम भी पहाड़ी इलाकों और वनों में रहते हैं। बड़ी-बड़ी योजनाएं जो बनती हैं। उनकी वजह से जितना बड़ा नुक्सान हमका होता है, जितनी व्यवस्था हम करना चाहते हैं, उतनी राशि हमको कोई नहीं देता है। वहां के जो आदिवासी लोग हैं, उनकी 2, 2 और 3, 3 बीघे जमीन अन-इकनामिक है। एक बड़ी भारी मैन-पावर है जिसके पास काम नहीं है। राज्य सरकारें यह करती हैं कि जिस जिले की जितनी जनसंख्या है, उस जिले के उतने मजदूर उसी आधार पर काम करें। इस बात को भी देखा जाना चाहिये। अभी होता यह है कि जहां ज्यादा पोलिटिक्स होता है, वहां काम ज्यादा होता है।

सूखे से निपटा जा सकता है। साइक्लोन हो, टाइफून हो, बाढ़ हो, इनको तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन सूखे को रोका जा सकता है। यह ज्यादा भयंकर चीज़ नहीं है, अगर प्रापर प्रौस्पैक्टिव प्लानिंग हो जाये तो इसका स्थायी रूप से हल निकाला जा सकता है। इसके लिये योजना बनानी चाहिये।

एक तरफ़ कहा जाता है कि बाढ़ आती है, दूसरी तरफ अकाल हो जाता है। क्यों नहीं बाढ़ का पानी अकाल के क्षेत्र में दिया जा सकता है। उसकी व्यवस्था करनी चाहिये, प्रापर सर्वे करना चाहिये और इंटर-लिंकिंग होनी चाहिये। लेकिन यह होता नहीं है, इसलिये सूखा पड़ता है।

यह बात ठीक है कि हमारे मंत्री जी सक्षम हैं, सफल भी हुए है और किसानों

के प्रति हमदर्दी भी उनके दिमाग में है। हमारे इरिगेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो इरिगेशन पोटेंशियलिटी बढ़ाते हैं। यदि ये दोनों मिनिस्टर मिल कर काम करें तो मैं समझता हूं कि बाढ़ और अकाल दोनों से निपटा जा सकता है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे कहीं पर बाढ़ आती है और कहीं पर सूखा पड़ता है, तो उस बाढ़ के पानी को सूखे के क्षेत्र में डालने का प्रबन्ध करना चाहिए। इस प्रकार अकाल नहीं आएगा। और उधर बाढ़ भी कम हो जाएगी। मेरा सुझाव है कि समाल इरिगेशन प्रोग्राम को भी लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। पहली, राजस्थान हमेशा अकाल से प्रभावित रहता है, इसलिए इस प्रदेश को अधिक से अधिक राशि दी जानी चाहिए। दूसरा, मैं ट्राइबल क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, मैंने संथाल परगना देखा और दूसरे क्षेत्र देखे हैं, ट्राइबल सदस्य कुछ कहें या न कहें, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं वहां बहुत ही गरीबी व्याप्त है।

I will also support their demands and they cannot be denied. Therefore, we have to see that all possible steps are taken to utilise the manpower. At the same time the water flowing from he high hills has to be stopped and properly utilised.

जिन क्षेत्रों में डैम्स हैं, उनको उनका फायदा भी होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आबंला) : माननीय सभापति जी, एक देवता के गुस्से से और एक देवी की अयोग्यता से हमें बाढ़ और सूखे के प्रकोप का सामना बहुत भयंकर रूप से करना पड़ रहा है। जब इन्द्र भगवान ज्यादा गुस्से में आते हैं तो कहीं पर ज्यादा बाढ़ आती है और कहीं पर ज्यादा सूखा पड़ता है और श्रीमती इंदिरा जी, देवी जी, उस प्रकोप का सामना जिस प्रकार से करना चाहिए नहीं कर पाती हैं। बाढ़ के बाद, सूखे के बाद, हम उस समस्या से कैसे निपटें, इस समस्या का समाधान आज इसलिए नहीं हो पाता कि इतनी दूरी हम यहां पर अपने सदन में बैठे कृषि मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी के बीच में देख रहे हैं, जितनी दूरी उनकी नीतियों में हैं। हमें खर्चा तो करना होगा, तब हम जाकर बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान कर सकते हैं। सूखे से निपटने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी दो दिक्कतें आती हैं। सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी। सिंचाई के लिए पानी इसलिए नहीं मिल पाता क्यों हम 35 सालों में इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं, जिससे सिंचाई के साधन बढ़ें।

आप देख लीजिएगा कि बाढ़ खत्म हुई और हमारी नहरों में पानी नहीं। ट्यूबवेल्स ज्यादातर बेकार पड़े हुए है। किसी के मोटर जले हैं, किसी का लिफ्ट इरिगेशन काम नहीं कर रहा है। नहरों में पानी नहीं जाता है।

मैं बदायूं और बरेली जिले में रात-दिन जा कर देखता हूं कि सैकड़ों ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जिनके मोटर नहीं है। ये सरकारी ट्यूबवेल्स की हालत है। मोटर को बनाने की व्यवस्था नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में ट्यूबवेल्स खराब पड़े हैं और जो चल रहे हैं उनको बिजली नहीं मिल पाती। बिजली किस समय आयेगी, यह पता ही नहीं होता।

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

किसान सो रहा है तो कभी रात को बिजली आ गयी, किसी दिन दिन में आ गयी, कभी एक घंटे को और कभी दो घंटे को आ गयी। यह तो फसल की बुवाई का समय है। लोग बुवाई में लगे हैं लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है। फिर किसान कसे सिंचाई कर के अपनी फसल को बोए ? यह एक गंभीर समस्या हो गयी है। इस से हम को बहुत मेहनत और सूझबूझ के साथ निबटना चाहिए।

आप सिंचाई के साधनों को बढ़ाएं। लेकिन जो मौजूदा साधन हैं उनका भी आप सदुपयोग करें। उन्हें आप बन्द न रखें। बिजली की आपूर्ति और सप्लाई इस ढंग से करते रहें कि हमारे लिये सिंचाई के साधन कायदे से उपलब्ध रहें। खास तौर से इस समय जब कि रबी की फसल बोनी है। इस समय पानी की कमी न आये।

आप बता देते हैं कि हमने इतने सिंचाई के साधन बनाये हैं। लेकिन उनमें आप उनको भी जोड़ लेते हैं जो ट्यूबवेल्स बंद हो गये हैं, जो अपनी क्षमता से बहुत कम फीसदी काम कर रहे हैं, बहुत से ट्यूबवेल्स तो बिल्कुल बैठ गये हैं, बहुतों की नालियां टूट गयी हैं, पानी दूर तक नहीं जा पाता है। किसी ट्यूबवेल की क्षमता तीन-चार साल की होती है। उसके बाद उसकी क्षमता घटती चली जाती है। हमारे यहां ट्यूबवेल्स दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल पुराने हो गये हैं। इन पुराने ट्युबवेलों की क्षमता बहुत घट गयी है। हमने इन ट्युबवेलों की क्षमता को नहीं आंका है। हमें इनकी क्षमता को भी आंकना पड़ेगा तभी इस देश की सूखे की समस्या से निबटा जा सकेगा। इसमें इन्द्र भगवान् का दोष नहीं है। इसमें इन्दिरा देवी जी का दोष है। उनको ही इस पर ध्यान देना पड़ेगा। (व्यवधान) हम तो वही कहेंगे जो हमें नजर आयेगा।

एक राजा के सामने प्रजा रोटी मांगने गयी। राजा ने प्रजा से कहा कि अगर तुमकों रोटी नहीं मिलती तो डबलरोटी खाओ, पूरी खाओ। हम सूखे से पीड़ित लोगों को भोजन चाहिए, काम चाहिए, तो आप कहते हैं एशियाड देख कर तसल्ली कर लो। आप डबलरोटी की जगह एशियाड गेम्स दे रहे हैं।

1980 में हम सूखे के शिकार थे, 1981 में बाढ़ के शिकार हुए और इस वष 1982 में बाढ़ और सूखे दोनों के शिकार हैं। इन परिस्थितियों में हमें बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। यह ठीक है कि हम प्रकृति के प्रकोप का पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं लेकिन इसे बहुत बड़ी सीमा तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार से इलाहाबाद से हावड़ा और हल्दिया तक आप गंगानदी को गहरा करने जा रहे है, उसी प्रकार से आप देश की अन्य नदियों को भी गहरा करने का प्रयास करें ताकि उनमें पानी रोकने की क्षमता काफी हो। इस से बे हमारा जलमार्ग भी बन जाएंगी। इसके साथ ही हमारे वेस्ट बंगाल के भाई भी प्रसन्न होंगे कि इन से मछली का उत्पादन भी बढ़ेगा।

बाढ़ से राहत दे देना ही काफी नहा है। आप राज्यों को राहत कार्य के लिए धनराशि दे देते हैं। राज्य सरकारों जिला प्रशासन को बांटने के लिए दे रही हैं। लेकिन आप देखिये यह राहत किस प्रकार से बांटी जा रही है ? जिनको आवश्यकता

है, उनको वह नहीं मिल रही है। जिनके मकान गिर गये हैं, जो तबाह हुए हैं उनको राहत नहीं मिल पा रही है। बरेली और बदायुं के हजारों किसानों ने दरख्वास्ते दीं, पर किसी को राहत नहीं मिली। कानूनगो या पटवारी जिसके बारे में लिख देता है, उसको मिल जाती है। बाकी लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है और हजारों एप्लीकेशंस जिलाधीशों के यहां पड़ी हुई हैं। जिला अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास जो लिख कर आया है, उसके अलावा हम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्र की तरफ से एक स्क्रीनिंग देहातों में होनी चाहिए, जहां पर बाढ़ और सूखे की विभीषिका का और उनकी सुविधाओं का इंतजाम किया जाना चाहिए। आज वहां पर अनाज नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है, चीनी नहीं है। मिट्टी का तेल न होने की वजह से वहां रात को रोशनी नहीं होती है। बाढ़ के समय तो हालत और खराब थी। इसी प्रकार आप नावों का इंतजाम उस समय करते हैं जब बाढ़ आ जाती है। आपको पहले से ही एक दल को तैयार रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के नाविकों ने लिखकर भी दिया था कि वे मुफ्त सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि आप तो ठेकेदारों के जरिए यह काम करवाते हैं। ठेकेदारों को 80 रुपया मिलता है, लेकिन बेचारे नाविक को 10 रुपए ही मिलते हैं। इसलिए आप ऐसे नाविकों को पहले से तैयार रखिए, इससे आपका पैसा भी कम खर्च होगा और लोगों को सुविधा भी अधिक मिलेगी।

नदियों से पानी लेकर लिफ्ट इर्रीगेशन के जरिए अच्छी सिंचाई होती है, लेकिन लिफ्ट इर्रीगेशन के बहुत से काम बन्द हैं। मंत्री जी आदेश देते हैं, लेकिन उसका पालन नहो किया जाता। बदायूं जिले में एक बड़ी नदी से नहर निकलती है, कई महीनों से वहां लिफ्ट इर्रीगेशन के जरिए पानी के संचालन की प्रक्रिया बन्द है। लोगों की धान और मूंगफली की फसल सूख रही है। फसल चौपट हो रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है। रोज रेडियो बोलते हैं, सरकार आश्वासन देती है कि हमने लगान की वसूलिया रोक दी हैं, कर्जे की वसूलियां रोक दी हैं, लेकिन जिला प्रशासन अपने कर्मचारियों को जो हिदायत देता है कि जल्दी से जल्दी पैसा वसूल किया जाए। सूखा पीड़ित लोगों से, बाढ़ पीड़ित लोगों से अधिक सख्ती से पैसा वसूल किया जा रहा है।

किसानों का जो पैसा बाकी है, वह उसको मिलना चाहिए। गल्ले का और गन्ने का करोड़ों रुपया बकाया है। शेखुपुर, बदायुं सहकारी चीनी मिल में किसानों का डेढ़ करोड़ रुपया बाकी है। किसान को फसल बोनी है। उसको पानी चाहिए, बीज का इंतजाम करना है, खाद का इंतजाम करना है, मजदूर के लिए पैसा चाहिए। डेढ़ करोड़ रुपया जहां किसानों का बाकी हो, कहां से वह सारी सुविधाएं जुटा पाएगा? सरकार सुविधा नहीं दे पा रही है। इसलिए बदायूं का किसान 19 तारीख से जेल भरो आंदोलन शुरू कर रहा है।

मैं ज्यादा न कह करके खास तौर से बाढ़ रोकने के लिए और सूखे से कैसे निपटा जाए, इसके लिए कुछ कहना चाहूंगा। इसको देखने के लिए एक संसदीय समिति बनाई जाए, तो इन सब चीजों को देखें। क्योंकि नौकरशाही के हाथ में आपने सारी व्यवस्था दे रखी है, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसे जनता से वास्ता नहीं रहता।

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

इसी प्रकार दूसरे देशों, जैसे केलीफोर्नियां आदि ने बाढ़ पर नियंत्रण किया है, उनसे हमको सीखना चाहिए। अंत में मैं फिर वही कहूंगा कि हे इंद्र भगवान रहम करो, हे इंदिरा देवी रहम करो ताकि देश का कल्याण हो। (इति)

SHRI K. T. KOSALRAM (Tiruchendur): Mr. Chairman, I am very thankful to you for giving me an opportunity to speak on this subject.

Mr. Mukherjee just now spoke explaining Mr. Mukherjee just now spooke explaining the point of view of West Bengal Government and the Chief Minister of that State and also the coordination between the Members of Parliament of that Party and the West Bengal Government. Unfortunately, Sir, in my State, Tamil Nadu, the Chief Minister never writes to his own party Members about any serious problem. Instead, he is organising a strike and a State-wide bandh in Tamil Nadu State condemning the Government of India. But my hon., friend Rao Birendra Singh Sahib is here. Rao Birendra Singh Ji, I want to know from you whether Mr. M. G. Ramachandran's Government has written to you, has sent a memorandum to you, requesting you or demanding so many lakhs of tonnes of foodgrains. Kindly reply to that. His Chief Secretary is issuing something and the Chief Minister himself is irrelvantly saying that 'the Central Government is not looking after us'. That is the allegation made by them. But I congratulate the West Bengal Chief Minister because he has got the coordination with the hon. Members of this House. My AIDMK friends are here. Let them say as to how many letters they have received from their Government and what is the position in Tamil Nadu. I want to know the actual position.

Sir, every Member spoke about the flood affected parts of the northern side and the drought affected parts of the southern side. How are you going to solve this problem? My hon. friend just now told that there should be a parliamentary committee to go into this question. The 'parliamentary committee' means gimmicks. My friends, Mr. Kedar Pandey and Rao Birendra Singh will agree with me that this is a serious problem. You should declare all the rivers as national waters and national wealth. Then only can you maintain the integrity of the country. That is the main thing.

My friends have elaborated all these things and I do not want to repeat them. But every year we are losing Rs. 1,400 crores in drought on the one side and flood on the other side. This is a fact, the Government cannot deny it. Under the Chairmanship of the Prime Minister some Advisory Committee seems to have been formed. How many committees have been formed? I am telling you, Mr. Pandey Ji, that the Prime Minister appointed a technical committee and the Planning Commission also appointed a technical committee. All the waters of the West-flowing rivers go waste into the sea. One million hectares can be irrigated with this water according to the Irrigation Committee Report. The Kerala Government has given its concurrence and the Karnataka Government has given its concurrence for the constitution of this committee. But what happens ultimately? Where is the Committee Report? Could you kindly place before this august House the reports of all the committees? These Committees were appointed by the Prime Minister of India with the concurrence of the States. But you are not in a position to implement the recommendations of these Committees. What is the use of appointing this Committee or that Committee? That is a great force. Our Party has got full strength here. I do not think other Opposition Parties will oppose declaring rivers as national wealth. My friend Shri Mukherjee explained very categorically. So, I do not think anybody will oppose it. You take a firm decision.

Irrigation Committee submitted its report in 1972. In my Constitutency Nanguneri Stankulam and Sankarankoi have

always been drought effected areas. Attention should be given by the State Government as well as by the Central Government. Ten years have passed since the Committee submitted its report, but the authorities have been sleeping over the matter and have not taken any action. I have all along been bringing to the notice of the House and the Minister, Shri Panday. Of all other talukas Nangunari is the worst famine stricken area. There is a Pachaiyar river there. I have been agitating about Pachaiyar Dam since 1946 in the local assembly.

There is another river Maninuthar here. As desired by the then PWD Minister, Madras State, I collected Rs. 1.25 crores loan from the public. We gave that to the Government. 60,000 acres have been irrigated in addition to stabilisation of one lakh acres under Thanbarani System in 1949.

There was a similar scheme so far as Pachiyar is concerned. I told in the presence of the Chief Secretary of Tamil Nadu in the Government function that I was prepared to collect Rs. 5 crores from the agriculturists and let him implement the Scheme. Why has it not been taken up? My friend Dr. Karunanidhi when he was Chief Minister, with the approval of the Planning Commission and the Engineering Department laid the foundation stone for this Project.

My friend Shri M. G. Ramachandran, the Chief Minister of Tamilnadu said that some sort of monkeys were there beyond 3000 feet. Monkeys are more important for him than the human beings. The dam is is below 3,000 feet. Wild Animal Act is coming into the picture. Finally my friend Shri Swaminathan told me on the floor of the House that he was prepared to deviate from the Wild Animal Act if the State Government was implementing the scheme. Three days back there was a written answer by the Minister for Agriculture here. He said, "The State Government does not want this scheme at all." Shri M. G. Ramachandran has dropped it for ever It was a categorical reply. This kind of thing is there.

In democracy to-day Shri M. G. Ramachandran is the Chief Minister. Tomorrow someone else can be the Chief Minister. The Constitution provides that anybody can be the Chief Minister and the Prime Minister. Simply because Shri Karunanidhi laid the foundation stone, he does not want to implement the scheme. This attitude is wrong.

My friend Shri Rao is here. His colleague Shri Swaminathan one day categorically gave a promise that it was possible to examine and give exemption if Tamilnadu Government wanted exemption from the Wild Animals Act. There is a racket scheme in the same Taluka. Shri Rao has given exemption. Forest has been handed over to the Defence Department. The work is going on above 3000 feet

18 hrs.

The hon Prime Minister one day addressing a huge gathering in a public meeting in Madras announced Krishna River Water Supply Scheme so that acute shortage of water in Madras city is eliminated for ever. Now, my friend, Mr. M. G. Ramachandran, the Chief Minister of Tamil Nadu does not want that scheme. According to him, it is very costly. But he wants to spend crores and crores of rupees for getting water from seasonal rivers. Sometimes the water may come, sometimes the water may not come from such rivers. He wants to implement such a scheme by bringing water from 250 miles away from Madras. But his publicity mouth-piece newspaper is attacking the hon. Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, for not implementing the Krishna Water Scheme. It is for the State to implement it. The Government of India assured. The Prime Minister assured. But he does not want the Krishna water to be utilised for Madras city. At the same time, he is attacking the Prime Minister politically. The Prime Minister assured in a mammoth public meeting that the Krishna water would be given to Madras city.

My friend, Mr. M. G. Ramachandran is always acting double role. Now, politically.

1801 hrs.

[SHRI V. N. GADGIL *in the Chair*]:

Another thing is that the food growing areas, Tanjore and Trichinopalli are drying. Without the approval of the Planning Commission, three dams have been constructed in Karnataka on Cauvery river by a friend of Mr. M. G. Ramachandran, the late Shri Devraj Urs He was the guru of Mr. M. G. Ramachandran. Mr. Kedar Pandey may check up that an amount of Rs. 200 crores has been spent by Karnataka Government without the Planning Commission permission. Even for construction of a small bridge on a national highway, you have to seek permission from the Planning Commission. But, here three dams—Hemavathi, Haringi and Kabini—have been constructed on the Cauvery river in Karnataka. Now, all the dams are full. Fortunately, my friend, Mr. Gundu Rao is letting 22 TMC of water to Tamil Nadu. I have already represented to you. There is plenty of water in the river. Instead of requesting the Centre, Mr. M. G. Ramachandran is politically demonstrating and convening the *bandh* there. During the last meeting of the Cauvery dispute convened by the Government of India, all the other Chief Ministers attended it. But Mr. M. G. Ramachandran had not attended the meeting. This kind of interest, he is showing.

I would now request Mr. Kedar Pandey to request the Chief Minister of Karnataka, Mr. Gundu Rao to release some more water, at least 36 TMC, to the State and save the situation in Tamil Nadu.

Similarly, Andhra Pradesh is affected by drought. So also Rajasthan which is affected worst. About West Bengal also my friend has already explained. So, the Government of India must come forward to help all the States including Tamil Nadu. Sir, the Chief Minister is not bothered about the people. It does not matter. The people are with you. Let us save them by giving water from the river Couvery.

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : सभापति महोदय, प्राकृतिक संकट का मुकाबला यदि इस विज्ञान युग में नहीं कर सकते हैं तो हम कब करेंगे ? यह सबसे बड़ा अहम सवाल हमारे सामने है। सरकार चाहे उधर की हो, या इधर की बने, लोकतंत्रीय पद्धति में जन-कल्याणकारी सरकारें होती हैं। मैं ऐसा कहकर आप पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। लोकतन्त्रीय व्यवस्था कायम होने के पश्चात् हमारे देश में सरकार ने कुछ सफलताएं भी प्राप्त की हैं। अनेक बांधों का निर्माण किया गया है। लेकिन यदि हम अपने पिछले कार्यों के इतिहास को उठाकर देखें तो हमें वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। मैं आप को राजस्थान की एक मिसाल देना चाहता हूं। उदाहरण के लिये आप भीम सागर बांध को ही ले लीजिये। सन् 1942 में उसकी नींव पड़ी थी और आज 1982 साल तक उस का काय पूरा नहीं हो पाया है। फिर आप कहते हैं कि सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। हम फिर किस प्रकार से खेतों के अन्दर पानी पहुंचाएं, कैसे हर खेत को पानी देकर हर हाथ को काम दिलाएं। इस विषय में हमारे पास कोई योजना नहीं है। हमने कभी इस विषय पर चिन्तन नहीं किया, कभी इसे गम्भीरता से नहीं लिया। क्या आप ऐसी किसी योजना के अभाव में सूखे का मुकाबला कर सकते हैं, बाढ़ और आर्थिक संकट का मुकाबला कर सकते हैं।

मैं आपको राजस्थान का ही दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां एक और हरीशचन्द्र सागर पर बांध बनाया जा रहा है। वह भी 1952 में बनना आरम्भ हुआ था और अभी तक उसका कार्य शेष रहता है। बड़ा थोड़ा सा पैसा लगाकर उस काम को पूरा करवाया जा सकता है, लेकिन उसका कोई

चिन्तन नहीं किया जा रहा है ; इसी प्रकार तीसरा मनोहर थाना बांध है, जो कि राजस्थान में बनने वाला है। लेकिन आज तक उसका सर्वे कार्य भी कम्पलीट नहीं हो पाया है, 1962 से वह कार्य आरम्भ किया गया था और अभी तक चल रहा है। इस तरह की हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनायें हैं। यदि आप इतिहास के पन्नों को देखें, सरकार के पिछले कार्यों को उठाकर देखें कि वास्तव में हम कहां खड़े हैं। जबकि दूसरी ओर हमारा विज्ञान आज शुक्र ग्रह की ओर जा रहा है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं, जिनको दुनिया ने ठुकरा दिया है, उठाकर बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी वे उन्नति कर रहे हैं। आप इजराइल का ही उदाहरण देख लीजिये। आज उसको रेगिस्तान में बसा दिया गया है, इसके बावजूद वह आगे बढ़ रहा है और वहां की सरकार सारी दुनिया के देशों को चैलेंज दे रही है। आज उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। दुनिया का वह छोटा सा देश जिसको विश्व ने ठुकरा दिया है, विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे निकल गया है कि सारे विश्व को चैलेंज दे रहा है। चाहे हमारी प्रधान मंत्री उस पर अपना रोष क्यों न प्रकट करें, रूस कुछ भी कहे, अमेरिका अपना रोष प्रकट करे, लेकिन उसको किसी की चिन्ता नहीं है। चाहे उसके ऊपर कोई भी संकट आये। वह किसी के आगे नहीं झुकना चाहता। मैं आप से यह निवेदन इसलिये कर रहा हूं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप किसी प्रकार की चिन्ता मत कीजिये, क्योंकि आज हमारी सारी नदियों का पानी व्यर्थ समुद्र में चला जाता है और अपने साथ हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को भी अपने साथ ले जा रहा है। उस के साथ हर बार करोड़ों मवेशी बहकर चले जाते हैं और करोड़ों मकान गिरते हुये चले जा रहे हैं। हमारे सामने जो संकट आज उपस्थित हो रहा है, चाहे वह बंगाल का संकट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का और चाहे राजस्थान का संकट हो या और कहीं का वह एक ही है। मारनी डैम का उदाहरण ले लीजिए। हमारे जितने भी बांध बनते हैं उनमें जो इंजीनियर्स कार्य करते हैं उनकी कार्यकुशलता के अभाव के कारण ही हमारे देश में बाढ़ें आती हैं। कुल बाधों में से 1/3 भाग बांध ऐसे हैं जिनके कारण हमारे यहां हर बार कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है, वह हमारी जमीनों को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी यहां पर मैंने देश के कितने हिस्सों में बाढ़ या सूखे के कारण नुकसान के आंकड़े जानने के सम्बन्ध में एक स्टार्ड प्रश्न किया था, जिसके उत्तर में राजस्थान का नाम गायब है। इसका मतलब है कि राजस्थान में कोई बाढ़ आई ही नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हू कि मेरे संसदीय क्षेत्र में अटरू, छबड़ा, छिपबड़ोद असनावर, सवाई माधोपुर, मनोहर थाना आदि कई क्षेत्र पानी में डूबे हुये हैं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय वहां पर हैलीकोप्टर से फूड गिरा रहे थे। फिर यहां पर शेजवलकर जी ने स्टार्ड प्रश्न संख्या 182 किया तो उसके उत्तर में कृषि मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया कि वहां के लिये कोई योजना ही बना कर नहीं भेजी गयी है। पहले योजना बनाइये, फिर उस पर विचार किया जाएगा। यानी आदमी कल मर रहा है और आज उसको जिन्दा करने की तैयारी की जा रही है।

यदि आप इन संकटों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको कोई न कोई राष्ट्रीय चिन्तन इस दिशा में करना होगा। तभी हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। सिर्फ प्रशासन की ओर से जैसा उत्तर आपके पास भेजा गया, आपने उसी को उठा

[श्री चतुर्भुज]

कर सदन के पटल पर रख दिया, इस प्रकार से हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिये ज्यादा लम्बे चौड़े विस्तार में न जाकर मैं कुछ बातों पर ही प्रकाश डालना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 35 वर्षों तक यदि हम कुछ करना चाहते तो बहुत कुछ सफलता की ओर बढ़ सकते थे। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि हम सफलता की ओर न बढ़ कर दूसरी ओर जा रहे हैं। वैसे हमारा देश जागृत अवस्था में है। चारों ओर से मांग उठ रही है। पिछले वर्ष हमारे कृषि मंत्री जी जब राजस्थान गए थे तो उस समय वहां पर पीने के पानी का घोर सकट पड़ा हुआ था। वहां पर उनसे हमने निवेदन किया था कि राजस्थान के लिए रिग्स वगैरह की व्यवस्था करवाई जाए ताकि पानी की समस्या का समाधान किया जाए। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि उनकी आज्ञा का पालन किया गया, कितने गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान किया गया। जैसा कि वहां के मुख्य मंत्री का स्टेटमेंट आया है, राजस्थान के अन्दर स्थिति यह है कि 35 हजार गांवों में से 23 हजार गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, सूखे से प्रभावित हैं। कोई योजना उनके पास नहीं है। श्री राम सिंह जी ने राजस्थान के अन्दर नहर के बारे में एक सर्वे कराया था कि कितना घोटाला किया। उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें यह कहा गया कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला दो सौ इन्जीनियर्स ने किया है। उन्होंने माना है कि राजस्थान नहर के अन्दर घोटाला हुआ है। मेरा निवेदन है कि जो हमारी कड़ी मेहनत का पैसा है, जो छोटे और गरीब आदमियों द्वारा हर स्तर पर टैक्स देकर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को देती है। उस का कितना उपयोग होता है। यदि मंत्री महोदय इसकी रखवाली कर लें तो वे सूखे और बाढ़ की समस्या का मुकाबला कर सकते हैं। यदि हमने यह रवैया रखा कि 200 करोड़ रु० का घोटाला होने के पश्चात् भी आपने राजस्थान सरकार से इस बारे में नहीं पूछा, उन दो सौ इन्जीनियर्स को ससपैंड नहीं किया, टरमिनेट नहीं किया तो यह एक परिपाटी बन जाएगी, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। जिस प्रकार देश के साथ गद्दारी करने पर मृत्यु दण्ड दिया जाता है उसी प्रकार की व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। राजस्थान नहर राजस्थान को ही अनाज नहीं दे सकती है, वह सारे देश को अनाज पेट भर कर दे सकती है। इस योजना को यदि आपने ठीक ढंग से नहीं लिया तो आप प्राकृतिक विपदा का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

यह मांग बहुत पुरानी है कि पशु-पक्षियों का बीमा करवा दिया जाए। मुझे इस बात का दुःख है कि जो सारे देश को अनाज खिलाते हैं, उनके खेतों की फसल का कोई बीमा नहीं है। केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है।

श्री रामप्यारे पनिका : किसान प्रीमियम कैसे देगा, इस बारे में सुझाव दीजिए।

श्री चतुर्भुज : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मवेशियों का बीमा करना चाहिए। बीमे को आप कम्पलसरी कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है किसान ही आपको देगा। मोटर एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट और हवाई जहाज एक्सीडेंट पर आप एक-एक लाख रुपया देते हैं।

मैं आपसे पूछता हूं कि सूखाग्रस्त और बाढ़ग्रस्त से जब खेतों की फसल चौपट हो जाती हैं, तब आप उनको क्या देते हैं। मुआवजे के रूप में जो आप उनको रकम देते हैं वह है 300 रु० । तीन सौ रुपए में क्या होता है। पेड़ की छांव में वह अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। अभी हमारे प्रदेश के संसद सदस्य मंत्री बने हैं, श्री अशोक गहलोत, उनका स्टेटमेंट है कि रोहतक गांव के अन्दर आदिवासी घास की रोटी खा रहे हैं। यह तीन दिन पहले का स्टेटमेंट है। यह आपकी सरकार का स्टेटमेंट है। मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर यह जो आपकी कोआप्रेटिव सोसायटीज चल रही हैं ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं। कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। आप इनमें से बेईमान आदमियों को चुनिए और उनसे निबटिये। अगर आप उनसे नहीं निबटेंगे तो कोई भी आपकी योजना पूरी नहीं होगी।

मैं एक बीज के वितरण के बारे में मंत्री जी से निवेदन करूंगा। जो यह शंकर ज्वार बीज है इसको लेकर राजस्थान विधान सभा में भी हंगामा हुआ था। यह बीज अनुवरक बीज है। इसमें साठ प्रतिशत भी उर्वरक शक्ति नहीं है। आपके केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने भी यहां से आदेश दिये कि इन बीजों को वितरित कर दिया जाए। इन बीजों का उपयोग करने से किसानों की फसल रह गयी है। ऐसी स्थिति में आप कैसे सूखे का मुकाबला करेंगे ?

फसल बोने के लिए आप किसान को दो घंटे भी बिजली नहीं देते हैं। आपके जो अधिकारी, इंजीनियर लोग हैं ये आपको सब से बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये ही बिजली का संकट पैदा कर रहे हैं। राजस्थान के अन्दर अगर आप बिजली नहीं देंगे तो आप वहां सूखे पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हमने 18 हजार गांवों को बिजली दे दी है। लेकिन आप जरा पता कराओ कि किस-किस गांव में बिजली पहुंची है। ट्रांसफोरमर गांवों में पहुंचा दिये हैं लेकिन किसी भी गांव को इलेक्ट्रिफाई नहीं किया गया है। एक गांव के अन्दर कनेक्शन नहीं गया है। ट्रांसफोरर्मर देकर कारपोरेशन ने फाइल पूरी कर ली है। किसी गांव में बिजली नहीं पहुंची है। फिर आप सूखे से कैसे मुकाबला करेंगे। इसलिए मंत्री जी इस सब पर गंभीरता से विचार करें। अगर आप राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचेंगे तभी आप इस संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा हम भाषण देते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, देश की जनता ऐसे ही कराहती आगे चलती रहेगी लेकिन उससे सूखे के संकट का मुकबला नहीं होगा।

MR. CHAIRMAN: Before you proceed, I would like to state that there are 30 names here. Now it is left to each one of you to decide. If you go on speaking, we have to sit till 12 midnight. My request would be that if you want to conclude it earlier, on eshould not exceed the time.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान प्रांत पांच वर्ष से अकाल से प्रभावित है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वहां के 16 हजार गांव चार वर्ष से प्रभावित हैं, 5 हजार गांव गत पांच वर्षों से प्रभावित हैं और दूसरे गांव कोई दो-साल से और कोई तीन साल से प्रभावित हैं। इस प्रकार की स्थिति वहां है। इस तरह से हर वर्ष वहां लगातार कंटीन्युसली अकाल पड़ रहा है। इस वर्ष का अकाल तो पश्चिमी राजस्थान के लिए, रेगिस्तान के लिए, इस शताब्दी का सब से भयंकर अकाल है।

[श्री वृद्धि चन्द जैन]

इस सूखे का मुकाबला करने के लिए राजस्थान सरकार की क्षमता नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने 20 जुलाई से कार्य बन्द कर दिये हैं और 20 जुलाई के बाद भी सूखे की स्थिति बनी हुई है। अगस्त, में, सितम्बर में कोई अनाज पैदा नहीं हुआ है। इसके ऊपर से सूखा आ गया। फसलें नष्ट हो गई हैं और अभी तक कोई राहत कार्य नहीं चल रहे हैं। पहले भी अकाल था तो राहत कार्य सितम्बर में भी चले, अक्तूबर में भी चले, लेकिन अब राहत कार्य न चलने से बाड़मेर जिले की स्थिति यह है कि 15 हजार किसान और मजदूर वहां से कूच करके अन्य क्षेत्रों में चले गए हैं, हरियाणा में चले गए हैं, पंजाब में चले गए हैं, गंगानगर में चले गए हैं, राजस्थान नहर में चले गए हैं, गुजरात के कच्छ में चले गए हैं। यह स्थिति हमारे क्षेत्र की है। राजस्थान सरकार ने इस बात की मांग की थी कि मार्च, से लेकर सितम्बर तक हमें जो राशि दी जाए वह 71 करोड़ रुपए दिए जाएं, क्योंकि इन दिनों लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि इस समय एक ही फसल होती है। इसलिए स समय ज्यादा मजदूर लगाने पड़ते हैं इसलिए हमें अधिक मदद की जाए, परन्तु अध्ययन दल ने क्या किया ? 20 करोड़ 13 लाख रुपए की सीलिंग लगाई। नवम्बर से लेकर मार्च तक 23 करोड़ 13 लाख की सीलिंग लगाई, परन्तु जब ज्यादा जरुरत थी, उस समय 20 करोड़ 13 लाख की सीलिंग लगाई। अध्ययन दल को स्थिति की कुछ जानकारी नहीं है। आप पिछले दस वर्ष के आंकड़े देख लीजिए कि मजदूर किस समय ज्यादा लगते हैं। मजदूर गलते हैं मार्च, से लेकर जुलाई तक और मई-जून में सबसे अधिक मजदूर लगते हैं। कभी-कभी तो 10–10 लाख तक इनकी संख्या हो जाती है। राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए उसने 30 जुलाई, को एकदम आदेश दिया कि राहत कार्य बन्द कर दिए जाएं और वें कार्य ऐसे बन्द हुए जो अधिकांश अधूरे थे। कहीं ग्रेवर नहीं हुआ है। ग्रेवर नहीं हुआ है तो पहले का जितना काम हुआ है वह सब बेकार हो जाएगा। करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं था, इसलिए वह स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकी। इस स्थिति में, भयंकर अकाल की स्थिति में अगर आप मदद करना चाहते हैं तो अभी से मदद देना शुरु करें, क्योंकि मार्च से लेकर सितम्बर तक 58 करोड़ रुपया कुल खर्च दिया है, 20 करोड़ रुपया उसको मिल गया है, अगर 38 करोड़ रुपया और उसको आप पहुंचा दें तब तो स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है, कुछ नेथ नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह 38 करोड़ रुपया दिया जाए, नहीं तो स्थिति डावांडोल हो जाएगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पशु मर रहे हैं। जैसलमेर में कुछ घास हुआ है, कुछ उस तरफ चले गए हैं, परन्तु दो महीने बाद वहां भी घास नहीं होगा और भयंकर संकट का सामना करना पड़ेगा। पशुओं को बचाने का प्रश्न राजस्थान सरकार के लिए बड़ा कठिन होगा। अभी भी चारा इतना महंगा है कि दो किलो चारा 2–2 रुपए में बिक रहा है। चारे के बारे में यह व्यवस्था करें कि जहां चारा हुआ है वहां पर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडीचर रेलवे डिपार्टमेंट

वहन करे, तब जाकर सब्सीडाइज्ड होकर के चारा हमको मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। तीन महीने में स्थिति यह होगी कि पशुओं को बचाने के लिए रेलवे से मालगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट कर के चारा भेजना पड़ेगा, तब इन मवेशियों को बचाया जा सकता है।

मार्जिन मनी 1-4-79 से पहले 10.19 करोड़ हुआ करता था जिसको उसके बाद घटा कर 7.74 करोड़ कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इसका क्या कारण है। मजदूरों को रिलीफ देने वाली यह सब से बड़ी आइटम होती है। इस को न जोड़ने का संबंध फाइनेंस कमिशन ने निर्णय लिया था। आठवें फाइनेंस कमिशन के सामने इसके बारे में आपकी तरफ से प्रार्थना जानी चाहिये कि मजदूरी का एलीमेंट एम्प्लायमेंट में सब से महवपूर्ण एलीमेंट होता है, इसके बिना लोग बच नहीं सकते हैं, इस वास्ते इस पर वह विचार करे। इसके बारे में मेरी भी उससे यही प्रार्थना होगी। लोगों को बचाने का यह प्रश्न है। अगर आप राज्य सरकार की इस में पूरी तरह मदद नहीं करेंगे तो लोग बच नहीं सकेंगे।

मजदूरी जो आज पांच रुपये दी जाती है मजदूरों को यह बहुत अपर्याप्त है और इसको सात रूपये किया जाना चाये

ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्ज को भी हाथ में लिया जाना चाहिये। आपको हर साल टैंकर्ज में पानी पहुंचाना पड़ता है और इस पर आपका बहुत खर्च भी होता है। मैं समझता हूं कि इसके वास्ते आपको मिलिटरी की व्यवस्था भी टैंकरों के साथ साथ करनी पड़ेगी। ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हो इसके लिए आप रिजनल पाइप लाइंज की व्यवस्था करे, ड्रिल्ज की व्यवस्था करें।

राजस्थान कैनाल का जो दूसरा फेज है इसको छठी योजना में पूरा किया जाना चाहिये। लिफ्ट कैनालज के बारे में मेरा कहना है कि इसको मंजूरी देकर हमारे क्षेत्र में पीने के पानी का तो कम से कम राजस्थान कैनाल से आप प्रबन्ध कर दें। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि में अगर आप पीने का पानी नहीं पहुंचा सके तो आप किसी भी महत्वपूर्ण समस्या को हल नहीं कर सकेंगे।

घग्गर से भयंकर बाढ़ आती है और बहुत सा पानी वेस्ट हो जाता है। काफी गांव भी उस कारण तवाह हो जाते हैं। इसकी बैड पर एक कैनाल बना कर उसके पानी का सदुतयोग किया जाना चाहिये ताकि वह पानी वेस्ट न हो।

इस मामले में केन्द्रीय सरकार की बहुत भारी जिम्मेदारी है और उसको यह जिम्मेदारी वहन करनी पड़ेगी। जल्दी अध्ययन दल भेजा जाना चाहिये और राजस्थान सरकार की जो 38 करोड़ की मांग है, उसको पूरा किया जाना चाहिये। राहत कार्य शुरू किए जाएं। आज स्थिति यह है कि दो दिन में एक दफा ही लोगों को खाना मिलता है और घास तक वे खाने लग गए हैं। इस भयंकर स्थिति से उनको बचाने के लिए राजस्थान सरकार की आप को पूरी सहायता करनी चाहिये।

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : मंत्री महोदय ने जो चार अक्तूबर को वक्तव्य दिया था अकाल के बारे में उसको पढ़ कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जिन प्रान्तों में अकाल की स्थिति है उनके नाम उन्होंने दिए थे। वैस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के नाम उन्होंने लिए थे लेकिन

[श्री भोम सिंह]

राजस्थान जोकि उनका पड़ोसी प्रान्त है, उसको बिल्कुल नजरंदाज़ कर दिया था। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने 2-8-82 को पार्लियामेंट के अन्दर ही अनस्टार्ड क्वेश्चन नम्बर 3729 का जो जवाब दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि राजस्थान में प्री मानसून में 87 लाख हैक्टर ज़मीन क्राप बरबाद हुई है, पोस्ट मानसून में 74 लाख हैक्टर ज़मीन की फसल बरबाद हुई है। इसी तरह पापुलेशन जो एफेक्टिड हुई उसकी फिगर्ज़ इन्होंने 167.71 लाख और 199.21 लाख बताई थी। इसी तरह से उन्होंने पशुओं की गणना भी की थी। प्री मानसून में 413 लाख कैटल और पोस्ट मानसून में 275.81 लाख कैटल की संख्या उन्होंने बताई थी। जब इतनी सारी फिगर्ज़ उन्होंने राजस्थान के बारे में बताई थीं तो राजस्थान कैसे उनकी नजर से बच गया, मैं समझ नहीं पाया और इसका मुझे अफसोस है और इस पर ताज्जुब भी है।

अब मैं कहना चाहता हूं कि करोड़ों रु० का नुक्सान फसलों का अकाल में होता है, बाढ़ के अन्दर धन जन और पशु समाप्त होते हैं। मैंने पिछले साल ड्राउट की बहस पर बोलते हुए कहा था कि अकाल, सूखा और बाढ़ को फेस करने के लिये पांच साला योजना की तरह एक लोंग टर्म प्लानिंग बनायी जानी चाहिये। मैंने सुझाव दिया था कि सूखा और बाढ़, दोनों मानसून से जुड़े हुए हैं। किसी जगह बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ गया और किसी जगह अधिक बरसात हो गई तो बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से खास कर गंगा और यमुना नदियों से काफ़ी तबाही होती है, और आगे जा कर उसकी सहायक नदियां तबाही मचाती हैं। तो भारत सरकार ने कुछ वर्षों पहले एक स्कीम बनाई थी कि यमुना के पानी को डाइवर्ट किया जाय और भरतपुर, अलवर के अन्दर सिंचाई के लिये उस पानी को दिया जाय। इसी तरह से गंगा के पानी की स्कीम थी कि उसको झुनझुनू, सीकर, चूरू नागौर, जोधपुर और बाड़मेर को divert करके पानी दिया जाना चाहिये। वह स्कीम बन तो गई लेकिन अभी तक फाइलों में ही बन्द है। अगर राजस्थान के सूखे इलाके को पानी दे दिया गया तो जो यू० पी० और बिहार में गंगा और यमुना महाप्रलय कर देती हैं उससे बचा जा सकता है और राजस्थान में सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी। जिस प्रकार बिजली में ग्रिडिंग सिस्टम है वैसे ही नदियों का भी ग्रिड बनाइये ताकि बरबादी से बचा जा सके।

फेमीन पानी की कमी से आता है। जब बरसात फेल हो गई तो अकाल हो गया। तो जहां जहां नहरें दे सकते हैं वह दीजिये, और जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा राजस्थान कैनाल देश की सबसे बड़ी योजना है और इस योजना को 25 साल हो गये बने लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पायी है और 200 करोड़ रु० की कमी है जो आप राजस्थान कैनाल के लिये खर्च करने को नहीं दे रहे हैं। जब कि 2,000 करोड़ रु० आप एशियड पर 15 दिन में खर्च कर देंगे, जैसे दिवारी में बच्चे पटाखे चला कर पैसा फूंक देते हैं इसी तरह से एशियन गेम्स 15 दिन में खत्म हो जायेंगे जिस पर 2,000 करोड़ रु० खर्च हो रहा है, लेकिन राजस्थान कैनाल को पूरा करने के लिये आप पैसा नहीं दे रहे हैं।

पिछले वर्ष मैंने कहा था कि राजस्थान के अन्दर बहुत सी जगह अन्डरग्राउन्ड

वाटर पोटेंशियल है जैसे झुनझुनू और सीकर में 50,000 गैलन अन्डर ग्राउन्ड वाटर पोटेंशियल है, इसी तरह दूसरी जगह 1 लाख गैलन वाटर पोटेंशियल है तो आप इस पानी को निकालने के लिए क्यों नहीं ट्यूववैल Corporation बनावाते ? अगर यू० पी०, हरियाणा और पंजाब में हो सकता है तो राजस्थान को क्यों नहीं बाध्य करते हैं कि वह भी ट्यूववैल कोरपोरेशन बनाये। काश्तकार तो ट्यूववैल नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनकी होल्डिंग छोटी हैं। लेकिन सरकार को बना सकती है, और जिस प्रकार से कैनाल का पानी आबपाशी चार्ज लगा कर देते हैं उसी तरह से ट्यूववैल का पानी भी किसानों को दीजिये, चार्ज कीजिये पैसा उसके लिये, ताकि सिंचाई हो सके।

अब अकाल पड़ रहा है, दूसरा अकाल यह पड़ने जा रहा है, क्योंकि खरीफ की फसल तो बरबाद हो गई, रबी की बोवाई का समय आ गया है वह भी बरबाद हो जायगी। बिजली की बहुत कमी है, और आपने खुद कहा है कि बिजली की शौर्टेज है और रबी की फसल में बहुत परेशानी होगी। कृषि मंत्री जी ने मुझे सेन्ट्रल हाल में कहा था कि आपने हिदायत भेज दी है कि 24 घंटे बिजली दी जाय। मैं समझता हूं कि हिदायत पूरी होने वाली नहीं है। 24 घंटों की बजाय अगर 8०10 घंटे भी आप बिजली काश्तकार को दे दें तो हम बहुत आभारी होंगे और आपको बधाई देंगे। आप उसकी व्यवस्था कीजिये। अगर आप नहीं भी दे सकें तो आप सब स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को बाध्य कीजिये कि वह कितने घंटे बिजली अपनी अपनी स्टेट्स में देंगे, यह एनाउन्स कर दें ताकि काश्तकार बिजली जितनी मिलने वाली है उसके मुताबिक वह अपनी प्लानिंग कर सके। जो पैसा किसान आज इन-पुट्स पर खर्च कर देगा, अच्छे बीज और फर्टिलाइज़र पर कर देगा और आप उसको बिजली नहीं देंगे तो वह क्या करेगा ? आप इस तरह से क्यों उसको लूटना चाहते हैं ? उसके पास जो पैसा है, उसको आप क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। आप फर्म कमिटमेंट दीजिये कि इतने घंटे बिजली देंगे। मेरा भी निवेदन है कि दिन में उसको बिजली दीजिये।

मुझे खुशी है, हमारे मोती भाई ने यहां कहा है कि गुजरात गवर्नमेंट एनाउन्स किया है कि दिन में बिजली देंगे। आप काश्तकारों को राजस्थान और हरयाणा में रात को देते हैं। रात को जब वह काम करता है तो क्यारी टूट जाती है, पानी बर्बाद हो जाता है, उसको खुले में काम करना होता है। जब कि इंडस्ट्रीज़ शैड में चलती है, उनको रात में बिजली देंगे तो उनका नुकसान नहीं होगा।

आपके फैमिन में रुपये की बर्बादी बहुत होती है, पिलफ़ेज भी बहुत होता है, अफसर पैसा खा जाते हैं। भारत सरकार का पैसा प्रापरली यूटिलाइज़, नहीं होता है, उसका बहुत बड़ा भाग खराब जाता है।

काश्तकारों को बीज देने के बारे में एक छोटी सी मिसाल मैं अर्ज करना चाहूंगा। राजस्थान में टी–59 का बीज कोटा का था जो कि इस साल का तैयार हुआ था। उस बीज को अगरे और यू० पी० के लिये भेज दिया गया। जोधपुर में टी–59 का बीज पिछले साल का तैयार था वह राजस्थान को दिया जा रहा है। आप राजस्थान और यू० पी०

[श्री भीम सिंह]

के काश्तकार में अन्तर क्यों कर रहे हैं ? राजस्थान के काश्तकार को भी ताजा बीज दीजिये ताकि उसकी बर्बादी न हो ।

बिजली ब्लड लाइन है । जैसे ब्लड हार्ट में नहीं जायेगा तो आदमी मर जायेगा । इसलिये काश्तकार को बिजली न देकर मारिये मत । बिजली की उसके लिये व्यवस्था कीजिये । अगर आप व्यवस्था न कर सकें तो उसे ना कर दीजिये कि हम नहीं दे सकते तो कम-से-कम वह अपना पैसा खर्च कर के बर्बाद तो नहीं होगा ।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति महोदय, बाढ़ और अकाल का प्रकोप हमारे देश के लिये कोई नया नहीं है । सदियों से इस देश में बाढ़ आती रही है और अकाल पड़ते रहे हैं, लेकिन सबसे गम्भीर मामला इस बात को लेकर अब हो गया है कि पिछले अनेक वर्षों से बाढ़ और सूखे का पैटर्न बदल गया है । वैसे तो बाढ़ और सूखा इस बड़े देश में किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष आते रहे हैं लेकिन एक बड़े एरिये में और थोड़े अन्तर देकर बाढ़ और सूखे का आना यह एक नई बात है । इसके बारे में हमको गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

1978 में भयंकर बाढ़ देश के कुछ भागों में आई, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में, उसके बाद यह बाढ़ लगभग उतनी ही विभीषिका से 82 में आ गई । 1979 में सूखा पड़ा देश के बड़े भाग में, जिसमें बहुत से राज्य प्रभावित थे और इस समय 82 में फिर यह सूखा पड़ गया है ।

इसका मुस्तकिल हल वैसे हो, अभी तक कोई हल निकला नहीं और बर्बादी बराबर हो रही है । मैं समझता हूं कि अब तक बाढ़ और सूखे से जितनी बर्बादी हो चुकी है और उसके लिये जितना रुपया राज्य सरकारों को बांट दिया गया है, लोगों को दे दिया गया है, अगर उतना रुपया पहले ही लगा दिया गया होता तो बाढ़ की रोकथाम अवश्य ही की जा सकती थी, लेकिन यह नहीं हुआ । सरकार को इस मामले में गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए ।

सभापति जी, अब हालत यह हो गई है कि सारा उत्तर प्रदेश भयंकर बाढ़ और भयंकर सूखे की चपेट में आ गया है । मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं और मेरे जिले के 500 से भी अधिक गांव जलमग्न हैं, महरूम हैं और बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं । वहां पर खरीफ की पूरी की पूरी फसल बरबाद हो गई है । इसी तरह, कुछ भागों में पानी न बरसने के कारण भयंकर सूखा पड़ रहा है । समस्त उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में वही हालत है, जैसी प्रदेश के पश्चिमी जिलों की है । सारा प्रदेश बाढ़ और सूखे की चपेट में आने के कारण तबाह हो गया है । अब हालत यहां तक पहुंच गई है कि 12 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में, जहां 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गरीबी की रेखा के नीचे रहता है, जहां लैण्डलैस मजदूर हैं, उनकी बहुत बड़ी फौज है, उन सब को काम चाहिए । यदि हम उनको काम नहीं देंगे तो उनको खुराक नहीं मिलेगी । पीछे जब 1979 में वहां सूखा पड़ा था तो उस समय "काम के बदले अनाज योजना" काफी कारगर साबित हुई थी । आज मैं उस योजना की तारीफ करना चाहता हूं कि 1979 में उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ने से जो "काम के बदले अनाज योजना"

चली थी, उसके कारण लोगों को काफी मदद मिली थी। लेकिन आज सभापति जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और इस बात को कहने में अपना कर्तव्य समझता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कहां गई। अभी यहां पर कृषि मंत्री जी सिर हिला रहे थे, जब विरोध पक्ष के लोग कुछ कह रहे थे। लेकिन उन को कागजों में जो आंकड़े लिख कर दिए जाते हैं, उसके कारण खजाने से कितना पैसा चला जाता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन सभापति जी, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आपकी यह योजना अभी धरती पर नहीं उतरी है। वास्तविकता यह है कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाईये, मेरे अपने जिले में एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनाई गई है। मैं बनारस की बात जानता हूं, वहां पर एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी है। उत्तर प्रदेश के किसी जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नाम की कोई योजना धरती पर नहीं उतरी है, कागजों में भले ही उसे दिखाया गया हो। अब यदि वहां किसी स्थान पर बाढ़ के पानी के चले जाने या सूखा पड़ने की वजह से बुआई नहीं हो सकती तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजली आप तीन-चार घण्टे से ज्यादा दे नहीं रहे हैं, नहरें चल नहीं रही हैं, ट्यूबवैल चल नहीं रहे हैं, आखिर लोग खायेंगे कैसे? आपकी योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। मेरे गाजीपुर जिले के बारे में, जिला प्रशासन ने साढ़े नौ करोड़ रुपये की, बहुत कम की योजना बना कर भेजी है, लेकिन उसकी आज तक स्वीकृति होकर नहीं गई है। कृषि मंत्री जी, आप एक वैलकनी के ऊपर बैठे हुए हैं। यदि आपने अभी फिक्र नहीं की और गम्भीरता-पूर्वक इस मामले को नहीं लिया तो यह वैलकनी फट जाएगा। इसलिए आपको इस बात पर विचार करना चाहिए।

राजस्थान के बारे में यहां पर बात कही गई। राजस्थान के साथियों के साथ हमारी हमदर्दी है। बंगाल के साथियों के साथ हमारी हमदर्दी है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के 12 करोड़ लोग भूखे रह जाएंगे तो आप देश के दूसरे हिस्सों से अनाज मंगाकर कैसे उत्तर प्रदेश को खिला पाएंगे। आज उत्तर प्रदेश अपने खाने भर अनाज पैदा कर लेता है तभी आप देश के दूसरे भागों को पंजाब और हरियाणा से अनाज ले जाकर खिला सकते हैं। यदि उत्तर प्रदेश में भी अनाज पैदा नहीं होगा तो आप वहां के 12 करोड़ लोगों को कैसे, कहां से खिलायेंगे। आप इतना अनाज कहां से लायेंगे, क्या करेंगे। इसलिए इस गम्भीर सवाल पर आपको ध्यान देना होगा। फिर राजस्थान का क्या होगा। फिर बंगाल का क्या होगा, और दूसरे राज्यों को आप कैसे अनाज दे सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : बिहार के बारे में भी कहिए....

श्री जैनुल बशर : बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए में कहना चाहता हूं कि समय बहुत कम है और इस पर जोर देना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के नाम पर य काम के बदले अनाज योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर काम शुरु करिए, बड़े पैमाने पर लोगों को राहत दीजिए, काम दीजिए ताकि उनकी जीविका चल सके, वे अपने पेट भर सकें, अनाज खरीद सकें और खा सकें।

[श्री जनुल बशर]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप बिजली की व्यवस्था किसानों को युद्धस्तर पर कीजिए। यदि आप बिजली की व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपकी रबी की बुआई नहीं होगी क्यों कि हमारे यहां बिजली से ही पम्प चलते हैं, ट्यूबवैल चलते हैं और किसानों के पास जो निजी नलकूप हैं, वे तभी चल सकते हैं, जब आप उनके लिए बिजली की व्यवस्था करेंगे। इसलिय बिजली की व्यवस्था करिए। खाद पर सब्सिडी दीजिए, बीज पर सब्सिडी दीजिए। बड़े पैमाने. पर राहत कार्य करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की मदद करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि चार या साढ़े चार करोड़ रुपए की मांग उत्तर प्रदेश की सरकार से आई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको अधिक से अधिक रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी ओवरहाल एबेलेबिलिटी को देखते हुए देना चाहिए। यदि आप उत्तर प्रदेश को नजर अन्दाज करेंगे तो आप समस्या को सुलझा नहीं पायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Again I request Members: please be brief. Stick to your region. I am sure the Minister will consider all aspects. It will be easy for me to accommodate a maximum number of Member. I have got a list of 30.

Now Prof. Parashar.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): The country is in the grip of severe drought, and the extent to which it is suffering has been indicated by the various speakers earlier. The various States are there; and about my own State, it is ironical that Himachal Pradesh should be suffering from drought. But in fact it is very sad situation. And the result is that more than the loss of the crops, it is the spectre of starvation that is haunting the people at the moment. The State Government has been doing its bit, but it is not possible for the State Government, with meagre resources, to rise to the occasion. We are in the fortunate position that the present Minister for Agriculture has been well conversant with more than half of the area which at present constitutes Himachal Pradesh; and he has been touring these areas when he was Minister in the Punjab Government. As he would bear me out, the districts of Kangra, Hamirpur, Mandi and Solan are the worst-affected districts. And even the scanty rain-fall has caused the water level to be very low, and the result is that the hydel generation is not upto the mark. Therefore, our State has to suffer.

Most often, what happens is that the projects for the conservation of the soil, for checking soil erosion are not there. And in this connection, our State had forwarded one scheme to the Ministry of Irrigation; and fortunately Mr. Kedar Pandey is sitting here. It is known as the small channelization scheme. With the help of the World Bank, it could harness a good deal of the area, and reclaim it for proper cultivation. At the moment, the crops are ruined, and the loss is estimated roughly to be to the tune of Rs. 45 crores to Rs. 50 crores. And the result is that people are even afraid that not only the crops are not there, but even the fodder problem is being to stare us in the face.

The Chief Minister has toured the area in one district, *viz.* Kangra, he visited some blocks and he found that Rs. 10 crores is the worth of crops that have been lost. In Hamirpur, it is Rs. 5 crores.

In most of the irrigation schemes, the waters are flowing out of Himachal Pradesh, towards Punjab and Haryana. It is an irony of fate that the State which is flowing its rivers through other States, which is sending its rivers to the other States, is itself suffering. Now, we have the anomaly that the Bhakra Manafement Board is asking us to pay charges for lifting one cusec of water and to pay

Rs. 21 per day for this. This is very strange that the rivers belong to the State, and the water has to be lifted to greater height now, because the sources have gone dry, and contours have been broken and earlier arrangements for irrigation by small farmers have lost their shape; and now they are in a hopeless mess. Even drinking water sources have gone dry, and soil erosion has done heavy damage. Water from one river, Beas has been diverted into Sutlej. The result is that there is prosperity for Punjab and Haryana, and some hope for Rajasthan. But for Himachal Pradesh, it is ruin, because roads have increased, distances have increased and the contours have increased. And the result is that the entire pattern of cropping has changed, the climate has changed, and the State is in the grip of a severe man-made disaster. For this purpose, therefore, I request the hon. Minister for Agriculture who is well conversant with the area, to come to the rescue of the State, and offer atleast asistance of Rs. 20 crores to the State Government immediately, because, otherwise, if the schemes are not inttiated right now, not only the people will starve but also there would be a resentment of a very acute order.

Formerly, we were employed in the army and we had, you can say, about 10 per cent of our people, recruitable population was there in the army. That quota has been reduced to only 1 per cent. So, the State has lost a big chunk of the source for employment. On the other hand, a dam which was being constructed has been completed and the labourers and the workmen who were working there have been rendered surplus; and no new dam have been constructed. So, new schemes which were there for hydro-generation, for irrigation and for circulation should be immediately sanctioned and taken up.

Secondly, what I have been emphasising is that now this is an annual feature in the part of the country or another, in one part of the State of another. Drought is there, relief is there, snow-storm is there and hailstorm is there. So, why not have a permanent natural calamity relief arrangement, some mechanism which can immediately go into operation? Why wait for the Central team? It will take its own time. Why wait for the revenue authoties—Patwari or the Lokpal whom you call the revenue authorities or officials? He will go from village to village, from field to fieled and by the time the statisties are collected, the time for relief is gone. I emphasise again, that the Ministry of Agriculture should rise to the occasion; and it is in the fitness of things that a permanent machinery, mechainsm is evolved with its headquarters at the State Capital so that whenever there is some sort of natural calamity—may be flood, may be snow-storm, may be drought—immediately it goes into operation, assessment is made and relief is provided....

For my own State, Himachal Pradesh, I would plead with the Minister to be very liberal because he has been very much personally conversant with the problems and that alone can save us.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): Mr. Chairman, floods and drought are equally important national problems of the country. Very often, North has been affected by floods and South is very frequently affected by drought. In Tamil Nadu, out of 16 districts, about 11-12 districts were affected by drought. In Tamil Nadu we are facing a very serious crisis due to failure of monsoon and drought conditions. In fact, famine is prevailing in Tamil Nadu. But the Government of Tamil Nadu and the Chief Minister of Tamil Nadu are fiddling with cinema people while Tamil Nadu is burning with drought and famine situation.

Now I am glad to hear that the West Bengal Government has sent its report demanding a certain amount of relief money and foodgrains to be despatched to the West Bengal Government. So far as my Government is concerned, I am afraid, I am very reasonably doubtful, the State Government of Tamil Nadu has not assessed or estimated the drought situation in Tamil Nadu; it has not yet accounted for the extent of damage caused by the

[Shri K. Mayathevar]

drought situation in Tamil Nadu it is too late on the part of Government of Tamil Nadu to proceed further. They have not sent any report to the Central Government. I urge the Central Government to ask the Tamil Nadu Government to appoint a State Committee for assessing the damage and prepare an estimate and send it to the Central Government. I am aware the Central Government is prepared to help and grant more and more money towards drought relief for the State but the State Government is not prepared to come with the demand to the Central Government to get things done. That is why, we, the people of the Tamil Nadu, are in great suffering, trouble and difficulties. We do not have drinking water in Madras city.

At the time of DMK rule from 1968—1975, the then Chief Minister of Madras, Mr. Karunanidhi evolved a scheme for getting water from Veeranam; and the then DMK Government spent nearly Rs. 28 crores to bring water; 50 per cent of the work has been executed. But then in 1977 when the ADMK Government came to power, it was dropped and suspended once for all because of the actual fact that it was initiated undertaken and partly done by the Karunanidhi Government. If Veeranam project was executed there would not have been any water problem or scarcity of water in the Madras city. I, therefore, request the Irrigation and Agriculture Ministers of the Government of India to instruct the present Government of Tamil Nadu to take up the Veeranam project immediately and to complete it quickly so that the problem of drinking water in Madras city can be solved.

We wanted more water from Karnataka. We wanted the Karnataka Government to supply more water in order to irrigate one and a half million acres of paddy fields in the districts of Thanjavur and Trichinopalli which are fertile lands for producing more and more paddy. We requested the Karnataka Government to release 36 CMT of water for Trichinopalli and Tanjore districts. But it was not done by the Karnataka Governments. I am very grateful to the Agriculture Minister, Rao Birendra Singh, who has spoken about this recently in the Rajya Sabha, a few days ago. I also express my thanks on behalf of the people of Tamil Nadu.

An agreement was entered into between the Governments of Tamil Nadu and Karnataka in the year 1892 and again in 1924. Those agreements have to be acted upon by the Karnataka Government.

The Central Government convened a Conference of the Chief Ministers to discuss the water supply problem. The Chief Ministers of Karnataka, Kerala and Pondicherry Governments came and attended, but not the Chief Minister of the Tamil Nadu Government, Shri M. G. Ramachandran. He was otherwise engaged with the cinema people. Therefore, it is better even to dislodge the Government in Tamil Nadu and save the people of Tamil Nadu. The Chief Minister is busy with the cinema people. He has got no time to spare for the people of the State. I was the first M.P. to be elected from that Party. I have now come to DMK, the people's Party, or the party of the leaders of the people, the DMK Party.

Tomorrow the ADMK Government is organising a *bandh*. What is the propriety of the Government of Tamil Nadu to organise a *bandh* against the Central Government? For the Chief Ministers' Conference the Chief Minister did not come, but he accuses the Central Government that it has not helped the State Government! The Central Government should take up the matter with them.

Regarding the supply of foodgrains by the Government of India, on 11th October, in reply to a Qustion the Minister of State told us that the State Government was demanding about 1,90,000 tonnes of foodgrains and that the Central Government had granted about 1.68,000 tonnes. It appears that the State Government had not cleared that stock. In another answer to my question, the hon. Minister of State mentioned that the State Government demanded 85,000 tonnes of rice of wheat and said that he was supplying 35,000 tonnes. All the foodgrains

supplied by the Central Government for distribution through the fair price shops are being diverted to the Chief Minister's Mid-Day Meal Scheme for Children. Kindly note it. I am not talking any falsehood. Your Minister of State, Mr. R. V. Swaminathan, was defending the State Government. I am very sorry to say that. He must understand that he is a Minister of this Government. MGR is levelling charges after charges that you did not supply any foodgrain at all to the State Government.

19 hrs.

The Health Minister of Tamil Nadu, Mr. Hande, said on October 9 that not even a grain of rice was supplied by the Central Government to the Tamil Nadu Government. This is the speech given by the Health Minister. It was followed by the Finance Minister of the State. It was endorsed by the Chief Minister in the Assembly. It was further endorsed by the Revenue Minister, Mr. S. D. Somasundaram. I want more supply of foodgrains whatever may be the things. I am pleading for more and more despatch of foodgrains to the State.

All your central schemes like Food for Work scheme, IRDP, National Rural Employment Scheme, for which the Central Government is spending so many crores and allotting so many tonnes of foodgrains have been diverted and diluted. MGR boils and cooks in a pot and re-shapes his own scheme called 'MGR's children nutrition food scheme'. It should be noted by the Government.

MR. MGR, the Chief Minister of Tamil Nadu, purchased a helicopter last year for Rs. 80 lakhs. The maintenance charges of that are Rs. 1 lakh every month from the exchequer of the Tamil Nadu Government. What for has he purchased that helicopter? To visit the State whenever it is affected by floods. Where is the flood now? ** Is it necessary for the Chief Minister of Madras, when there is no rain or flood, to purchase a helicopter in order to inspect, supervise and visit the State? He himself is creating drought situation in the State.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI K. MAYATHEVAR: Instead of collecting arrears of loan from big capitalists, he has written off arrears of loan of Rs. 8 crores which was to be collected from the re-rolling mill owners. But he has not written off petty loans due to poor farmers and petty shop-keepers in the street.

He has to pay Rs. 28.16 lakhs as income-tax arrears. This has not been collected from him. Is he a poor man? **Why do you not collect all this money? (*Interruptions*).

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North East): Will you allow all these allegations against a Congress Chief Minister?

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI K. MAYATHEVAR: He has allotted Rs. 100 crores without any permission. (*Interruptions*) He started the nutrition programme costing Rs. 100 crores, without any resources, as was mentioned in the Assembly.

MR. CHAIRMAN: That part of the speech where he makes allegations will not go on record.

SHRI K. MAYATHEVAR: So, I request that you should dismiss or dislodge that Government and save the people of Tamil Nadu.

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : मइस हृत्वपूर्ण विषय पर डिसक्शन करते समय हम काफी विषयान्तर हुए हैं । किसी ने अपनी कंस्टिट्युएंसी को प्रावलैम्ज रखी है और किसी ने पोलिटिकल सवाल उठाए हैं । इस का मुझे बहुत दुख है ।

**Not recorded.

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी

इस विषय का सम्बन्ध अर्थ व्यवस्था से बहुत नजदीक से है। हम पंचवर्षीय योजनायें चलाते हैं, उत्पादकता वर्ष का आह्वान करते हैं, 20–प्वाइंट प्रोग्राम गरीब लोगों के लिए चलाते हैं लेकिन बाढ़ और सूखे पर हम काबू नहीं कर पाए हैं। अगर इन पर हमने काबू नहीं पाया तो भविष्य में हमारी अर्थ व्यवस्था पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है।

तीन अगस्त को एक घंटे तक इस पर बहस हुई थी। आज भी काफी लम्बी इस पर बहस चल रही है। बाढ़ और सूखे की जो स्थिति है, एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर इस वास्ते काबू नहीं पाया जा सका है क्योंकि हमने जो योजनायें बनाई, हमने जो प्लान बनाएं वे कागजों तक ही सीमित हो कर रह गए, उनको कार्यावित नहीं किया जा सका। अगर योजनायें कार्यान्वित नहीं हुई और यह जो बहस है यह भी कागजों तक ही सीमित रही तो फिर हमारा काम चलने वाला नहीं है। इस वास्ते जैसा पहले एक माननीय सदस्य ने कहा स्थायी रूप से योजना यहां बनाई जाए और उसको कार्यान्वित किया जाए, तभी कुछ लाभ हो सकता है। काफी योजनाओं का माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। मैं भी एक विनती करना चाहती हूं। हमारे देश में कई प्रान्त हैं जहां बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा नदियां जहां बहती है और जहां की जनता बाढ़ से त्रस्त रहती है जबकि दूसरी तरफ कई प्रान्त ऐसे हैं जहां पीने तक के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता है। काफी वर्ष पहले हमने एक योजना बनाई थी कि सभी बड़ी नदियों का एकत्रीकरण करके पूरे देश के लिए, सभी प्रान्तों के लिए उनके पानी का उपयोग हो, इसकी व्यवस्था कर दी आनी चाहिये और देखा जाना चाहिये कि सभी प्रान्तों के लोगों को उसका फायदा मिले। उस योजना के बारे में सरकार को तुबारा सोचना चाहिये। उस पर चाहे जितना खर्चा आए करना चाहिये ताकि हमेशा के लिए बाढ़ और सूखे से जो जनता पीड़ित होती है, उसको स्थायी राहत मिल सके। हम सब जानते हैं कि तेहात की जो जनता होती है, ग्रामीण जो जनता होती है, जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं वही बाढ़ और सूखे से प्रभावित होने हैं और बड़े शहरों में बंगलों में रहने वाले लोग अच्छे घरों में रहदे वाले लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं और उनको बाढ़ और सूखे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए बाढ़-ग्रस्त या सूखा-ग्रस्त लोग चाहे राजस्थान के हों या महाराष्ट्र के हों किसी भी इकने के हों उनकी मांग यह है कि उनको समय पर राहत मिलनी चाहिये, हर साल बाढ़ आए और हम उनकी मदद करें। लेकिन मदद उनकी समय पर नहीं होती है। सर्वेक्षण करने में आधा साल चला जाता है। फिर रिपोर्ट आने में और भी कितने ही दिन गुजर जाते हैं। लेकिन उनको राहत नहीं मिलती है। अगर रबी की फसल का वह वक्त हुआ, जब तक राहत का प्रबन्ध होता है, खरीफ की फसल का समय आ जाता है और उनको उसके लिए सोचना पड़ता है। उसके लिए उनको नया बीज चाहिये होता है, खाद की उनको व्यवस्था करनी होती है। इस वास्ते समय पर उनकी मदद हो जानी चाहिये। यह जो देरी होती है मदद पहुंचाने में इस तरफ शासन का ध्यान जाना चाहिये। शासन देना भी चाहता है लेकिन नियम ऐसे हैं, टैक्नीकल फिडिक्ट ऐसी है कि देरी हो जाती है। योजनायें कई साल तक पड़ी रहती है कार्यान्वित नहीं होती है। इनके कार्यान्वियन का काम

आप जिला परिषदों को सौंपें, पंचायतों को सौंपें । राहत कार्य भी उनके माध्यम से कराए जा सकते हैं । ऐसे जो दुखी लोग हैं उनकी मांग है कि उनको हर साल यह मदद नहीं चाहिये, उनको हमेशा के लिए अभय चाहिये, विश्वास उनको दिलाया जाना चाहिये कि ये समस्यायें उनके सामने आ कर खड़ी नहीं होंगी । हमारा जोर इसी चीज़ पर होना चाहिए ।

बिजली का विषय भी किसी माननीय सदस्य ने उठाया है । जहां पानी की कमी है, जहां सूखा है, कम से कम वहां तो शासन को बिजली का पूरा प्रबन्ध करना चाहिये । महाराष्ट्र के कई इलाकों में हमने देखा है कि वहां सूखा पड़ा हुआ है, कुओं से जो इरिगेशन किया जाता है उसके लिए बिजली की कटौती की जाती है या बिजली का पूरा प्रबन्ध नहीं होता है । राव साहब ने राज्य सभा में एक सवाल का जवाब देते समय एक आश्वासन दिया था । अगस्त महीने में हम सूखे और बाढ़ का सामना करने के लिये उस क्षेत्र में सभी बातों का प्रबन्ध करेंगे ताकि इर्रीगेशन फेसिलिटीज़ उपलब्ध हो सकें । इस बारे में सरकार ने कहां तक कदम उठाये हैं, यह मैं जानना चाहती है ।

19.10 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

सर्वेक्षण पद्धति के लिये आपने कहा है कि कई प्रान्तों में सर्वेक्षण कमेटी पहुंची है और केन्द्र सरकार सूखे और बाढ़ क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहती है । तो मेरा विचार है कि पिछले साल महाराष्ट्र में सर्वेक्षण के लिये आपकी कमेटी गयी थी । कब ? जब फसल उग आयी थी और महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि हमारे यहां बहुत कम फसल हुई है और हमें केन्द्र से अनाज और पैसे की मदद दी जानी चाहिये । तो आपकी कमेटी ने सिर्फ कपास और अनाज का ही सर्वे किया । हमने कहा कि विदर्भ में जैसे संतरा होता है, पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ना होता है, इस प्रकार जो अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग फसलें होती हैं उन सब का सर्वे होना चाहिये । पर ऐसा नहीं किया । नागपुर और अमरावती में संतरा पैदा होता है, लेकिन उसमें इस साल कोलसी रोग लगा हुआ है जिससे उत्पादन कम होगा और परिणाम यह होगा कि हमें विदेशी मुद्रा अधिक नहीं कमा सकेंगे । इसलिये हमारा कहना है कि सर्वेक्षण पद्धति केन्द्र की ऐसी होनी चाहिये कि उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हमारे पास आनी चाहिये । ताकि उस इलाके को तुरन्त राहत दे सकें और उसमें अधिकारी लोगों का सहयोग लेकर जल्दी ही रिपोर्ट मंगायी जानी चाहिये और वहां जो भी फसलें होती हैं, उन सब का सर्वेक्षण किया जाना चाहिये तभी वहां की हालत का आप सही निरीक्षण कर सकते हैं ।

मज़दूर और किसानों के लिये मैंने पहले ही कहा, जो बाढ़-ग्रस्त और सूखा-ग्रस्त क्षेत्र के गरीब लोग हैं उनको राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत राहत देनी चाहिये । अभी एकसंसद सदस्य ने कहा जो योजना अभी तक ज़मीन पर नहीं उतरी उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक ग्रामीण रोजगार योजना है जो बड़ी अच्छी है जिसको अन्य प्रान्तों को अनुकरण करना चाहिये जिससे गरीब लोगों को रोजी रोटी दी जा सके । बाढ़ और सूखे की स्थिति के तीन हिस्से होने चाहियें । एक तो उसके कारण क्या हैं उसको रोकने के लिये दूर दृष्टि से कोई योजना बनानी चाहिये । बाढ़, सूखा क्यों पड़ता है, गार क्यों पड़ती है ? महाराष्ट्र में फसल जब हाथ में आती है

[श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी[

तो बड़ी बड़ी गार वहां पड़ती है जिससे फसल को नुकसान होता है तो जिस इलाके में कभी गार नही होती है अब क्यों हो रही है इस बारे में सोच कर उसको रोकना चाहिये और दूसरी बात यह है कि उनको किस प्रकार मदद देनी चाहिये। हमें हमेशा के लिये उनको कुछ साधन देने चाहियें ताकि वह स्थिति का मुकाबला कर सकें तो जहां हमेशा बाढ़ और सूखा होता है वहां आप बड़े और छोटे उद्योग लगाने के बारे में क्यों नहीं सोचते ? कब तक वहां का किसान खेती पर निर्भर करेगा ? जहां पोलिटिकल प्रेशर होता है, या कामदार आन्दोलन करते हैं या बड़े बड़े शहर हैं वहां तो उद्योग लग जाते हैं, लेकिन जो ट्राइबल और ग्रामीण इलाके हैं उनमें उद्योग नहीं लगते। अगर ऐसे क्षेत्रों में उद्योग लगाये जायें तो आप उनको स्थायी रूप से रोजी रोटी दे सकेंगे।

उनको राहत देने के लिये हम सब यहां पर सोच रहे हैं। ऐसे समय में सख्ती की वसूली क्या चीज है ? राज्य सरकार से कहें कि जो लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं और अन्य बैंक हैं जिन्होंने छोटे किसानों को कर्जा दिया है उसको इस साल सख्ती से वसूल न किया जाये। जब तक अच्छी फसल न आ जाये तब तक वसूली स्थगित होनी चाहिये। इधर बिजली की कमी, बरसात नहीं, महाराष्ट्र राजस्थान जैसा सूखा ग्रस्त तो नहीं होगा लेकिन दिन-प्रतिदिन महाराष्ट्र की हालत बिगड़ रही है। जहां इसके 2, 3 जिले सूखाग्रस्त रहते थे, आज भी 33 में से 13 जिले सूखाग्रस्त है और कई जिलों के छोटे छोटे क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखे की हालत है। वहां पहले ही फसल होती नहीं है, जो थोड़ी बहुत होती है, हमारे राव साहब अभी चले गये हैं, हमारे यहां की कपास और उसके भाव का प्रावलम बराबर उनके सामने आता रहता है। वह प्रावलम बराबर बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत में उस क्षेत्र में जो सख्ती से कर्ज वसूली होती है, उसे राज्य सरकार को नहीं करना चाहिये। इसके बारे में आदेश देने की आवश्यकता है।

मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगी कि बाढ़ और सूखे के चक्कर में जो किसान फंस जाते हैं, उनके लिये बीज और खाद समय पर मिलता रहे या नहीं, लेकिन समय पर पानी उनके यहां पहुंचता रहे, यह बहुत जरूरी है। इसके लिये कृषि अनुसंधान परिषद् और कृषि विद्यापीत जो प्रान्त में खुले थे, जिन पर जिम्मेदारी डाली गई थी कि वह सर्वे कर के मदद दें, खाद की, फसल की बीमारी की बीज की कोई प्रावलम किसान को हो तो उसके लिये काम करें। उस तरफ के किसानों का हक है, उसके लिये हमारे कृषि मंत्रालय को और शासन को कुछ कदम उठाने चाहियें।

हमारे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने अभी-अभी 131.41 करोड़ की मांग की है, मेरी रिक्वैस्ट है कि महाराष्ट्र की मदद के लिये, सूखे का सामना करने के लिये हमारी सरकार बड़ी खुशी से उसे मंजूर करके यह राहत दे।

मैं जिस विदर्भ राज्य से आती हूं, वहां इरिगेशन 20 टका भी नहीं है। हरयाणा और उत्तर प्रदेश में 80 टका इरिगेशन होता है। हमारे यहां पहले ही पानी की कमी है और किसान बड़ी मेहनत से विदर्भ में कपास का निर्माण करता है जिसके बारे में एशिया में बहुत बड़ा नाम हमने कमाया है, इसलिये ग्रामीण एरिया की मदद के लिये हम शासन से अपेक्षा करते है।

हमारे विरोधी भाई ने कहा कि यह शासन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं देखता । जब हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं थ, तब भी उन्होंने बाढ़ के क्षेत्रों में दौरा किया था और अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया था कि आप अपने क्षेत्र को स्थिति का मुकाबला करें । अब सत्ता में हमारी पार्टी है, हमारा राजकीय और पार्टी का धर्म है कि हम किसान और मजदूरों और गरीबों के संकट का हल करें, हमारी ऐसी पार्टी है जिसमें हम खड़े हैं, इसलिए आप सभी का साथ इसमें होगा तो हमारी सरकार बड़ी निर्भयता से इस हालत का मुकाबला करेगी । अपनी इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करते हुए अपना भाषण मैं समाप्त करती हूं ।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइण्ट आफ आर्डर है । अभी बहुत सारे वक्ता हैं, हमारा आग्रह है कि इस डिस्कशन को इस वक्त पोस्टपोन किया जाये, और कल 6 बजे इसे ले लिया जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I formally move the resolution:

"This House resolves that the discussion on flood and drought situation be adjourned till 2 P.M. tomorrow, October 15."

You take the opinion of the House. The Minister agrees. This is an important matter and the Minister agrees. The Minister said if the Chair agrees, he has no objection.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please listen to me.

SHRI CHITTA BASU: I had a talk with the Minister, Rao Birendra Singh. He says he has got no objection if we agree to postpone the discussion for tomorrow. One of the reasons is this.... (*Interuptions.*) We also feel that there should be a reply from the Minister which should be in detail because many important issues have been raised. It is not the question which concerns only partisan or any political Party. We want to know the Government's view. Therefore, they will also take some more time to explain their position. If that is so, we can continue the discussion tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati Geeta Mukherjee to continue. In the mean time, I will ascertain the opinion of the Government.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: They have raised a point. I will consult the Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI G. NARASIMHA REDDY (Adilabad): Sir, if that resolution is going to be adopted, then the Members who are leaving tomorrow should be allowed to speak now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am telling you that it is not possible to run the House according to the convenience of every Member. This discusion has been allowed by the hon. Speaker and the time-allotted is only 2 hours.

SHRI SUNIL MAITRA: I object to this. The Speaker has said, if you are prepared to sit beyond 6 O'clock, you can discuss as long as you wish.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is right. Now, you have come to my rescue. I thank you very much. So, if you are prepared to sit late in the evening, I am doing that. And if everybody finishes his speech in time, that is, within 2 hours, the Minister would have replied by 6 O'clock. Therefore, it is not the fault of the Government or this House. Therefore, I will ask Shrimati Mukherjee to continue.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Now, it is past 7 O'clock.

[Shri Satyasadhan Chakraborty]

Tomorrow if we sit beyond 6 O'clock, what is there?

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is all right. But you must know, tomorrow is week-end. Though we have a sitting on Saturday, most of the Members might go to their Constituencies.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will ascertain the opinion of the Government.

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, the Government has come!

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, with your permission, I move....

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, हम लोगों का आग्रह है कि अब बहस जितनी चल सकती है, उसको चलने दिया जाए और बाकी विषय को कल तक के लिए पोस्टपोण्ड कर दिया जाए, कल फिर 6 बजे से इसे ले लें । मिनिस्टर साहब भी एग्री हैं और हाउस को भी यह राय है ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह): हम सब लोग मिल कर ही इस का निर्णय करेंगे । लेकिन मेरी राय है कि आज 8 बजे तक चलने दें और शेष कल 6 बजे से बैठ जायें, क्योंकि काफ़ी लोग बोलने के लिए हैं ।

PROF. MADHY DANDAVATE: This is acceptable.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Accepted.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: My suggestion is, let us continue the discussion up to 8 O'clock. Tomorrow, from 6 O'clock we will sit late. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The suggestion made by Shri Narasimha Reddy is that whoever is going tomorrow should be allowed to speak now.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we will continue the discussion upto 8 O'clock. I have already called Shrimati Geeta Mukherjee.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a request from this side. Some people are showing the air tickets also. The suggestion to postpone the discussion came from the Opposition side only. Therefore, I will allow up to 8 O'clock or 9 O'clock. If the Ruling Party Members want to speak, let them speak. Why do you worry? I want to allow Ruling Party Members who are going tomorrow. Therefore, I will call the Ruling Party Members.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: After Shrimati Geeta Mukherjee, if anybody wants to speak today, if he waits. I will allow him to speak, even beyond 8 O'Clock. The Minister of Parliamentary Affairs has been good enough to agree that tomorrow also we will have it. Anybody who wants to go tomorrow can speak today. I am prepared to sit.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am sorry that our hon. Minister, Rao Birendra Singh, is not here....

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Deputy Minister is here.

Because a lady member speaks, a lady Minister is here.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: It is not that I am speaking as a lady; I am speaking as a Member of Parliament.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I said, lady member.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: I am speaking as a member of Parliament from my State as well as from my party for the whole country. Ours is a national party.

First of all, I would like to draw your attention to the fact that those who have spoken from different States either from that side or from this side have all expressed grave anxiety. This should be noted. But I am sorry to say that that grave anxiety has not been reflected in the statement made by the hon. Minister, Rao Birendra Singh, either on the 4th or yesterday in the Rajya Sabha.

Actually, I feel that the gravity of the situation, how it is going to affect our whole country in the near future, probably is not in full comprehension of the Central Government. Otherwise, the tone and the tune would have been more anxious and it would not have been complacent.

The hon. Members preceding me have raised certain points. Because of dearth of time, I shall not repeat those points. Take, for example, the problem of irrigation, how it was neglected and all that. I fully subscribe to those things but for brevity sake, for time sake, I shall not go into those details.

I want to take up one question first. What will be the consequences of this drought? As regards long-term programmes, yes, it is bound to affect them. As regards immediate programmes, there is one very serious thing that is going to happen. The clamour for foodgrains from all States will go on increasing. The Central food stock at the moment is being quoted to be as 1 crore and 32 lakh tonnes. That is what is being quoted. I do not know how far that is true because, as I see, I am doubtful about it. Even in Delhi, the ration shops do not deliver the ration, even when the Parliament session is on, from where the MPs draw their ration. This seems to me to be a very grave situation. With 1 crore and 32 lakh tonnes stock, probably it should not happen. Assuming 1 crore and 32 lakh tonnes are there, even then, I feel the demand will be very much more.

Here is the question of immediate change of policy and that is about the Government policy with regard to State trading in foodgrains. It is very essential that immediately the whole policy is changed and very big drive is made for further procurement from all the surplus pockets that are there, from all the surplus States that are there. For that, the paddy price of Rs. 122 announced by the Hon. Minister is not sufficient.

This question may not seem to be connected immediately with the drought and flood relief. But this will be in future one of the biggest questions.

I would like to draw your attention at the outset to the necessity of increasing the procurement price of these essential foodgrains. Procure them in a big way not leaving the room open for the profiteers and blackmarketeers to corner the grains which they are surely going to try. But I do not find any mention made, about such attempts of the profiteers or about the intentions of making such attempts by the government, in the statement of Shri Rao Birendra Singhji. Whatever the Hon. Minister might have said about the 20 Point Programme which includes an item on rationing and distribution system we know that generally all over India the supply of foodgrains to ration shops is in a very difficult position.

West Bengal expresses its solidarity with the rest of the States of India which are most affected by drought and floods. I am not naming those other States. I straightaway take up my own State.

I would like to draw your pointed attention to one fact. Look at the House. See. how many MPs are present here from each of the other States. Look at the MPs. from West Bengal. How many of them are present here? Why their attendance is more than others? Why this proportion of greater attendance of West Bengal M.Ps. compared to other States? It is because our State of West Bengal is really in a very serious situation. This is reflected in the

[Shrimati Geeta Mukherjee]

greater attendance of Members from West Bengal in the House today. It is not for politicking that we are here. It is an appeal to the whole of India about our difficult situation which is very critical. Famine is looming large in our State. I would like all sections of Members on the other side of the House to recognise this fact and help West Bengal in every way so that it can tide over the crisis. In this effort, let us not make any political distinctions.

I would like to mention certain facts about West Bengal. When Hon. Samar Mukherjee was speaking, Shri Rao Birendra Singhji mentioned about the offtake in West Bengal during the month of September. Shri Rao Birendra Singh asked what was the offtake in West Bengal. I know that in the month of September, the offtake of foodgrains in West Bengal was 2,59,000 tonnes. Yes. That is the point which has to be recognised. Not by us. We do recognise. That has to be understood fully by Shri Rao Birendra Singhji. If already in September, the off-take of foodgrains from ration shops is 2,59,000 tonnes, then how is it that Shri Rao Birendra Singhi has, two days back in the Rajya Sabha, made this statement that the allotment of foodgrains to West Bengal for October is 2,45,000 tonnes and that this is more than sufficient to meet the requirements of West Bengal?

If the production of foodgrains in West Bengal is in a difficult position, how is it that the allotment of 2,45,000 tonnes is enough to meet the requirements? And Shri Rao Birendra Singhji knows that whatever foodgrains there are in West Bengal now, even in that stock of foodgrains, 40,000 tonnes of rice and 80,000 tonnes of Australian wheat is not edible. This is absolutely non-usable stock in the State. The total stock in West Bengal is 3,56,029 tonnes as on 1st October, 1982. This is the position as on 1st October 1982—3,56,029 tonnes and 1,20,000 tonnes not edible. What is our situation? In Rajya Sabha it was not our Member whose question he did not answer. It was hon. Member, Shri Shankar Prasad Mitra who happens to be one of the Congress MPs who asked whether it was true that the allotment to West Bengal has been reduced from 1980 to this date. Rao Birendra Singhji did not answer. I only want to point out one thing. Even in 1980, the allotment for West Bengal—the monthly average—came to 3,23,250 tonnes and the allotment in 1981 was 2,65,500 tonnes. Now in September our allotment was 2,50,000 tonnes only. Other years we could somehow survive because our production was not of that situation. Last year's drought and this year's tremendous drought I would like you to see. I would like Rao Birendra Singhji to come and see how our peasants are fighting in the situation. For some time there was no rain. Then a little rain very late. In that little time they worked in the fields like warriors and somehow or other they have ploughed the fields and sown paddy but that very paddy is totally destroyed because there was no rain at all. This was the situation. What is going to happen to us unless the Central Government feels in a different way, speaks in a different way and acts in a different way. He says 2,45,000 tonnes is enough for West Bengal when the offtake itself was already much more than that. We have to say that. The West Bengal Chief Minister has made a big plea and we all MPs beseech this House and also the Central Government through you to rush at least four jumbo rakes a day. That is absolutely essential.

Another small point I have to make. Sir, I can see your feelings for the time. But I feel more for the distress. Now take the NREP programme. They say that the utilisation certificate has not come. In 1980 I was in Bihar during the elections. I was standing by the side of an NREP project and the contractor was running the work. I saw a woman coming and taking only half the wheat and going back and they furnish the utilisation certificate. That kind of utilisation certificate can always be had. Sir, the West Bengal Chief Minister has promised that within December they will give all the utilisation certificates. Now with this contractor's utilisation certificate—that should be the criteria or there can be something else from the humanity point of view? It is already October and within December they will get all these from West

Bengal. Then why should not NREP be taken up in a big way? So I feel the extent of the difficulty has not yet been fully understood. At the same time, I would like to tell you that in West Bengal our people are not beggars nor our Government has thrown up its hands in despair. We are trying our level best. The West Bengal Government has decided that by 15th October, 145 big tube wells and 22 river lift irrigation projects will be activated and despite all the electricity crisis, the West Bengal State Electricity Board has been asked to give priority for an 8 hour supply to these tube wells.

At the end, I would like to tell you one thing. To those who are thinking of politicking with West Bengal, my humble request is to consider one thing. Look at the North-East. It is now in turmoil. Look at the other Hindi speaking areas of India. What is happening in Punjab? How many communal riots are taking place in all the Hindi-speaking belt areas?

The entire north-eastern region—Assam —is in turmoil. Some may feel differently politically. But, is it not true that our State has a political stability? This is something which should be backed by all. Is it not true that despite all provocations in our State there is no communal riot and there has been no lingual riot. We have to be protected by the whole of India. If the stability in our State is to be destablished by some people. it cannot be done. I am sure about it. So, Sir, I appeal, through you, to Rao Birendra Singh, to take a different attitude and come to our help immediately. Let him personally lead a team and see for himself the areas affected by drought. The NREP and supply of foodgrains are the national task of the entire India. I am speaking for West Bengal. This is an SOS from millions of West Bengal. Remember that though we got 52 per cent of votes from the majority of the population, but you also got 48 per cent of the votes. Don't you have the same responsibility? On the ration card there is no mention of whether the holder is Congress or Communist. Let them seriously think over. Listen to the SOS of our people and let him come to the aid of West Bengal which is acting as one of the pillars of integrity, secularism and also national integration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri K. S. Bhoi. I shall call one by one.

DR. KRUPASINDHU BHOI (Sambalpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, anyhow after so many encroachments you have allowed me to speak. My number was 6. Now it is number 10.

Anyhow I am thankful to you for allowing me to speak. This is not a political problem; this is a national problem—flood and drought. At the same time, Orissa is a victim of cyclone also. Sir, you must be remembering that in the first calling attention of this Parliament two years ago, the hon. Minister, Rao Birendra Singh had promised on the floor of the House that he was going to constitute a board to deal with the problems of natural calamities in a bigger way. He promised on the floor of the House that the experts of the country would go deep into the matter and suggest measures for eradication of floods and drought. This natural calamity and disaster checking board was to be formed for the whole country. It is impossible to eradicate this. But, you can at least take some palliative measures so that the menace of drought and floods can be checked. In our country there are two schools of thought for control of floods. By controlling floods, fifty per cent of the miseries of the drought-affected areas can be solved.

Our hon. Dr. K. L. Rao, a top-grade Engineer, has suggested the building up of big reservoirs in different parts of the country, so that we can harness the surplus waters of the rivers which are now flowing into the sea. More than 1363 million cusecs acre feet of surplus water is now flowing into the sea. At the same time we can have a few selected major Mr. Visveswarayya has shown the path to his followers in the country. He has stated that we can have small reservoirs in all the rivulets of the country and at the same time we can have a few selected major irrigation projects,—not major in the irrigation terminology. Now they have changed the terminology. Major means that which is multi-purpose; the cost will be very much and we cannot get so much of finance in this country. What I want is small river, multi-purpose projects which

[Dr. Krupasindu Bhoi]

can be constructed without delay, which will have lesser gestation period. At the same time we can have our afforestation and horticulture programmes. This multi-purpose project will include horticulture and afforestation and production of electricity. Up till now though very many commissions and committees have been appointed to go into the question of the control of flood, yet, no master plan has been drawn up in a proper way, so that we can harness all these waters which are drained away into the oceans. If any such master plan had been drawn up with regard to major, medium and minor irrigation, the hon. Minister should take the House into confidence and tell it on the floor of this House as to which are the proects which can be taken up in this way. He can say, "After my discussion with some international people I am going to have these projects major, medium, minor projects". But so far such a concrete master plan has not been formulated.

My second point is this: Financing is a major problem in this country. We can adopt the scheme of "project sale" to the farmers. That means, take a project which costs Rs. 100 crores and it is irrigating more than 4 lakhs acres of land. Now, what is the cost benefit ratio? We can give incentive to the farmer and we can collect the cost of the Project from him in instalments.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Bhoi, please resume your seat. I have an announcement to make Hon. Members, after Dr. Bhoi concludes his speech, Mr. Kedar Pandey will intervene. Then, some members from either this side or that side who want to speak.... (*Interruption*) You must listen to me. The hon. Irrigation Minister will intervene. Do you not want this intervention?

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhilwara): We want afterwards.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have discussed with Parliamentary Affairs Minister. Such of those Members who will not be available tomorrow may speak now; they can speak taking 10 minutes each. We will go up to the last speaker completing in this way and then the House will adjourn. Tomorrow, after half-an-hour discussion is over at 6 O'Clock, we will again take this up. So, this is final. Now, Dr. Bhoi to continue.

DR. KRUPASINDHI BHOI: Such plans which gives incentive to the farmers can be introduced. In Sambalpur this type of scheme has been adopted for Minor Irrigation. Government of India should adopt such schemes in other places also. Funds will not be a problem at all. The fund can be paid back to the Irrigation Department. So, in this way, we can harness the rivers properly for the benefit of the nation.

The slippages in the gestation period of major irrigation projects takes more than 5 years. It is more than the scheduled time. These slippages are very much. We must learn something from China and the USSR. Within a period of 80 days they could complete a multi-purpose river project by employing millions of people who have got much more human resources. We have to mobilise the human resources and unless these irrigation schemes are declared as an industry and the workers engaged in the irrigation schemes are paid as the industrial workers who are paid more than Rs. 16 per day, we cannot mobilise the human resources for the irrigation scheme works. For all the big multi-purpose river projects, both in the United States of America and in China it was possible for them to muster human resources. But I do not understand why it is not possible for India to muster huge human resources for our various major jrrigation schemes. During Pandit Nehru's time in my own constituency, Hirakud Dam was constructed with a record of time of six years' gestation period and it was inagurated by Pandit Jawaharlal Nehru in 1957. So also some projects in Karnataka had been completed within the scheduled time under the supervision of the great Engineer, Dr. Visveswarayya. But in many other cases slippage of the gestation period was more than 5 years or six years or seven years. The point which I would like to mention is that we have given more impetus to the energy sector and we are going to produce more than 14,000 megawatt of power from the thermal

power stations in the Sixth Five-Year Plan. We are spending about Rs. 1 crore for production of one megawatt of power in thermal power stations and it is estimated that on a multi-purpose river dam project, for production of one megawatt of power and for giving irrigation to more than a thousand acres of land, we spend Rs. 1.2 crores. This is not an expensive proposition, because in thermal power generation, we are using the non-renewable energy resources, but for production of hydro-electricity, we are using renewable energy and also at the same time we are controlling flood and helping the drought affected people and afforestation. So, serious consideration should be given by the Irrigation Ministry and they should approach the Planning Commission and the Government, so that there is a fresh plan of appraisal and allocation of more funds for multi-purpose river projects.

Sir, after 1900 A.D. Orissa has always been facing severe drought especially in the Western part, it is occurring regularly and intermittantly, the coastal part of Orissa is a victim of flood. So, the whole economy of Orissa is getting shattered every year. Today, after all these years of independence, how many crores of rupees we are spending for construction of embankments, for temporary restoration measure and giving relief to the poor? Up-till-now the Government of India has no estimate to this effect. But we are spending a lot of money in this account without much benefit. In this year, the tragic pendulam of cyclone had swung to drought and then flood. In the last Session also, we had discussed the drought situation in the country and I had given at that time some suggestions. I would again request the Government to consider those suggestions.

Now, on 18th and 19th of last month, there was a cloud burst in Sambalpur, which is my constituency. The rain-fall was more than 581 milli-metre and because the rain gauge capacity was 581 milli-metre, nobody knew how much water over-flowed. The whole tragedy happened within six hours. So, it was a cloud-burst in Sambalpur and its surrounding area of about 40 kilometers. The damages to life and property are more than Rs. 50 crores worth. Eleven people died and 4 people were missing in the mishap. More than 20,000 houses were washed away, collapsed and semi-collapsed. Then, again, in the coastal parts of Orissa, in the Mahanadi Basin catchment area, there was heavy rainfall and devastation on 29th and 31st. The rainfall was more than 17 to 18 inches. Hirakud dam was closed, and the blocked rainwater in Mahanadi catchment water which rushed to Cuttack and Puri districts was more than 17 laks cusecs. It can negotiate only fifteen lakhs cusecs of water and because of that it burst and the whole districts of Cuttack, Puri, Bolangir and the surrounding areas were submerged in water for so many days.

According to the memorandum submitted by the Government of Orissa to the Government of India, the flood was more in intensity than in 1955 and the damage to life and property was also much more. It caused severe damage 9000 villages and 114 blocks in 8 districts namely Cuttack, Puri, Ganjam, Phulbani, Dhenkanal, Bolangir, Sambalpur and Kalahandi had suffered. The devastation had extended over 90,000 square miles; 7 municipalities and 16 notified area councils had been affected. A population of more than 5 million people were affected. According to the report, about 12 lakh hectares of crop was damaged; more than 20 per cent of the total cultivated area of land was affected due to the inundation.

Orissa is a poor State and always its economy is affected by this natural calamity and political instability. The Minister for Agriculture comes from Haryana, and as we know the *per capita* income of Haryana and Panjab is very high, and I am a person from Orissa, where the *per capita* income is the second lowest. Sir, the 6th Plan allocation for Orissa for flood control and irrigation is Rs. 360 crores which is only pelting a store over a mountain. There are so many projects in my State which have been investigated. Shri K. L. Rao, in his speech in 1976, had categorically told about the miseries of Orissa and indicated how these can be overcome. Suvernrekha project has already been cleared, but the implementation has yet to be started. The land in my constituency, except two blocks, is all non-irrigated, and they are always victims of drought. In order to check

[Dr. Krupasindhu Bhoi]

drought and to help the flood-affected areas of coastal districts, there are many projects which have been submitted to the Government of India. There is the Chiroli irrigation project on the river Ong. The Prime Minister had promised to look into this matter. I will request the Minister for Irrigation that the Chiroli irrigation project which will irrigate more than one lakh acres in Padampur sub-division should be vigorously pursued and it should be pushed through immediately. This is because in the 6th Plan, the money has already been provided by the State Government; CWC has, of course, yet to clear it. I want the Minister to look into it personally, so that it can be cleared by the CWC and the Government of India.

Then in Tel river area in Bolangir district there was a great devastation this year. Three projects can be located in three places in this river. The Government of Orissa has given a proposal to control the floods of the Mahanadi. But these two rivers Ong and Tel can be harnessed if you construct dams on them according to the Visvesvarayya report. 7000 cusecs of water can be reduced. There is a controversy about embankment. In all the embankments due to heavy silting in all the rivers, the riverbed is going up. So, it is but natural that water will find its own way and level. Cuttack town is now lower than the bed of the River Mahanadi. For these things technical experts should be consulted to see how this unnecessary spending on embankments can be checked and dredging operation can be maintained and that these embankments are totally wiped out with the consultation of the technical *experts*.

20 hrs.

Sir, Sambalpur is my district. This district was also visited by the floods. The Orissa Government and the Sambhalpur District Authority had presented a memorandum to the Central Government wherein they have asked for a minimum of Rs. 30 crores separately for the district so that the devastation caused to Sambhalpur district can be recouped. At the same time the State Government has asked Rs. 618 crores from the Government of India and they should consider these requests as soon as possible.

Sir, about the food situation, the Government of Orissa has asked 1,40,000 tonnes of rice and 30,000 tonnes of wheat immediately so that they can combat the situation.

Last but not the least water management is a national problem and all Members of Parliament are agreed on this. In so many previous discussions hon. Members have opined that it should not be treated as a State subject, but it should be brought under the control of the Government of India so that proper checks and balances can be maintained. And, Sir, it is not my opinion alone. When the Opposition party was in power, our party was toeing the same line that the water management should be treated as a Central subject. And now when we are in power, except West Bengal, I think all Parties are agreed on this. This is a national problem and we can check this national disaster by adopting the theory that it should be a subject under the control of the Union Government.

सिंचाई मंत्री (श्री केदार सिंह) : माननीय उपसभापति जी, इस डिवेट में 16 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और इस बहस को श्री हरिकेश बहादुर ने शुरू किया । उन्होंने अपनी बात कहते हुए ज्यादा जोर सिंचाई के मुताल्लिक दिया । जहां तक ड्रौट की बात हैं, उसके सम्बन्ध में हमारे लायक एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपके सामने अपनी बातें रखेंगे । शायद वे आज ही आ जाएं या कल भी आ सकते हैं । आज भी आ सकते हैं । वैसे उनके रिप्रेजेण्टेटिव कृषि राज्य मंत्री यहां पर मौजूद हैं ।

सिंचाई और बाढ़ के मुताल्लिक यहां पर जितनी बातें कही गई, वैसे मैंने बहुत बार यहां पर कहा है कि बाढ़ और ड्रौट का रैडिकल क्योर हो सकता है । यह कोई भगवान की देन नहीं है । ऐसा हम यहां नहीं कह

सकते । क्योंकि आजकल विज्ञान और टेक्नालांजी के युग में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है । इसलिए बाढ़ और सुखाड़ दोनों का रैडिकल क्योर हो सकता है । हमारे दोनों सदनों में नेशनल प्लान के ऊपर काफी वहस हो चुकी है । हमने उस वक्त भी कहा था कि इस देश में सरफेस वाटर हर साल कितना वह कर आता है । हिन्दुस्तान में प्रतिवर्ष 1440 मिलियन एकड़ फीट पानी बरसात के दिनों में आता है । मैं आपको यह बिल्कुल करैक्ट फीगर्स दे रहा हूं । लेकिन हम पानी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सके हैं । अभी तक हम 1440 मिलियन एकड़ फीट पानी में से केवल 220 मिलियन एकड़ पानी का ही इस्तेमाल कर पाये हैं । बाकी पानी समुद्र में बह जाता है । इस देश में इतनी बारिश होती है, जिसकी वजह से यह बाढ़ हैं ।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री केदार पांडे : मानसून में इतनी वर्षा होती है । इस देश का क्लाइमेट ऐसा है । इस देश की हवा ऐसी है—यही वजह है । हम 1440 मिलियन एकड़ पानी में से 220 मिलियन एकड़ पानो का उपयोग सिंचाई और सब बातों में कर सके हैं और बाकी का नहीं कर सके हैं ।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री केदार पांडे : साधन नहीं है । यह पुरानी कहानी है ।

एक माननीय सदस्य : आपकी इच्छा नहीं है ।

श्री केदार पांडे : इच्छा रहने पर भी । आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं । इसी लिए हम लोगों ने राष्ट्रीय योजना बनाई है—प्लान फार दि वाटर रिसोर्सेज डवेलपमेंट इन दिस कण्ट्री । इस पानी का इस्तेमाल हम लोग कैसे करें और फ्लड न हो तथा इसका उपाय करें । दूसरा सवाल है इसको सिंचाई में लगाया जाए और तीसरा है कि हम इससे बिजली पैदा करें । नेशनल प्लान के बारे में फिल्म बनी है । आप लोगों ने देखी है । आपने बुक लेट भी पढ़ा होगा ।

श्री राम प्यारे पनिका : नहीं पढ़ा ।

श्री केदार पांडे : नहीं पढ़ा है, तो पढ़ना चाहिए । आप लोगों को दिया गया है, फिर भी आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको पढ़ना चाहिए । हमने इसको काफी बंटवाया है । आशा है नेशनल प्लान से फ्लड हमेशा के लिए बन्द हो जाएगा । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि 1440 मिलियन एकड़ पानी हर साल अमरीका में भी आता है, जिसका कि उसने 50 प्रतिशत इस्तेमाल कर लिया है । इसलिए आपने देखा होगा कि अमरीका में बाढ़ नहीं सुनते हैं । सुखाड़ बहुत कम सुनते हैं । अमरीका सब से धनी देश है । उससे बढ़ कर दुनिया में धनी देश कोई नहीं है । समस्या बहुत बड़ी है, जिसको सुलझाना है । यहां पर माननीय सदस्यों ते एक बात यह भी कही कि इसका कोई रैडिकल क्योर नहीं होगा, मैं कहना चाहता हूं कि ज़रूर होगा और इसमें शंका की बात नहीं है । मैंने पहले कहा था कि 50 हजार करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा । इतना धन कहां से आएगा । एक ही बार तो इस्तेमाल नहीं करना है । पैनिन सुलर और हिमालयन रिवर्स सब नेशनल प्लान में सम्मिलित हैं । पानी के इस्तेमाल के बारे में नेशनल प्लान है । उसका साइंटिफिक एनालिसेस है । ऐसी बात नहीं है कि इसका प्लान है ही नहीं । पहले नहीं था, अब है । गारलैण्ड कनाल

[श्री केदार पांडे]

की बात भी थी । वह प्रैक्टिकल नहीं था । इसलिए सब को मिला कर हिन्दुस्तान ने इसको कबूल किया है । जो बंगलौर में इरिगेशन की कान्फ्रेंस हुई थी, उसमें नेशनल प्लान रखा गया । पूरे देश ने इसका स्वीकार किया है । "इफ" और "बट" का सवाल नहीं है । आगे बढ़ने की बात है । नेशनल प्लान के वाटर रिसोर्सेज डवेलपमेंट के लिए एजेंसी बनाई गई । एजेंसी का रजिस्ट्रेशन आठ जुलाई का हुआ है । इस एजेंसी के द्वारा इस सर्वे का काम हम लोगों ने उड़ीसा से शुरू करने को सोचा है । उड़ीसा में सब से ज्यादा बाढ़ हैं । माइक्लोन आया, कितना नुकसान हुआ । लेकिन एक बात है, हीरा कुड डेम इफैक्ट रहा । वह टूटा नहीं । यदि टूट जाता तो हालत और खराब हो जाती । लेकिन उसके नीचे सम्बलपुर में इतनी बारिश हुई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हुई । उसका इन्तजाम हम लोग करने जा रहे हैं । उस एजेंसी के द्वारा हम लोग महानदी का सर्वे कर रहे हैं । महानदी में सबसे ज्यादा बाढ़ आई । ऐसा कोई उसका सर्वे शुरू करें और भी कोई सर्वे शुरू करें । इरादा यह हैं कि महानदी का जो सरपलस पानी है, उसको हम साऊथ की किसी रिवर में डाइवर्ट करें । इस तरह से हम काम शुरू करने जा रहे हैं । यह कोई कपोलकल्पित बात नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है जो कि कागज पर ही हो । अब हम इसको करने जा रहे हैं । (**व्यवधान**) . . .

मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि अब शुरूआत हो रही है, नया अध्याय शुरू हो रहा है । पानी के उपयोग के नये कार्य होने जा रहे हैं । पहले तो आप यह सब सुनते थे लेकिन अब आप सुनेंगे नहीं बल्कि होते हुए देखेंगे । अब हम जल्दी से शुरू करने जा रहे हैं ।

हमने इसका सर्वे करने के लिए नये स्टेप्स उठाये हैं । एक स्पेशल एजेंसी बनायी है और उसके द्वारा हम सर्वे शुरू करेंगे । एक बात हम कहना चाहते हैं कि यह जो बाढ़ और सुखाड़ जैसी विपत्तियां हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए हम पूरी तरह से प्रयत्नशील हैं । इनके बारे में हमें निराश होने की जरूरत नहीं है ।

जहां तक फ्लड की बात है, ड्राट की बात है ये इस साल पहली बार नहीं आयी है और ना ही ड्राट इस साल पहली बार पड़ा है । ये पहले भी होते रहे हैं । लेकिन इस साल एक आदमी भी भूख से नहीं मर सका है । इसके बारे में हमें कहीं से भी कोई खबर नहीं आयी है कि भूख से कार्य व्यक्ति मर गया हो । क्योंकि हमारे पास अनाज इतना है कि हम किसी को भी भूख से नहीं मरने देंगे । (**व्यवधान**) किसी ने भी हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि भूख से कोई आदमी मरा हो । (**व्यवधान**) बाढ़ से मरे है लोग । सूखे से कोई नहीं मरा है । यह बात मैं इस मायने में कह रहा हूं कि हमारे पास अनाज की कमी नहीं है जिससे कि लोग भूख से मर जाएं । इस बारे में हमारे पास कहीं से भी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है ।

अब आप साइंटिफिक बात भी जानिये । हमारे यहां फ्लड प्रोन एरिया 40 मिलियन हेक्टेयर है । जिसमें से हर साल 1.2 मिलियन हेक्टेयर एरिये में बाढ़ आती है । इतना बड़ा फ्लड प्रोन एरिया है । इसको आपको जानना चाहिये । इसमें से हर साल 1.2 मिलियन हैक्टेयर एरिये में बाढ़ आती है । यह जो 40

मिलियन हेक्टेयर फ्लड प्रोन एरिया है इसमें से पिछले 26–27 वर्षों में एरिया घटा है। इतने वर्षों में 11.17 मिलियन हेक्टेयर एरिये का प्रोटक्शन हम कर सके हैं। इसमें खर्चा हुआ है। हमने इतने डेम बनाये हैं। आपके सामने भाखड़ा नांगल डेम है। बहुत-सी नदियों पर एम्बेंकमेंट्स बनाये हैं। कोसी में बनाया है। उस एम्बेंकमेंट का असर पड़ा है। कोसी में हम रिजवायर भी बनाना चाहते हैं। मैं गोरखपुर का एरियल सर्वे करने गया था। वहां मैंने देखा कि एक भी एम्बेंकमेंट नहीं टूटा है। उसकी वजह से गोरखपुर और बलिया की रक्षा हुई।

श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप इन्क्वायरी कराइये कि बिहार में कोई आदमी भूख से नहीं मरा है। नहीं तो आपके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस आ जाएगा। यह सब कुछ आपको पता कर के कहना चाहिये।

श्री केदार पांडे : कोई खबर आए तब तो हमको पता चलेगा। अभी तक हमको कोई खबर नहीं मिली है। हमें इतना पता है कि हिन्दुस्तान के पास इतना अनाज है कि अनाज की कमी नहीं हो सकती और काफी मात्रा में हर जगह अनाज भेजा जा रहा है और भेजा जाएगा और अभी तक भूख से एक भी आदमी नहीं मरा है। बाढ़ से मरे हैं, हमने फिगर हमें बताये हैं।

तो एक बात यह कि 40 मिलियन हेक्टर फ्लड प्रोन एरिया में से 11.17 मिलियन हैक्टेयर प्रोटेक्ट हो गया है और 8 मिलियन हैक्टेयर एरिया ऐसा है जिसका प्रोटक्शन करना आसान नहीं है। 967 करोड़ रुपया हमने इस पर खर्च किया है, अभी तक, लेकिन सिक्सथ फाइव इयर प्लान में 2.5 मिलियन हैक्टेयर का प्रोटक्शन करने के लिए 1045 करोड़ रुपया रखा गया है। इस प्रकार 40 मिलियन हैक्टेयर में से 18, साढ़े 18 मिलियन हैक्टेयर फ्लड प्रोन एरिया हर जाएगा, जिसका इंतजाम आगे किया जाएगा।

अब आप यह जान लीजिए कि हिन्दुस्तान में कितना फ्लड है। जनरल टर्म में बात करने से काम नहीं चलता, साइंटिफिक स्टेटिसटिक्स में बात कीजिए।

Then you will be able to appreciate the problem.

. . . (**व्यवधान**) . . .

मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करता मैं पूरे हिन्दुस्तान की बात करता हूं।

. . . . . (**व्यवधान**) . . . .

मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा बाढ़ चार प्रदेशों में आई है। उत्तरप्रदेश, बिहार, आसाम और उड़ीसा।

PROF. MADHU DANDAVATE: If people die in the floods, it is no sense in telling them that you are only a small perceriege composition of the entire population of the country. These statistics will not help them.

SHRI KEDAR PANDAY: But tell me the name of a State where a single person has died in floods.

SHRI HARIKESH BAHADUR: In your statement itself there is a mention of deaths due to floods.

SHRI KEDAR PANDAY: I am talking of statistics, in the sense, as to how much area is flood-prone in the country. That is what I meant when I said 'statistics'. Up till now we have been able to protect so much area from floods. We have done a lot in this direction.

SHRI SUNIL MAITRA: In your Ministry you have also now changed the vocabulary. Instead of 'flood control' you are now saying 'flood management'.

श्री केदार पांडे : फ्लड कट्रोल है, हम कहते हैं । जब फ्लड से प्रोटक्शन दिया तो फ्लड कंट्रोल है । अब चाहे इसे फ्लड कंट्रोल कहिए, चाहे फ्लड मैनेजमेंट कहिए ।

But the matter is the same.

SHRI SUNIL MAITRA: It is not the same.

श्री केदार पांडे : यह बात सही है कि फ्लड से रक्षा हुई है । यह आप मानिए । 11.17 मिलियन हैक्टर फ्लड प्रोन एरिया में प्रोटक्शन मिला है, इस बात को आप चैलेंज नहीं कर सकते और सिक्सथ फाइव इयर प्लान में 2.5 मिलियन हैक्टर में प्रोटक्शन देंग, इसके लिए 1045 करोड़ रुपया दिया है । हम इसको कर रहे हैं ।

दूसरी बात सिंचाई की है । आप देखिए 1951 में क्या हालत थी, विफोर प्लान पीरियड । उस वक्त 22.4 मिलियन हैक्टर और आज इरीगेशन 61.4 मिलियन हैक्टर में है । इरीगेशन से हमारे देश में सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि अनाज की पैदावार बढ़ी है ।

अनाज के मामले में हम सैल्फ सफिशियन्ट हुए, पहले नहीं थे । (**व्यवधान**) यह इरीगेशन की वहज से ही हुआ ।

एक माननीय सदस्य : बाहर से फिर अनाज क्यों आ रहा है ?

श्री केदार पांडे : स्टाक मेन्टन करने के लिए है ।

उसी तरह से आगे बढ़ और यह काम तो अच्छा हुआ । एक-तरफ आप कह रहे हैं कि इस गवर्मेन्ट ने और इस कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए । जो एचीवमेन्ट हुआ है, उस एचीवमेन्ट को भी रखना चाहिए और जहां ड्रा-बैक है उसको भी रखना चाहिए । दोनों आसपेक्ट्स आपको रखने चाहिए । मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि फ्लड से नुकसान हुआ है, बराबर परेशानी हुई है, ड्राट भी आया है और हर साल आता है । लेकिन हम चाहेंगे कि नेशनल प्लान को एग्जीक्यूट करें । लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेंगा । उसके बारे में हमने एक और बैठक बुलाई थी और कहा था कि 113 मिलियन हैक्टर्स होटल अल्टीमेट इरीगेशन पोटेन्शियल इस देश में है । अब तक हमने 61.6 मिलियन हैक्टर्स कवर किया है । बाई दी एन्ड आफ सैन्चुरी हम चाहते हैं कि 113 मिलियन हैक्टर्स जो अल्टीमेट इरीगेशन पोटेंशियल है, उसको एचीव करें । पिछले साल अनाज की पैदावार 134 मिलियन टन हुई । इरादा यह है कि बीसवी सदी से अन्त तक हम इरीगेशन पोटेन्शियल एचीव करेंगे और उस समय अनाज की पैदावार 268 मिलियन टन हो जायेगी ।

ज्यादा इरीगेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ेगा । इस देश में काफी प्रोडक्शन ऐसा होता है, उसका 60 परसेंट इरीगेटेड एरियाज से आता है, इसको कोई चेलेंज नहीं करता है ।

उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कहता हूं । नेपाल से प्रापर अन्डरस्टेन्डिग की जरूरत है । जब तक नेपाल से प्रापर अन्डरस्टेन्डिग नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा भी आयेगा, इसलिए उसका डम बनाना होगा नेपाल के

हिस्से में ।

We should have cordial relations with Nepal. We have got cordial relations. We are going to pursue it.

हम कान्फीडेट हैं कि एक वक्त आयेगा, जब वहां का मामला तय हो जायेगा । अभी फल्ड के बारे में मैंने इतना ही बताया, कल ड्राट की बात होगी, अनाज के पैदावार की बात होगी और जो स्टेट प्राबलम्स हैं उसको हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर रखेंगे ।

SHRI G. NARASIMHA REDDY (Adilabad): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very thankful to the hon. Member, who has raised this discussion. Many Members have thrown sufficient light on the drought and flood situation in the country. I am also thankful to the hon. Minister, who has now given sufficient statistics about the national plan. An important point has been raised by hon. Members in this House. The hon. Minister is convinced that the drought and flood situation in the country can be solved by the end of this century by the national plan, if it is going to be implemented.

If you see the history of our country in the last so many years, we used to have once in a way drought and once in a way a flood. But I would like to remind this House that if you see carefully, as the years have passed, the drought or flood has been occurring after every five or two years. But this year, as many hon. Members have said, the situation is such that drought and flood have come in the same year and in the same area.

I am drawing your kind attention to this fact that if the same situation continues, though the hon. Minister feels that by the end of the century the problem would be solved, I am one of those who feel that the problem would be aggraveted and that it would be one of the very difficult problems which we will have to face by the end of the century. Why do I say so? Because, by the end of the century, the situation will be such that we will have drought almost everywhere and if at all we receive a little rain, it willl not be sufficient and, if we have a little more rain than we do want, it will become a flood.

I am only trying to bring to your notice the fact that in our country, in the last so many years, the trees were indiscriminately felled, if they are going to be felled in the same way, the situation by the end of this country will be that we will have no forests left. Once you have no forests in the country, once the area under forests is going to dismish, whatever the size of your projects are going to be, they will get silted up. One of the reasons for floods in the rivers of our country is that because of land erosion the depth of the river is decreasing. And when the depth of the river decreasses, even when the amount of rainfall is negligible, even when it is 40" or less, there will be floods everywhere. Unless we think of the root cause, floods and drought will recur in the same area in the same State at the same time and we cannot solve them.

So, I would urge upon the hon. Minister not to be guided by simple statistics. He should see why it is happening and what is the cause and how can we protect our existing irrigation projects. You have got the irrigation engineers, who can give thought to the problem why the irrigation projects are getting silted up so fast and why a project, whose life is supposed to be 70 or 100 years, does not last even for 25 years. If the present trend continues, by the end of the century, I am afraid, all your irrigation projects and rivers may be silted up and even a few drops of rain may cause floods all over the country.

Therefore, the problem is not only about the money or the national plan. The solution for saving this nation from drought or flood lies in going back to our olden days, so that we can have sufficient rain and yet no flood or drought. The only way out is to invest sufficient funds in growing forests in this country. We must have at least one-third of the area under forests. Otherwise, even if we spend Rs. 40,000 crores or Rs. 100,000 crores this problem is not going to be solved. On the other hand, the problem will be aggraved by the end of the century

[Shri G. Narsimha Reddy]

and, as I have already said, we will have drought everywhere in the country and even with a little rain there will be floods all over the place. Therefore, I would urge upon the hon. Minister to pay attention to this.

I now come to my State of Andhra Pradesh, which has been suffering from severe drought conditions. It is only very recently that an hon. Member of this House, Shri Vijay Bhaskara Reddy, took over as the Chief Minister of that State. He was sworn in on the 20th. On the 21st, even before visiting his office, he had to rush on a tour of the drought-affected areas. For five days he toured the entire area, because the situation was very bad. The Government of Andhra Pradesh have submitted memorandum to the Government of India. Only yesterday we read that the Government of India are thinking of sending a team to Andhra Pradesh either today or tomorrow.

I would only like to give some statistics as far as the situation in our State is concerned. Usually in our State this is the monsoon season, we receive rains through the south-west monsoon and also north-east monsoon. In the beginning of June when we received south-west monsoons, we had very good rains and all our farmers had high hopes. They all went into the fields and ploughed their lands and sowed seeds. In most of the areas irrigation facilities are not there. About 70 per cent of the land depends on monsoons. After sowing the seeds they were very happy. But by the time the month of August came there was such a dry spell that almost all the crops in 20 districts, in 177 talukas in Andhra Pradesh were affected. Because of this, the farmers and the agricultural labourers become unemployed. The farmers had invested a lot and they were only waiting for harvesting, but because of the long dry spell, we did not have anything and the farmers are in a miserable condition. The purchasing capacity of the weaker sections and agricultural labourers has become zero. Our hon. Minister with great pride said, 'We have sufficient food available in our country to feed every man.' There is no doubt about it and I am very happy about it. But I would only ask the hon. Minister: Are you going to give food free to us? We must have purchasing power. Unless our farmers and agricultural labourers and other weaker sections of the community in the villages have the purchasing capacity, your FCI godowns or the fair price shops are not going to give us any foodgrains. Unless you create the potentiality of work and create an opportunity for the weaker sections of the community to earn so that they can purchase the foodgrains which you have got—thousands of tonnes in the godowns—no purpose will be served. Therefore, I urge upon the Government that Rs. 200 crores as requested by our State Government may not be sufficient. Whatever the amount may be, I would only request the Government to come out with a statement to this effect so that all the people in the country, whether it is the people of Andhra Pradesh or Rajasthan or any other part of the country, will have the necessary confidence. The Government must be able to create the confidence amongst all the people of our country who are now suffering from either drought or flood, saying that here is the Government, if the State Government cannot help the people, the Government of India is prepared to invest as much money as possible to save the life of the people to create work for them, to see that their purchasing power increases and they will not starve. This is very important. You have to create confidence among the people more than give Rs. 30 or Rs. 40 crores.

Lastly, because of this sudden drought in our State, nearly 81 lakhs of acres of land in our State did not yield crops and it was estimated that there is a loss of nearly 53 lakhs tonnes of foodgrains. The total estimated loss would be about Rs. 600 crores and 31 lakhs of people including farmers and agricultural labourers are today without work.

With these few words—I would not like to take much of your time—I would once again urge upon the hon. Minister to see that a team to Andhra Pradesh is sent immediately to study the situation and

give them the required monetary assistance, but more than that, give the confidence to the people of the State so that they can stand on their legs and face the situation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Mr. Ram Swaroop Ram may speak.

SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY (Mehsana): You have already given chance to three Ruling Party Members. Now it is my turn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your party has already been given enough time. As a special case I will permit you. Because you are requesting, I will permit you, but you have got to complete your speech quickly.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your Party has already been permitted. Your Party's time is over. But I am giving time to you as a special case.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We want to adjourn the House at 9 O'Clock. I have consulted the Minister for Parliamentary Affairs. If every one speaks for five minutes, all of them can be covered. If you cannot speak for five minutes and take more time then some of your Members will have no chance and they will have to speak tomorrow.

When I say five minutes, then you must give only new points.

श्री राम स्वरूप राम (गया) : बिहार का रिप्रेजेन्टेशन भी नहीं हुआ है ।

श्री राम प्यारे पनिका : आपने यह तय किया था कि जिसको कल जाना है, वही आज बोलेगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I cannot run the House as per your convenience only.

SHRI RAM PYARE PANIKA: That was your decision.

MR. DEPUTY-SPEAKER: At 9 O'Clock I will adjourn the House. If you want to give chance to other Members then you stick to the timing. After all, all of us are sitting here from 4 O' Clock.

SHRI RAM PYARE PANIKA: I am going out of station.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must remain here tomorrow. You have to cancel that programme. This discussion is more important.

SHRI RAM PYARE PANIKA: Now you have changed your decision.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If I were in your position I shall speak without going anywhere else. You must show your devotion to your electorate.

Shri Ram Swaroop Ram.

श्री राम स्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम यहां सुखाड़ और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार कर रहे हैं । यह सिर्फ एक राज्य की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि सारे देश में अधिकांश प्रान्तों में बड़ी भयावह स्थिति है । माननीय सदस्यों ने बहुत ही विस्तारपूर्वक इसकी चर्चा की है, मैं मुख्यत: अपने प्रान्त बिहार राज्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

बिहार राज्य तीन भागों में बंटा हुआ है । गंगा के उत्तरी हिस्से को उत्तरी बिहार कहते हैं, उसके बाद कुछ समतल भूमि है जिसमें नवादा, गया, औरंगाबाद, पलामू आदि सब एरिया पड़ते हैं और उसके बाद छोटा नागपुर का पठारी एरिया पड़ता है ।

उत्तरी बिहार तो बाढ़ से भयंकर रूप से प्रभावित रहा और इसके साथ ही दुर्भाग्य यह भी रहा है कि वहां बाढ़

[श्री राम स्वरूप राम]

के तुरन्त बाद सुखाड़ का भी प्रकोप हुआ । हमारे दक्षिण बिहार में सुखाड़ 1967 से ही है । पिछले 16 बरस में हमारा बिहार राज्य 4 बार सुखाड़ के प्रकोप से प्रभावित रहा है । यह हमारी रिपोर्ट नहीं है बल्कि बिहार राज्य में जो सेंट्रल टीम कृषि मंत्री ने भेजी थी, उन्हीं को रिपोर्ट है--

during the last sixteen years the State has experienced four major droughts — in 1966-67, 1972-73, 1977-78 and 1979-80.

एक तो हम आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब और पिछड़े हुए हैं, नेशनल रिसोर्सेज का बहुत कम पैसा वहां खर्च हुआ है, बल्कि नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिये बहुत ज्यादा चीजें हम वहां से देते रहे हैं ।

हमारे श्री समर मुखर्जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिये कि क्या वह हमसे पानी नहीं ले जा रहे हैं ? पानी के सम्बन्ध में दक्षिण बिहार के साथ खिलवाड़ दामोदर वैली से नहीं कर रहे हैं ? उस पर बिहार सरकार और बंगाल सरकार के बीच कई बार मीटिंग्स हुई । लेकिन अभी तक बहुत सा बंगाल सरकार का बकाया बिहार सरकार पर है । माननीय सिंचाई मंत्री एवं कृषि मंत्री दोनों को मालूम है कि जो राज्य इतना पिछड़ा हुआ हो, जहां पर लगातार चार-चार बार सूखा पड़ा हो, प्राकृतिक आपदाएं आई हों और पुनः इस बार भी जो भयंकर स्थिति से गुजर रहा है, क्या उसको नजरअन्दाज किया जा सकता है । उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता । यहां पर माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हुए नहीं हैं । पिछली दफा बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट उनको भेजी थी, मुझे पता चला है कि वे इस बार 60 हजार टन गल्ला दे रहे हैं, जिसमें 20 हजार टन चावल और 40 हजार टन गेहूं बिहार को दिया जाएगा । वर्तमान में, हमारी रिक्वायरमेंट, जसे आंकड़े बिहार सरकार ने सैन्ट्रल टीम के सामने अपनी रिपोर्ट दी है, अनुशंसा की है, उसमें कहा गया है कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक करने के लिए, कम से कम एक लाख टन गेहूं और 50 हजार टन चावल प्रति मास दिया जाए । ताकि लोग अन्न के अभाव में भूख से मरें नहीं । साथ ही सैन्ट्रल एसिस्टैंस के रूप में 226.11 करोड़ रुपया भी हमको दिया जाए । हमारी बिहार सरकार ने ड्रौट से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए यह रिक्वायरमैंट्स रखी थीं । लेकिन उसके अनुपात में उसको कितना अन्न दिया जा रहा है । जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप सैन्ट्रल एसिस्टेंस के रूप में बिहार सरकार को कितना पैसा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तो हम उसको रिव्यू ही कर रहे हैं । आप ही बताइये, वहां कितनी भयानक परिस्थिति पैदा हो गई है और आप अभी तक रिव्यू ही कर रहे हैं । अभी हमारे पांडे जी स्टैटिस्टिकल फीगर्स देकर यह साबित करना चाहते थे कि हम बड़े प्रिविलेज्ड पोजीशन में हैं, बड़ी कम्फर्टेबल पोजीशन में हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि वे कहीं गुरु जी की पाठशाला वाला औसत तो नहीं निकाल रहे हैं । मैं सिर्फ एक-दो मिनट में वह साधारण सा वाक्या सुनाना चाहता हूं । एक लाला जी एक पाठशाला में गुरु जी थे । उनके 5 बच्चे थे । एक बार वे कहीं जा रहे थे । उनके रास्ते में एक नदी पड़ती थी । नदी को पार करने से पहले उन्होंने अपने पांचों बच्चों की लम्बाई का औसत निकाला, फिर पानी

को गहराई निकाली। उनके पांचों बच्चों की औसत लम्बाई 5 फीट 3 इंच आती थी, जब कि नदी की गहराई 5 फीट थी, उन्होंने सोचा कि इस हिसाब से सारे बच्चे नदी पार कर जायेंगे । लेकिन उन्होंने अपने सबसे छोटे बच्चे की लम्बाई पर ध्यान नहीं दिया कि क्या वह भी 5 फीट 3 इंच का है या नहीं। उन्होंने औसत निकाल कर यह सोचा कि इस हिसाब से तो सारे बच्चे पार हो जाएंगे । लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि उनका सबसे बड़ा बच्चा तो नदी पार कर गया और बाकी चार नदी में डूब कर मर गए । इसलिए कहीं हमारे मंत्री जी उन लाला जी वाला औसत तो नहीं निकाल कर हमें समझाना चाहते हैं । यदि ऐसी बात है तो यह बड़ी गम्भीर बात है। क्या उन्होंने लाला जी वाली स्टेटिस्टिक्स तो नहीं निकाला है। हमारे कृषि राज्य मंत्री जो बैठे हुए हैं, सिंचाई मंत्री जो बैठे हुए हैं, मैं उन से चाहूंगा कि जल्दी आप वहां का रिव्यू करवा लीजिए और प्रार्थना करूंगा कि जल्दी स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए वहां थोड़ी मदद पहुंचाइये।

हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी हमारे देश में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग प्रभावित होता है। उसके कारण खेतों में काम करने वाले किसान की हालत बड़ी खराब होती है। आज उसके पास क्रय शक्ति नहीं है । आप कितनी ही फेयर प्राइस शौप्स खोल दें, लेकिन जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो वह वहां से कैसे अनाज खरीद पाएगा। आज वह जौबलैस हो गया है । हमारे यहां ऐसे लोगों की आबादी 43 प्रतिशत है, जो लोग हरिजन या आदिवासी कहलाते हैं। बड़े बड़े किसानों की बात छोड़िये । बड़े किसानों में तो किसी के यहां वकालत होती है, किसी के यहां नौकरी होती है, किसी के यहां बिजनैस होता है। उन के यहां अगर किसी बार खेती नहीं होती तो वकालत से इन्कम हो जाती है, नौकरी से तनख्वाह आ जाती है या बिजीनैस से पैसे आ जाते हैं। लेकिन जिस आदमी की जीविका ही खेती पर निर्भर है, ऐसी स्थिति आने पर उसकी क्या हालत हो जाती है, उसकी आप कल्पना कीजिए । जब वह जाबलैस हो जाए तो उसकी स्थिति कितनी भयानक होगी। आपको इस स्थिति को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए।

आपने एन० आर० पी० प्रोग्राम क्यों बंद कर दिया । एक तरफ तो हमारे किसान के पास क्रय शक्ति नहीं है, खेतों में काम करने वाले जौबलैस हो गए हैं, और दूसरी तरफ आपने एन० आर० पी० प्रोग्राम भी बंद कर दिया। इसका उन लोगों पर क्या असर होगा । वे लोग गांव छोड़ कर शहरों की तरफ भागेंगे । जब शहरों में आयेंगे तो उनका शोषण होगा। एक और हमारी प्रधानमंत्री की नीति है कि आप रोजगार का माहौल उनके लिए बनाइये । एन० आर० ई० एस० जो आपका प्रोग्राम है कि हम उनको उठायेंगे, क्या आपका यह प्रोग्राम सार्थक हुआ है। उसके अन्तर्गत कितने परिवार ऊपर आये हैं? कोई परिवार ऊपर आया भी है या नहीं? आप आंकड़ों की खेती भले ही कर लीजिए आंकड़ों की इस खेती से बहुत दिनों तक काम नहीं चलेगा।

जब हम 1980 में जीत कर आये थे तो उस समय कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि पांच वर्ष के अन्दर जितने भी देश में प्राब्लम विलेज हैं उनमें से पेयजल का संकट हम खत्म कर देंगे। क्या

[श्री राम स्वरुप राम]

आप बतायेंगे कि हिन्दुस्तान के कितने गांवों को आपने अब तक कितनी कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। हमें ढ़ाई साल हो गये हैं और हमारे देश के सात लाख गांवों में से 60 प्रतिशत से भी अधिक गांवों में अभी भी पानी का संकट है। जो आप कहते हैं उसको करने की कोशिश करिये तभी यह लगेगा कि काम हो रहा है।

यह बड़ी खुशी की बात है कि बिहार के संकट को देखते हुए आपने वहां एक केन्द्रीय टीम भेजी । उस केन्द्रीय टीम के समक्ष बिहार सरकार ने जो अपनी सिफारिश की है, वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं। बिहार के लोगों की मदद करने के लिए वहां की सरकार ने यह अनुशंसा की है—

"As regards the requirements of foodgrains, it may be mentioned that in the year 1966-67, the State was in the grip of severe drought during the period of 15 months between October, 1966 and December, 1967. 22.4 lakh tonnes of foodgrains were distributed through the fair price shops."

इस में जो सेन्ट्रल असिसटेंश की बात कही गयी है, वह बिहार की 6 करोड़ आबादी को ध्यान में रख कर कही गयी है । अब बिहार की आबादी 10 करोड़ है । इसलिए इतनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए ही बिहार को असिसटेंश मिलनी चाहिए ।

बिहार में जो इस समय भयंकर सूखे की स्थिति है वह मुख्यत: गया, नवादा, औरंगाबाद और हमारे पार्लिया-मेंट्री मिनिस्टर के जिले पलामु में है । वहां की रिपोर्ट मंगा कर आप देखें कि वहां कितनी भयानक स्थिति है । लोग पेड़ के पत्ते खा कर गुजारा कर रहे हैं । पहले तो भदही की फसल हो गयी थी लेकिन इस समय तो भदही भी मारी गयी है । रबी की बुवाई तो हो नहीं सकेगी । हमारे मंत्री जो फिगर्स दे कर हमें इत्मीनान करा रहे थे ।

मैं सिंचाई मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार की दो-दो सिंचाई योजनाएं आपके मंत्रालय में पड़ी हुई हैं । आप थोड़ा जोर लगा कर उनको पूरा करा दें । आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने मुहाने रिजर्वायर के लिए चार बार प्रश्न किये जिसके आपने और आपके राज्य मंत्री जी ने भी जवाब दिये । उन्होंने कहा कि मार्च 1981 में मोहाना रिजर्वायर बहुत बड़ी योजना को कार्यान्वित किया जाएगा, जिससे गया, नवादा, औरंगाबाद को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी । कहा गया था कि सेन्ट्रल वाटर कमीशन से इसको क्लीयर करा देंगे, लेकिन जब मैंने रिपोर्ट को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ ।

अन्त में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा । बजट के समय मैंने कहा था कि क्राप इंशोरेंस स्कीम लागू की जाए । आज कहीं कोई वाहन-दुर्घटना होती है तो उसको पूरा पैसा मिल जाता है, कहीं फैक्ट्री में कोई दुर्घटना होती है तो उसको भी पूरा पैसा मिलता है, लेकिन खेती के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप चाहे बड़े किसानों के लिए इसको लागू न करिए, लेकिन 5 एकड़ से कम खेती वाले किसानों पर इसको अवश्य लागू करिए, नहीं तो किसान मेहनत भी करता रहेगा और भूखों भी मरता रहेगा । खेती को इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए । जब तक यह काम नहीं किया जाएगा तब तक किसान की स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता । अगर सिर्फ स्टेटिसटिक्स की बात की जाएगी तो

इसी तरह से सब अपनी बात कहकर घर चले जाएंगे और उससे कोई फायदा नहीं होगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

बिहार सरकार ने केन्द्रीय टीम के समक्ष जो अपनी सिफारिशें रखी हैं, उनके तहत शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जाए, ताकि वहां लोगों को राहत मिल सके ।

सुखाड़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सारे कर्जों की वसूली रोक दी जाए । चाहे वे बैंक के कर्जे हों, तकावी लोन हों या अन्य कोआपरेटिव सोसायटीज के कर्जे हों । इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लेबरर हैं उनको कम से कम 100 रुपए की तत्काल सहायता दी जाए, चाहे उसे वसूल करने का प्रावधान भी रखा जाए, लेकिन अभी उनको यह सहायता शीघ्र दी जाए, ताकि वे भूख से मरने से बच सकें । इसका असर अभी इतना नहीं पड़ेगा, जितना दिसंबर के बाद पड़ेगा । काफी भयंकर स्थिति उत्पन्न होने वाली है ।

एन० आर० पी० के कार्यों को तत्काल शुरू किया जाए ताकि मजदूरों को काम मिल सके ।

डिसेवल परसन्स ओल्ड एज के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए ।

सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाइए और इसके लिए युद्ध स्तर कार्यवाही करें । माइनर, मीडियम और मेजर योजनाएं बनाकर सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए ।

एक चीज और कहना चाहता हूं। श्री के० एल० राव ने एक रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी । उन्होंने कहा था कि गंगा के पानी को, गेंजेज वाटर को यूटीलाइज करके साउथ बिहार में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकती है । मैं समझता हूं कि यह बहुत लाभकारी योजना होगी । इसलिए मेरा सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध है कि वे के० एल० राव की रिपोर्ट को देखें और इस योजना को कार्यान्वित करवाएं ।

आशा है मेरे सुझावों पर मंत्री महोदय अवश्य ध्यान देंगे, अन्यथा सिर्फ स्टेटिसटिक्स में उलझने से कोई काम नहीं होगा ।

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : माननीय उपाध्यक्ष जी मैं और तमाम बातों में न जाते हुए सिर्फ इतना ही जिक्र करूंगा जिसके बारे में केन्द्र सरकार अन्धेरे में है । और वह यह कि गुजरात में आज अकाल की परिस्थिति चल रही है । गुजरात में 18 हजार गांवों में से 9 हजार से अधिक गांवों में अकाल की स्थिति है । कुछ दिन पहले केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री जी ने अकाल की परिस्थिति के बारे में इस सदन में जिक्र किया था लेकिन इसके बारे में उल्लेख तक भी नहीं हुआ था । अकाल की परिस्थिति के बारे में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में कैसा व्यवहार चलता है, इसका यह नमूना है । इस लिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी केन्द्र सरकार की टीम गुजरात में जाए क्योंकि वहां अभी आधे हिस्से में अकाल की स्थिति है । वहां पशुओं के लिए घास की कमी है । आप अमेरिका से गेहूं मंगवाकर लोगों को खिलयेंगे लेकिन पशु जो कि कृषि के लिए जरूरी है, उसे कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे कृषि की जायेगी । बैलों के लिए, पशुओं के लिए घास की तंगी का सवाल सबसे ज्यादा महत्व का है । इस तंगी को दूर

[श्री मोतीभाई आर० चौधरी]

करने के लिए जो प्रावधान करना जरूरी हो, वह जल्दी से जल्दी किया जाए ।

मेरी दृष्टि में अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए जरूरी चीज यह है कि बिजली की कमी दूर की जाए। बिजली की कमी के बारे में भी केन्द्र सरकार घोर अन्धेरे में चल रही है । कुछ दिनों पहले ऊर्जा मंत्री ने यह सदन में बताया था कि बिजली की स्थिति गुजरात में सबसे अधिक अच्छी है । 50 प्रतिशत कमी आज गुजरात में चल रही है । दिन में उद्योगों को बिजली नहीं मिलती है । कृषि के लिए दिन में बिजली देने का तय किया है, लेकिन आज कृषि को न दिन में न रात में बिजली मिलती है । बार-बार बिजली बन्द होती है, वोल्टेज कम होता है । जिससे कृषकों की बिजली की मोटरें जल जाती हैं । रबी के मौसम में कृषि के लिए बिजली बहुत जरूरी है । खरीफ तो एक आखरी बारिश न आने से अकाल-ग्रस्त हो चुका है ।

हमारे यहां तो ऐसी कोई बड़ी नहर नहीं है जो बारहों मास पानी देती रहे । इस से बिजली द्वारा ट्यूब-वैल से सिंचाई करनी पड़ती है इसलिए बिजली अधिक महत्व की है । रबी सीजन के लिए हमारे यहां जो नर्मदा योजना है, उससे तीव्र गति से काम चलता नहीं है । ऐसे कई सूखाग्रस्त जिले हैं वहां इसका पानी जाने वाला है । हमारी अगर नर्मदा की योजना पूरी हो जाए तो दो-तीन साल तक अकाल पार उतर सकता है । यह कहा है कि विश्व बैंक की टीम आने वाली है, कब आयेगी ? कब इनको पैसा मिलेगा ? और कब योजना चलेगी ? हमको पता तक नहीं है । उसे भी अधिक तीव्र गति से उठाया जाय । हमारे लिए जरूरी चीज है फिलहाल वह यह है कि बिजली हमको निश्चित रूप से मिलनी चाहिए । अब रबी का सीजन आ रहा है । उन 15 दिन में बुआई का काम शुरू हो जायेगा । किसानों को दिन में निश्चित रूप से कितनी बिजली मिलती रहेगी, इसके बारे में जल्दी से जल्दी तय होना चाहिए । 25 लाख टन गेहूं इस बार मंगाना जरूरी हुआ तो अगले साल के लिए 50 लाख टन मंगवाने पर भी हमारा काम नहीं होगा अगर किसानों को समय पर निश्चित रूप से बिजली नहीं मिलती । तो इसलिए, मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार बिजली के बारे में गुजरात सरकार को बराबर मदद करे ताकि कृषकों को बिजली मिलती रहे ।

दूसरी बात मैंने पशुओं को घास देने के बारे में कही थी । इसके बारे में बराबर ध्यान रखा जाए, जल्दी से जल्दी केन्द्रीय टीम भेजी जाए और उसके बाद पीने के पानी का भी सवाल जल्दी से जल्दी उठाना होगा । पांच सौ से हजार फीट नीचे से कई गांवों में पीने का पानी खींचा जाता है और वह ट्यूबवैल के जरिए आता है । पूरे चौबीसों घंटे बिजली मिलती नहीं है तो लोग पानी कैसे पीएंगे । इसलिए, पीने का पानी निकालने के लिए बिजली का प्रावधान किया जाए और पीने के पानी की व्यवस्था जगह-जगह जल्दी से जल्दी हो और नए कुएं लगाए जाएं । टैंकरों से भी गांवों में वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये । इन सब बातों में केन्द्र द्वारा गुजरात की ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मदद की जाए यही मेरा निवेदन है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Keyur Bhushan. He will be followed by Shri Panika. After five minutes, you may get up and begin to speak. I shall give you

only five minutes. You must give the chance to all the others.

Otherwise I shall adjourn the House.

श्री कँवूर भूषण (रायपुर) : हर एक प्रांत के माननीय सदस्यों ने अपने अपने प्रांत में सूखे और बाढ़ की जो स्थिति है वह आपके सामने रखी है । विशेषकर बंगाल के साथियों ने बहुत ही कारुणिक ढंग से और आंकड़े देकर अपने यहां की स्थिति को आपक सामने रखा है । हो सकता है कि हम उस ढंग से अपने यहां कि स्थिति को संगठित रूप से रख न सकें क्योंकि हमारे प्रांत के सभी साथी यहां पर एकत्रित नहीं हो पाए हैं ।

सिंचाई मंत्री और कृषि मंत्री के पिछले भाषणों को पढ़ने का मुझे अवसर मिला है । उन्होंने बताया था कि सूखे के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का स्थान नहीं है । लेकिन स्थिति उससे बिल्कुल भिन्न है । अभी भी पूर्वी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का है सूखे से पीड़ित है । उसका कुछ हिस्सा बाढ़ के कारण पीड़ित रहा है । शुरू में काफी वहां बारिश हुई जिससे नुकसान हुआ लेकिन उसके बाद एक दम वहां सूखा पड़ा । जो बीज थोड़ा बहुत तैयार हुआ था, जो फसल थोड़ी बहुत तैयार हुई थी, अंकुरित हुई थी इस वजह से वह सारी की सारी मारी गई । फिर से उनको बीज की आवश्यकता पड़ गई है । कई ऐसे किसान हैं जो बीज की कमी के कारण अपने खेतों में फिर से उत्पादन नहीं कर सके हैं और अनायास ही एक भयंकर स्थिति उनके सामने आकर खड़ी हो गई है । वर्षा होने के बाद भी पचास प्रतिशत से भी अधिक किसानों के सामने गांव छोड़ कर भागने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । वह पूरा का पूरा क्षेत्र एक फसली क्षेत्र है और केवल धान की पैदावार वहां होती है । धान के पकने के समय पानी नहीं मिलता है तो सारी की सारी उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है । लोगों के सामने भुकमरी की स्थिति आ गई है । मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा भुखमरी से पीड़ित है लेकिन फिर भी मात्र तीन करोड़ की सहायता ही उसको दी गई है । जिस व्यापक पैमाने पर राहत कार्य वहां खोले जाने हैं उसको देखते हुए यह बहुत कम राशि है । वहां इस वर्ष पचास करोड़ से भी अधिक का नुकसान किसानों को हो चुका है । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वहां जो छोटे लोग हैं, खेत मजदूर हैं उनकी स्थिति दयनीय हो गई है और यह ठीक भी है । पता नहीं एक दो महीने के बाद क्या होने वाला है । जहां पर दूसरी फसल की खेती हो सकती है, गेहूं की खेती हो सकती है वहां तो स्थिति फिर भी सुधर सकती है लेकिन यहां तो धान नहीं हुआ तो दूसरी किसी फसल की सम्भावना भी खत्म हो जाती है । आज भी वहां लोग मकानों पर ताले लगा कर अन्यत्र चले गए हैं, दिल्ली में आ गए हैं । छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर के लोग हजारों की तादाद में यहां फैले हुए आपको मिल जायेंगे । ये वहीं के लोग हैं जिन्हें वहां रोजी और मजदूरी बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी । एशियाड में जिन लोगों द्वारा काम किया जा रहा है, मजदूर जो इस पर काम कर रहे हैं ये ज्यादातर उसी क्षेत्र के लोग हैं । पंजाब, हरियाणा तथा दूसरे स्थानों में भी उसी क्षेत्र के लोग व्यापक रूप से काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं । राहत कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा आप मध्य प्रदेश की सरकार को दें ताकि वहां लोगों को काम मिल सके ।

मेरा सिंचाई मंत्री जी से एक विशेष निवेदन है । एक बार वह उस क्षेत्र का जा कर अवश्य दौरा कर लें तो उनको पता लग जाएगा कि किस कद्र वह क्षेत्र पीड़ित है । महानदी का उद्गम स्थान वहीं पर उस क्षेत्र में है । महानदी के पानी के कारण उड़ीसा में बाढ़ का प्रकोप हो जाता है और बहुत ज्यादा नुकसान उड़ीसा में होता है । उस पानी को वहीं पर रोका जा सकता है । दस साल तक सर्वेक्षण कार्य उस क्षेत्र में हुआ है । तीन चार बड़ी नदियां हैं । उन्हीं के बहाव

[श्री कैयूर भूषण]

के कारण उड़ीसा में बाढ़ का प्रकोप होता है। वहां बांध बनाने का काम जिस का सर्वे हो चुका है, पूरा किया जाना चाहिए। अगर इसको पूरा नहीं किया गया तो न केवल यह पानी छत्तीसगढ़ को उजाड़ कर रख देगा बल्कि उड़ीसा को भी उजाड़ कर रख देगा। इस स्थिति को बचाने के लिए मेरा निवेदन है कि युद्ध स्तर पर छोटी और बड़ी योजनाओं को शुरू करना चाहिए, और ढलान पर पानी को रोक कर जो आदिवासी और हरिजन क्षेत्रों के अन्दर हैं, जहां बारिश अधिक होती है मगर रोकने का कोई साधन नहीं होता, इन छोटी छोटी योजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष ध्यान दें तो अच्छा रहेगा।

श्री राम प्यारे पनिका : (राबर्टसगंज): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सब गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी माननीय सदस्यों ने जो विभिन्न विचार सूखे और बाढ़ के सम्बन्ध में रखे हैं मैं उन मदों को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन एक बात की ओर सिंचाई और कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में यदि आप बाढ़ की गम्भीरता को देखें, 14 राज्यों में जो बाढ़ आयी है और उससे नुक्सान हुआ है उसका टोटल है 76.356 लाख हैक्टर जमीन, उसमें से 49.40 लाख हैक्टर जमीन अकेले उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित हुई है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं और हमारे यहां 57 जिलों में से 43 जिले प्रभावित हैं, 2 करोड़ 11 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और मेरे क्षेत्र में 8 ब्लाक्स प्रभावित हैं, जैसे सीखड़, नारायणपुर, पहाड़ी, सीठी, मझवा, जमालपुर, छानवे, कोन जिले के शेष 12 ब्लाक्स बाढ़ से प्रभावित हैं, और अब यह भी सूखे से प्रभावित हो रहे हैं। किस तरह से बाढ़ के समय औरतों और बच्चों ने तकलीफ उठायी है उसको सुन कर आंखों में लोगों के आंसू आ जायेंगे। महलियें 11, 12 रोज तक पानी में खड़े खड़े टट्टी करती थीं। खाना पीना तो दूर रहा। सबसे भयंकर बात इसलिये भी हुई कि इस साल बाढ़ का ठहराव 15 रोज तक रहा। इसलिये आप अनुपात में जितना हिस्सा उत्तर प्रदेश का आवे उसके अनुसार राहत दें। और जो गंगा नदी का कटाव हो रहा है हर साल मिर्जापुर में उसको रोकने के लिये हमारी प्रदेश सरकार ने एक योजना भेजी है उस योजना को आप कार्यान्वित करें। कई लोगों ने कहा कि सरकार गम्भीरता से नहीं सोचती। लेकिन मेरा कहना है कि हमारी प्रधान मंत्री कृषि और सिंचाई मंत्री ने दौरा किया और तात्कालिक सहायता सरकार ने मुस्तैदी से दी, जिला प्रशासन अधिकारियों ने काफी सहायता की।

अब मैं दो प्रकार के सुझाव देना चाहता हूं। तात्कालिक समस्या का निदान जो कुछ हुआ हो गया। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि दीर्घकालिक रूप से कैसे इस समस्या का मुकाबला करें इस पर हमें विचार करना है। माननीय सिंचाई मंत्री ने कुछ सुझाव दिये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनके लिये सबसे जरूरी सुझाव यह है कि तत्काल प्रत्येक गांव सभा के स्तर पर आप एन० आर० ई० पी० कार्यक्रम को चलायें। प्रधान मंत्री के नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक 2,000 यूनिट पर एक राशन की दुकान खोलने की बात कही गई है। आप कहते हैं कि राशन बहुत है, लेकिन इन्टीरिय भागों में लोगों को राशन नहीं पहुंच रहा है। इसलिये मेरी मांग है कि र 2,000 यूनिट पर चाहे सरकार या गैर सरकारी ढंग से राशन की दुकान खोलें।

इसके अलावा जहां किसान सूखे से प्रभावित हैं उनका लगान, सिंचाई कर तथा अन्य प्रकार के जो कर हैं उनको न केवल स्थगित करें, बल्कि उनको माफ करें । और किसानों पर जो ट्रैक्टर या अन्य कृषि साधनों के कर्जे हैं उनकी किस्त आगे बढ़ा दें और सूद माफ करें तभी किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है ।

बाढ़ में सड़कों, पुलों, नहरों और सरकारी भवनों की जो बहुत बड़ी क्षति हुई है उनकी मरम्मत और निर्माण के लिये सहायता देना बहुत जरूरी है । अभी तकावी के रूप में प्रदेश सरकार घर के गिरने पर केवल 100,50 रुपये दे रही है, उसको भी 1000 रुपये से 5000 रुपये किया जाना चाहिये ताकि वह घर खड़े किये जा सकें ।

बाढ़ के क्षेत्र में चारे की बहुत कमी है, पशुओं के लिये चारा पहुंचाना होगा । भविष्य में जब बाढ़ आवे तो हरेक ग्राम सभा में कम से कम एक नाव देनी होगी और बाढ़ वाले इलाके में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कम-से-कम एक स्टीमर देना होगा ताकि संकट की घड़ी में वह सामना कर सकें ।

सूखे के लिये पिछले कई वर्षों से डी पी ए पी के कार्यक्रम चलाये जा रहे थे आज उन कार्यक्रमों को देखा जाना चाहिये कि क्या कुछ हो रहा है या नहीं। जिस भावना से कार्यक्रम शुरु किये गये थे वह नहीं हो रहे हैं । उसके अन्तर्गत जो सिंचाई की योजनाए बनी थीं, कनांड एरिया नहरों का नही हो रहा है, इसलिये मैं चाहता हूं कि जो सिंचाई योजना हाथ में ली गई है, उनका काम होना चाहिये । हमारे मिर्जापुर में क्या हुआ है, उस काम को समय से पूरा कराइये । अगर स्टेट गवर्नमेंट उसके लिये पैसा नहीं दे रही है तो आप उस कार्य को पूरा कीजिये ।

जहां पर आई आर डी और कम्पोनेन्ट के कार्यक्रम हैं उनको भी सरकार को समय पर पूरा कराने की व्यवस्था करनी चाहिये ।

सूखे में भी हमारे 39 लाख हैक्टर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं । हमारी बंगाल की बहिन कह रही थीं, यह बात सही है वहां भी बहुत कटिनाई है, हमारे उत्तर प्रदेश के सदस्य बहुत कम बोले हैं, मैं प्रदेश की जनता और वहां की सरकार की तरफ से मांग करता हूंकि जो केन्द्रीय टीम, वहां गई थी, उसकी रिपोर्ट के अनुपात से आप बाढ़ व सूखे के लिये सहायता दें, तभी हम उत्तर प्रदेश की जनता को बचा सकेंगे । धन्यवाद ।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो समस्त बिहार आज सूखे और बाढ़ से प्रभावित हुआ है किन्तु बिहार के 33 जिलों में 20 जिले इस बार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । उसमें सबसे ज्यादा क्षति सारण और सिवान जिले को हुई है जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है । स्वयं सिंचाई मंत्री ने सारण जिले का दौरा किया है और वह वहां की हालत अपनी आंखों से देख चुके हैं कि किस तरह से सारण जिले के लोग तबाह हुए हैं । जहां आज तक कभी बाढ़ नहीं आई थी, वहां भी इस बार इसके कारण बुरी तरह लोग प्रभावित और तबाह हुए हैं ।

सिंचाई मंत्री एम-बैंकमैंट बनाने की बात जब कह रहे थे, तो मैं आशा करता था कि जो आश्वासन वह वहां के नागरिकों और अधिकारियों के बीच दे

[श्री कृष्ण प्रताप सिंह]

आये हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे । वहां सिंचाई मंत्री जी ने कहा था कि डुमरी से छपरा तक और छपरा से सोनपुर तक हम गंगा पर एमबैंकमैंट बनायेंगे और सारण व सिवान जिला जो बाढ़ से प्रभवित होता है, इस पर नियंत्रण करेंगे । मैं आशा करता हूं कि आप इस सदन में आश्वासन दें या न दें, किन्तु आप इस पर जरूर कार्यवाही करेंगे ।

दो, तीन बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक तो हमारे क्षेत्र में एक सितावदियारा गांव है जहां स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि है, प्रतिवर्ष वहां बाढ़ आती है और वहां के लोगों को दूसरी जगह जाकर शरण लेनी पड़ती है : वहां योजना बनी थी कि हर गांव में, दस-दस जगह गांव बसे हैं, हर जगह एक ऊंचा प्लेटफार्म बनाया जाये ताकि बाढ़ के दिनों में लोग अपने मवेशी वगैरा लेकर वहां रह सकें । उसमें कुछ काम 1980 में पहले हुआ था, हम आग्रह करेंगे कि इस बारे में स्थायी रूप से उन गांवों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । दूसरे मैं यहां पर फ्लड कमीशन की बात करना चाहता हूं । सारण जिले की ड्रेनेज स्कीम बहुत दिनों से लम्बित पड़ी हुई है । अच्छी बात है कि आप एक प्रोपोजल बना कर, वहां के लिए एक नेशनल प्रोजक्ट बना रहे हैं । परन्तु जो छोटी-छोटी स्कीम्स वाटर कमीशन के पास लम्बित पड़ी हुई हैं, हम आपसे उनकी स्वीकृति जल्दी दिए जाने के लिए आग्रह करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, वहां पर एन० आर० पी० का काम करवायें । इस स्थिति से निपटने के लिए हमारी बिहार सरकार ने जितनी 226 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है, उस सहायता को दीजिए ताकि राज्य सरकार इस भयंकर सूखे की स्थिति का सामना करने में सफलता पा सके । इसके साथ ही, जितने गल्ले के आवंटन की मांग की गई है, उसको भी दीजिए ताकि उससे प्रभावित क्षेत्रों में सस्ते रेट की दुकानों के जरिए लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, उनको भूख से बचाया जा सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष जी, मैं अपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी । उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं यहां खास कर सुखाड़ के बारे में बोलना चाहता हूं । हमारे देश में काफी वर्षा होती है । अभी माननीय मंत्री जी ने यहां पर आंकड़े प्रस्तुत किए । हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन वह सारे का सारा क्लाइमेट पर डिपेंड करता है । जब तक हम क्लाइमेट पर निर्भर रहेंगे, उससे लड़ कर, संघर्ष कर के प्राकृतिक विपदाओं का सामना नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता । हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, वह ऐसी ही बनी रहेगी । हमारे देश में हर तीन वर्ष के अन्दर किसी न किसी साल अकाल पड़ता है । कहीं अकाल पड़ता है, कहां सूखा पड़ता है तो कहीं तूफान आता है । कहीं बरसात ज्यादा होती है । यदि हम इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित एरियाज में कोई स्कीम बना कर राहत कार्यों को चलायें तो संभव है हम क्लाइमेट के विरुद्ध लड़ कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं । ऐसी योजना मंत्री

जी को बनानी पड़ेगी । उपाध्यक्ष महोदय, जिन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है, फ्लड आ ता है, उसका मेन कारण हमारे पहाड़ों पर वृक्षों का काटा जाना है । आज सारे पहाड़ नंगे हो गए हैं, जिसके कारण हमारी नदियों में पानी पूरे बहाव के साथ आता है और नदियों का पानी बाढ़ का कारण बनता है । यदि हम पहाड़ों पर वृक्ष लगायें तो संभव है काफी हद तक बाढ़ को रोका जा सकता है । फिर जितनी वृक्षों की पत्तियां सड़ेंगी, उतना ही किसानों के लिए खाद बनेगा और अच्छी पैदावार हो सकती है । इसलिए मैं मंत्री जी से चाहुंगा कि वे इस सम्बन्ध में कोई प्लान तैयार करें, ताकि हम अधिक से अधिक पेड़ों को लगा कर बरबादी को रोकें ।

ऐसे ही, हमारे यहां कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां प्रति तीन वर्ष में एक बार औसत सूखा पड़ता है । कहीं-कहीं 5 साल में और कहीं 10 साल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है । जब तक आप उन इलाकों के लिए कोई परमानेंट प्लान नहीं बनाऐंगे, तम तब समस्या हर बार हमारे सामने आती रहेगी और उसका समाधान नहीं होगा । मेरे डिस्ट्रिक्ट झाबुआ में बहुत से आदिवासी रहते हैं और पिछले 10 सालों से लगातार सूखा पड़ता आ रहा है । वहां की आबादी 8 लाख है, जिसमें से एक लाख लोग मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं । यदि ऐसे डिस्ट्रिक्ट के लिए आप कोई परमानेंट प्लान नही बनायेंगे, तब तक सूखे की समस्या हल नहीं हो सकती । वहां पर एक महानदी है । वह बहुत ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, इन्दौर से दाहा तक रेलवे लाइन भी बनी हैं लेकिन वहां हर साल सूखा पड़ता रहता है । मैं चाहूंगा कि आप उस नदी पर डैम बनाने का कार्य आरम्भ करें ताकि वहां के लोगों को मजदूरी मिले । आज उनके सामने पेट भरने का सवाल है, मजदूरी का सवाल है । वे आप से कोई कालेज या कृषि फार्म नहीं मांग रहे हैं । बल्कि हम तो आपसे सिर्फ दो टाइम का खाना मांगते हैं । हम जैसी मक्की की रोटी खाते हैं, हमको वही मिल जाए । उसकी मंत्री जी व्यवस्था करवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

राज्य सभा में एक स्टेटमेंट देते हुए हमारे मंत्री जी ने—सूखे के बारे में आंकड़े दिए, मगर उसमें मध्य प्रदेश का वर्णन नहीं है । उन्होंने मध्य प्रदेश के सूखे के बारे में कुछ नहीं कहा । मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 50 प्रतिशत जिले सूखे से प्रभावित हैं । वैसे अभी हमारे माननीय सदस्यों ने मध्य प्रदेश के बारे में बताया । वहां जिन स्थानों में सूखा पड़ता है वे क्षेत्र हरिजन और आदिवासी लोगों के हैं । वे लोग पहाड़ों पर खेती करते हैं । यदि किसी वर्ष बरसात नहीं होती तो उनकी सारी की सारी फसल सूख जाती है । करीब-करीब वह सारा एरिया सूखे का शिकार रहता है । इसलिए जब तक वहां पर सरकार की ओर से किसी प्रकार के राहत कार्य आरम्भ नहीं किए जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा । दूसरी बात मैं रुरल डैवलपमेंट के बारे में कहना चाहता हूं । आधे से अधिक जिले सूखे से प्रभावित हैं । मध्य प्रदेश के पहाड़ी एरिये में बहुत सूखा पड़ता है । हरिजन और आदिवासी लोग पहाड़ों में खेती करते हैं वहां सारी की सारी फसल सूख गयी है । हमेशा ही यह फसल सूख जाती है । मेरे तो सारे के सारे एरिये में सूखा पड़ा हुआ है । जब तक आप उस एरिये में निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे तब तक उन लोगों का काम नही चलेगा, उन लोगो को रोजगार नहीं मिलेगा ।

[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीमें हैं उनमें बहुत सारे ग्राम पंचायत के लोगों को काम दिया गया है। मगर वहां पर गरीबों के लिए जो पैसा भेजा जाता है वह गरीबों के पास न पहुंच कर दूसरों की जेब में जाता है। जब तक आप इस पैसे को प्लान और योजना बना कर खर्च नहीं करेंगे तब तक गरीबों का विकास नही हो सकता है। हमारा आज तक का अनुभव है कि हम गरीबों के नाम से जो पैदा देते हैं वह पैसा कहां कहां और किस-किस की जेब में जाता है। इस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए तभी उन लोगों का भला हो सकता है, किसानों का भला हो सकता है, गरीबों का भला हो सकता है।

आज बिजली की बात भी आयी कि किसानों को बिजली मिले। जब तक आप किसानों को टाइम पर बिजली नहीं देंगे तब तक किसान फसल नहीं बो सकता है और उसका भला नही हो सकता है। इसी प्रकार से आप किसानों को ऋण देते हैं लेकिन किसान की जब इकोनामी ही ठीक नहीं है, वह पैदा ही कुछ नहीं कर पा रहा है तो वह कर्जे की अदायगी कैसे करेगा। आप उसके कर्जे का कंवर्शन कर देते हैं लेकिन जब उसकी खेती में पैदावार ही नहीं होगी और उसकी इकोनोमी ही ठीक नहीं रहेगी तो वह कर्जा कैसे चुका सकता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उनका कर्जा माफ करें तभी किसानों का भला हो सकता है।

मैं आपसे यह भी कहूंना चाहूगा कि मध्य प्रदेश में आपको तीन सर्वे टीम भेजनी चाहियें। वहां के शासन ने जो रिपोर्ट आपको भेजी है और उसमें जितना पैसा मध्य प्रदेश शासन ने मांगा है उतना पैसा आपको मध्य प्रदेश शासन को सूखे से निपटने के लिए देना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री गोविन्द प्रसाद अनुरागी (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान बिलासपुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी एक, दो और तीन अक्तूबर को मैं अपने क्षेत्र बिलासपुर जिले में गया था। वहां पर मुझे सब गरीब लोग मिले, साथ ही साथ गर्भवती महिलायें भी मिलीं। वे मुझे यह कहने लगीं कि हम पहाड़ से कड़ुआ कांड़ा लाकर और उसे ऊसन कर खाते हैं और इससे गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होने और उनके मरने का डर है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि भूख से कोई नहीं मरा है। मंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भूख से हम किसी को मरने नहीं देंगे। मैं अपने क्षेत्र की शंका आपके सामने रख रहा हूं कि वहां गर्भवती महिलओं की क्या हालत हो रही है इस कड़वा कांडा को खाने से। मैं कल फिर वहां अपने क्षेत्र में जा रहा हूं।

आपने मुझे तीन मिनट दिए हैं इसमें मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। आप मुख्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह को तत्काल यह आदेश दीजिए कि वे युद्धस्तर पर जहां-जहां भयंकर अकाल है राहत कार्य खोलें। दूसरे मेरा सुझाव है कि देश की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए खडिया टेंक और खदाघाट टेंक की क्षमता को अहिरन नदी को डाइवर्ट करके बढ़ा दिया जाए इससे सिंचाई में बढ़ौतरी होगी। तीसरे महानदी, हसदेव, अरपा एवं हाप, को मिला कर एक कम्पोजिट योजना बायी गयी है जिसके प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के माध्यम से विश्व बैंक को भेजे जा चके हैं, विश्व बैंक के विशेषज्ञों के अनेक दल इन योजनाओं का

निर्धारण कर चुके हैं और वे राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही से पूरी तरह सन्तुष्ट हैं। इस योजना के लिए आप 150 करोड़ रुपए की मंजूरी देने की कृपा करें ताकि इस कार्य को पूरा किया जा सके। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं वहां पर लोगों को आश्वासन देकर आया हूं कि आप लोगों के लिए जरूर कुछ न कुछ किया जाएगा। अगर भूख से एक भी आदमी मर गया तो यह उचित नहीं होगा। मुझे धीरज नहीं है, मैं अधीर हो रहा हूं। मुझे आशंका है कि उन सैकड़ों गर्भवती महिलाओं के गर्भ की रक्षा कैसे हो सकेगी। वे गर्भवती महिलायें कह रही थीं कि हमारे गर्भ की रक्षा करिए, कड़आ कांदा से हमें बचाइए। मैंने उस कड़ए कांदे को प्रधान मंत्री जी की टेबल पर भी रखा है और उनसे भी निवेदन किया है कि आप युद्धस्तर पर राहत कार्य शरू करवाइए।

मैंने तीन मीनट का समय मांगा था और अपने वचन का पालन कर रहा हूं और इस आशा के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि सरकार बिलासपुर जिले में राहत कार्य प्रारम्भ करवाएगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I hope Mr. Mallu will also set an example by taking only five minutes.

SHRI ANANTHA RAMULU MALLU (Nagarkurnool): Let me convey my thanks to the Speaker and the Deputy Speaker, in particular, for having allowed a special discussion on this particular subject. Drought has become a routine and regular problem in the country. Every year we have been discussing this problem in this august House, and we have been making long speeches; and several assurances are also being given by the hon. Ministers. I do not say that nothing is being done. But, at the same time, we are forced to repeat the same requests every year.

Some permanent measures shall have to be taken, to put an end to drought situation in the country. Andhra Pradesh and Rajasthan have become a continuous target for drought. Ninety per cent of the rain water is becoming a waste, and going to the sea. Our plans are not in a proper manner. A proper plan will have to be made to preserve this rain water. Then only we will be able to face this drought situation in the country.

I do not like to go on discussing about the other States' problems. As far as my State, Andhra Pradesh is concerned, it has submitted its Memorandum long back. An alarming situation is there, and several reports have been published in the Press; but even till to-day it is unfortunate to know that the Central team has not visited there. And I have seen in the Press that it is going to visit Andhra within one or two days. But this is not a news suddenly coming. It is there for the last one month. We have been seeing every day in the papers that Andhra is being severely affected by drought. Our hon. Deputy Minister Mr. Mallikarjun who represents Mahbubnagar of Andhra Pradesh has visited; and he has also reported the matter. Unfortunately, in spite of our repeated representations and also submission of a Memorandum by the State Government, the Central Government has not come to the rescue of the State in particular.

Rayalaseema has become a problem every time. I received a reply from the Minister of Agriculture stating that Bihar and other States have also submitted memoranda; and Andhra has also done it. But he was pleased to say that the Central teams had visited other States—but not Andhra. I have a grievance even to-day. My only submission is: Try to understand the situation in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is called 'Annapoorna'.

I would like to say this specifically to the Minister of Agriculture: Rs. 200 crores have been sought by Andhra Pradesh. Whenever drought or floods or some other situation is there in the country, generally Government of India used to release funds only from out of plan funds, and then deduct them from the

[Shri Anantha Ramulu Mallu]

allocations to the State. Unless you have a special fund for this particular purpose, it is highly impossible to meet the needs and demands of the situation. I suggest that the Government of India should think in those terms and try to allocate special funds, other than regular allocations; otherwise, it is highly impossible to meet the needs of the people.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must take it up with the Finance Commission.

SHRI ANANTHA RAMULU MALLU: I am not such a big man to go and represent the matter to the Finance Commission. My hon. Minister for Agriculture, Rao Birendra Singh happpens to be a champion of this cause. He happens to be an agriculturist. He knows the problem. I am sure that he will certainly take up this cause with the Finance Commission, and see that something is done in this regard.

Coming to Rayalaseema, regarding cattle possession, the position is very bad. I cannot say anything in this august House. The cattle are being sent to the slaughter houses. Some of the big farmers who do not like to send their cattle are appealing to others to take their cattle. This is the position in Rayalaseema and my district Mahbub Nagar.

A part of the Telegana district is being severely affected by this drought. The problem has become very severe. In my Assembly Constituency, we haev to take water from 2-3 kms. away and serve the people there. This is the problem now itself. We cannot imagine if the summer comes what will happen to the people.

The agricultural labour problem is also very severe. My constituency area which is the most backward area has been declared as a drought prone area. DPA programmes are being taken up in the district. This district has been notified as the drought prone district right from the inception. The rivers Krishna and Tungabhadra pass through my district. It is most unfortunate that we cannot make use of a drop of water of the River Krishna. The Andhra Pradesh Government has been representing about this particular problem. At the Farmer's Conferences, at the Labour Conferences, we have submitted several representations to the Government. I myself have submitted representation to the hon. Prime Minister. She was kind enough and addressed a letter to the Minister of Irrigation asking him to take up the projects in the district. I am particularly referring to Bhima and Jurala Projects in Andhra Pradesh. As regards the Jurala Project, the former Chief Minister, Mr. Anjiah laid the foundation-stone. He said, he will certainly take up the projects and within 15 years it will be completed. But this year, the allocation is not even Rs. 1 crore. If this is the position, we cannot imagine that even in 100 years the project will come up. Bhima Project is a joint project. Whenever we ask the Andhra Pradesh Government, they say that they have referred the matter to the Karnataka Government and the Karnataka Government say that they are seriously discussing about this problem; whether they use the water or whether we use the water; but meanwhile the water is going waste. This is the unfortunate state of affairs. This has to be looked into very seriously. Otherwise, it is a very big problem, particularly the ditrict does not have even one project. This year, small projects like Koyalsagar and Sarlasagar are there. Even they are also being dried up.

The Chief Minister of Andhra Pradesh, Mr. Vijaya Bhaskara Reddy, recently visited my district also. I took him to all the villages of my constituency. I had explained the situation to him. My district is also famous for labour. You might have heard the name of Palamur Labour. Palamur is another name of Mahabub Nagar. Wherever you go in Maharashtra and Karnataka you will find Palamur labour. Why? We have no work; we are not in a position to show work. This is the pitiable condition of my constituency. Unless special attention is paid by the Government, it is highly impossible to protect my people who are leaving not only my constituency but also my district and even the State. You

can try to understand the miserable conditions of the people.

We are allocating lakhs of rupees for providing drinking water to the people; whether it is a State Government or the Central Government; but the Engineering staff while boring wells is playing a lot of mischief. They go upto only 50 ft. but they record 100 ft. The next day we do not get water. This should be properly checked. Otherwise, there is no use of spending lakhs of rupees. This is a very serious problem which is going on there.

When we are facing a serious drought and the people are suffering, the government machinery should also feel about it and they must come to the rescue of the people. Unless it is properly understood, it is very difficult to solve it. In backward areas, particularly the hill areas and tribal areas, it is highly impossible for the Government asks for contribution. We are required to pay contribution for water supply. Whenever we represent, th Government asks for contribution. We are not in a position to pay for our own food. That being the case, where is the question of paying compensation? Some direction will have to be given to the State Government to start definite schemes in the backward areas, or at least in the scheduled areas and the tribal areas to augment the water supply instead of depending on contributions from the people.

As far as resources are concerned, I would like to mention specifically about my district. I come from a backward district. There is no project for us. But some industries can be started, where we can give some work to the labourers, we can engage them. Such things shall have to be taken up. Labour-oriented industires will have to be taken up, particularly in those areas. Government is naturally aware of these problems. The drought situation in Andhra Pradesh this year is the same as it was last year and before last year.

I want to make one submission. Loans will have to be given to small farmers, marginal farmers, and weaker sections. Simply postponing of the collection of loans is not the solution for this problem. I suggest that the Government may take a decision to write off these loans. This is a continuous thing happening in backward areas facing drought. I would request the Minister of Agriculture to kindly look into this and direct and State Government to write off the loans which are given to the weaker sections, small farmers and backward class people. Specific and severe punishment should be given to the officers responsible for not implementing the drought-relief programmes in these districts. The officers should also be made responsible for non-implementation of the programmes. As far as the Food Corporation of India is concerned, as Mr. Narsimha Reddy mentioned. providing sufficient stocks is not the only solution to the problem. Some subsidy should also be given for the purchase of rice and other foodgrains. I am sorry for taking more time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

21.37 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, October 15, 1982/Asvina 23, 1904 (Saka).

GMGIPND—M—2475 L. S. 17-12-82—890